

हिन्दी प्रचार
का
इतिहास

४१०.०८
जय। हि

हिन्दी-प्रचार का इतिहास

लेखक

जय शङ्कर त्रिपाठी
साहित्याचार्य, एम्. ए.

भारती परिषद, प्रयाग

प्रकाशक
भारती परिषद्, प्रयाग

●
प्रथम संस्करण

१९६७

●
मुद्रक

मूल्य—तीन रुपये

निवेदन

जन-भाषा हिन्दी के विकास की कहानी तब शुरू होती है जब इस देश की राजनीतिक अवचेतना का आरम्भ होता है। इसीलिए हिन्दी की व्यापकता और उसके प्रचार-प्रसार को मूलभूमि धार्मिक क्रान्ति के सन्देश-वाहक सन्तों और लोकभाषा के कवियों के इतिहास से आशुत है, राजनीति से उसे प्रेरणा नहीं मिली है। इतिहास का यह सिलसिला एक हजार वर्ष पुराना है। हिन्दी भाषा के सभी रूपों—राजस्थानी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का प्रसार एक साथ ही उस इतिहास में दिखाई पड़ता है, परन्तु अवधी और ब्रज को राम और कृष्ण की जन्म-भूमि की बोली होने के कारण प्राथमिकता मिल गई। खड़ी बोली, जो आज हिन्दी का मानक रूप है, धार्मिक क्रान्ति के सन्तों द्वारा ही अपनायी गई। जन-सम्पर्क के लिए मुसलमानों ने जब इसे अपनाया तब इसको 'हिन्दी' नाम उर्दू और दक्खिनी का रूप मिला। सन्तों ने इसे सामान्य रूप में 'भावा' ही कहा है। साहित्यिक रूप में इसको व्यवहृत करते हुए सैयद इंशा उल्ला खाँ को इसके 'हिन्दवीपन' का लोभ रहा है। जब अंग्रेज आये और उन्हें उत्तर भारत में जनसम्पर्क के निमित्त भाषा का माध्यम खोजना पड़ा तब 'हिन्दुस्तानी' कह कर उन्होंने इस खड़ी बोली को अपनाया। अंग्रेजों के ज्ञान ने देश में एकमुखाता और ज्ञान्ति का जो वातावरण पैदा किया उससे देश में धार्मिक जागरणों के साथ अपनी भाषा के स्वाभिमान का भी जागरण हुआ और उन्नीसवीं बनी ई० में अंग्रेज शासकों से यहाँ के जन-प्रतिनिधियों ने प्रशासन में अपनी जनभाषा हिन्दी और नागरी लिपि के व्यवहार की माँग की। उस समय उर्दू और फारसी लिपि का व्यवहार शासन में होता था। यह माँग कुछ अंग्रेजों में स्वीकार होती रही और अस्वीकार भी होती रही। इसके साथ ही जब देश की आजादी के लिए प्रबल आन्दोलन खड़ा हुआ तब ईस्वी बीसवीं शती में राष्ट्रनेताओं ने अविध्य में आजादी मिलने पर समूचे देश की राष्ट्रभाषा का हल इस हिन्दी में देखा। सन् १९४७ में हमें आजादी प्राप्त हो गई। आजादी मिलने के साथ जैसी

नभावना थी उसका उलटा हुआ. राजभाषा अंग्रेजी है, हिन्दी अब भी जनभाषा है और देश में जनतन्त्र की सरकार है। हम प्रकार इस जनभाषा हिन्दी की कहानी जनता और धामन के अलग-अलग अस्तित्वों के संघर्ष की लम्बी गाथा है।

उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध से धार्मिक और साहित्यिक अनेक संस्थाओं ने हिन्दी को समूचे देश में व्यापक बनाते तथा शासन में प्रतिष्ठित करने के लिए ऐतिहासिक महत्त्व के प्रयास एवं संघर्ष किये हैं। हिन्दी-प्रचार का इतिहास जन-चेतनाओं, ऐतिहासिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक स्वार्थों का उलझा हुआ संघर्ष है, जो चल रहा है, अन्तिमंत्थम् उसका निपटारा नहीं हो रहा है। उसका लम्बा विस्तार है। प्रस्तुत पुस्तक में उस विस्तार की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न हुआ है।

आजादी मिलने के बाद हिन्दी के प्रचार-कार्य में भी स्वाधियों ने डेरा डाल दिया और यह कहने में सकोच नहीं है कि १९४७ के पहले हिन्दी की जो सेवा त्यागी जननेताओं द्वारा हुई थी, उस पर ही आज के तथाकथित हिन्दी-सेवक कुठाराघात कर रहे हैं। हिन्दी-सेवा और उसके नाहित्य-निर्माण के लिए आज भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अनुदान, पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन भी दे रही हैं, भारत की बातें छोड़िए, 'मोक्षित भूमि' भी हिन्दी सेसकी को पुरस्कार देती है, विदेशों में हिन्दी का अध्ययन-अनुशीलन होता है, परन्तु भारत में सामान्यतः हिन्दी के लिए, हिन्दी-विद्वानों के लिए सम्मान नहीं है। उपेक्षा और संवर्षों से भरा हुआ जनभाषा हिन्दी का यह इतिहास हमें नीबू प्रेरणा देता है कि हम अपने इस महान् राष्ट्र को वाणी को मुखरित करने के लिए उसकी राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करें। इस प्रतिष्ठा के कार्य में हमको त्याग और साँजन्व से आगे आना है।

भारतंत्र दिवस

शकाब्द १८८८

प्रयाग।

—जय गङ्गूर त्रिपाठी

विषय-क्रम

१. हिन्दी भाषा का मानक रूप और उसके प्रचार-प्रसार की लम्बी कहानी १-१७
हिन्दी की व्यापकता, मुसलमान-जामक-उद्दे और दक्खिनी हिन्दी, नराठा जामको और अंग्रेजों का हिन्दी के प्रति आकर्षण, हिन्दी-प्रचार के आरम्भिक प्रयत्न, उत्तरी भारत में हिन्दी-प्रचार का जागरण ।
२. राष्ट्रभाषा की खोज और हिन्दी १८-२६
राष्ट्रभाषा का आन्दोलन और दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार, १९५० तक के स्वर्ण का निष्कर्ष ।
३. 'हिन्दी' नाम का इतिहास २७-३०
४. संस्थानें ३१-८७
देवनागरी प्रचारिणी सभा मेरठ, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् जगलोर, हिन्दी परिषद् नई दिल्ली, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ बम्बई, गुजरात विद्यापीठ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, हिन्दी विद्यापीठ देवघर ।

५. रचनात्मक संस्थान

८८-६२

हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना, हिन्दी-यमिति लखनऊ, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, भारतीय हिन्दी परिषद् ।

६. राष्ट्रभाषा हिन्दी

८३-८६

बकिमचन्द्र चटर्जी, महात्मा गांधी, नेता जी सुभाष चन्द्रबोस, कवीन्द्र रवीन्द्र, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री श्रीनिवास शास्त्री—आदि ।

७. विदेशों में हिन्दी

१००-१०३

परिशिष्ट

१०४-११२

नागरी प्रचारिणी सभा काशी के सभापति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास के दीक्षान्त-भाषण-कर्ता, राष्ट्र भाषा प्रचार सम्मेलन वर्धा के अध्यक्ष, मंगलाप्रसाद पारितोषिक-प्राप्त हिन्दी - लेखक, महात्मा गाँधी पुरस्कार प्राप्त अहिन्दीभाषी हिन्दी-लेखक ।

हिन्दी-प्रचार का इतिहास



हिन्दी भाषा का मानक रूप और उसके प्रचार-प्रसार की लम्बी कहानी

हिन्दी की व्यापकता

हिन्दी भारत के मध्य भाग की मातृभाषा है। इस मध्य भाग में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सीमाएँ आती हैं। राजस्थान और पंजाब के पूर्वी भाग भी इसमें सम्मिलित हैं। एक हजार वर्ष से इस भूभाग में जो भी कवि या सन्त हुए हैं उन्होंने सर्वथा अपनी रचनाओं और उपदेशों के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग किया है, यह बात अवश्य है कि प्रदेश-भेद में प्रारम्भिक शताब्दियों में हिन्दी के स्वरूप में भी भेद रहा है। इस स्वरूप-भेद के रहते हुए भी आज हिन्दी के जिस खड़ीबोली रूप को सर्वमान्यता प्राप्त हुई है, उस रूप के प्रयोग भी हमें हिन्दी के उद्भव काल से ही सन्तों और कवियों की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। उन सन्तों में से कोई बिहार-जंगल के है, कोई महाराष्ट्र-राजस्थान के है, कोई पंजाब के है। सन्तों की वारिसी का सम्पर्क प्रायः लोकवाग्गुी से होता है अतः सन्तों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी का खड़ी-बोली-रूप उसकी लोक-व्यापकता का सूचक है।

इन सन्तों में आठवीं शती के सरहृषा आदि (चौरासी सिद्धों) से लेकर कबीर—मालहरी जर्ता की अवधि तक के लोक-धर्म की क्रान्ति जगानेवाले अनेक सन्तों के नाम आते हैं, जिनमें हिन्दीतर प्रदेशों के भी ख्याति-प्राप्त सन्त हैं, इन सन्तों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें आज की खड़ीबोली के प्रयोग हैं और उन प्रयोगों को देखकर खड़ी बोली के लोक-व्यापक रूप का

पता चलता है। नामदेव महाराष्ट्र के सन्त हैं, ये तेरहवीं शती में विद्यमान थे। इनका एक छन्द देखिए, जो खड़ीबोली के रूपों में ओतप्रोत है—

माइ न होनी बाप न होते, कर्म न होना कथा,
हम नहीं होने, तुम नहीं होने, कौन कहाँ से आया ?
चन्द्र न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया,
शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँ से आया।

(नामदेव)

महाराष्ट्र-सन्त की खड़ीबोली हिन्दी की यह बाग़ी हिन्दी को लोक-व्यापकता और लोक-प्रियता दोनों सूचित करती है।

आचार्य पं० सीताराम चतुर्वेदों के अनुसार खड़ीबोली का मूल नाम नागरी है—“नागरी भाषा का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है। जिस क्षेत्र की यह आज से सहस्रो वर्ष पूर्व बोली रही है, उस क्षेत्र (मेरठ और मुजफ्फर नगर) में प्रायः ठीक उसी रूप से आज भी बोली जाती है। यद्यपि अभीर खुसरो और नामदेव की ही कुछ रचनाएँ नागरी की सर्वप्रथम रचना के रूप में उपलब्ध हैं तथापि उनकी भाषा का जो पुष्ट रूप प्राप्त है, उसे देखते हुए यह असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि इस भाषा में पहले से रचना होती रही, जो आज मिल नहीं रही है। विक्रम की आठवीं शताब्दी में रचे हुए आचार्य कुमुदेन्द्रमुनि के ‘भूवल्लय’ ग्रन्थ में जहाँ उन भाषाओं के नाम गिनाये गये हैं, जिनमें उस ग्रन्थ का पढ़ा जाना सम्भव है, वहाँ नागरी का भी उल्लेख किया गया है। इससे ही यह सिद्ध हो जाता है कि आज से १२०० वर्ष पूर्व भी आज की नागरी (जिसे कुछ लोग खड़ीबोली इसलिए कहते हैं कि ब्रजभाषा की अपेक्षा उसमें कठोरता, रूखापन, अक्खड़पन अधिक है) की प्रसिद्धि मुख्य भाषा के रूप में ही थी।” (रा० प्र० सं० वर्षा—रजत-जयन्ती ग्रन्थ, पृष्ठ ३७७-३७८)

चतुर्वेदों जी ने नागरी (खड़ीबोली) के विस्तृत क्षेत्र का निर्देश भी किया है—“जिस प्रकार अवधी, राजस्थानी, ब्रज और मैथिली के विशेष क्षेत्र हैं उसी

प्रकार नागरी का भी । पंजाब और राजस्थान के डोंडे से लेकर मध्यप्रदेश के मध्य भाग में होते हुई उड़ीसा को छूती हुई बिहार के पूर्वी छोर तक अपना हाथ फैला कर नेपाल की तरई के नीचे में आकर भारत की राजधानी के पश्चिम पड़नेवाले सम्पूर्ण भूभाग को अपने अंक में नागरी समेट लेती है ।” (वही पृष्ठ ३७६) ।

सिद्धों के गुरु अर्जुनदेव ने ‘गुरु ग्रन्थ साहब’ का सकलन किया था, जिसमें गुरु नानक के अतिरिक्त ग्रन्थ प्रदेशों के मन्त्रों की वाणियाँ भी हैं। इन वाणियों में भी खड़ीबोली के रूपों का पुट है ।

बारहवीं शती में गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्र ने ‘सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन’ नामक ग्रन्थ बनाया, उसमें संस्कृत के साथ प्राकृत और अपभ्रंश के छन्दों के उदाहरण भी दिये गये हैं । ये उदाहरण अवश्य ही हेमचन्द्र के पूर्व के होंगे । इन उदाहरणों में यत्र-तत्र खड़ीबोली के रूप का दर्शन मिलता है—

भल्ला हुआ जु मारिया बहिरिण महारा कन्तु ।
लज्जेजं तु बरसिअहु जइ भग्या घर ण्तु ॥
पिय मगमि कट तिहूँ ? पियहो परोक्खहो केव ।
मइं विचिवि विज्जासिया .निह न एँव न तेंव ॥

इसी प्रकार चौदहवीं शती के प्रारम्भ में शाङ्गधर ने ‘शाङ्गधर-पद्धति’ नाम का सुभाषित-संग्रह सकलित किया । उसमें भाषा-चित्रकाव्य के उदाहरणों में देश भाषा के प्रयोग भी हुए हैं, उस प्रयोग में खड़ीबोली का रूप स्पष्ट है—

भूठे गवं भरा मवालि सहसा रे कन्त मेरे कहं ।
कठे गग निवेश जाह शरणं श्रीमल्लदेवं विभुम् ॥

अपभ्रंश से खड़ीबोली के रूप का जो विकास हुआ उसका परिचय हमें सिद्धों की वाणियों का अनुशीलन करने से हो जाता है । सरहपा (आठवीं शती) की रचनाओं में खड़ीबोली का रूप-प्रक्रिया का प्रत्यक्ष दर्शन होता है—

खायन्त पिथन्ते सुहर्हि रमन्ते,
गिण्त पुष्पु चक्काहि भरन्ते ।

बैरहवी शती के अन्त में अमीर खुसरो ने ठेठ ग्राम्य भाषा में जो दिल्ली के आसपास प्रदेश की बोली थी, पहेलियाँ लिखी हैं, साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा को छोड़ कर ठेठ ग्रामवासी में लिखने का कारण दिल्ली में मुसलमानी सल्तनत के आरम्भ के साथ आसक और जनता के आरम्भिक सम्बन्धों का प्रभाव था। उनकी पहेलियाँ सर्वांग में आज की हिन्दी के मूल (ठेठ) रूप में हैं—

एक थाल मोती से भरा ।
सबके सिर पर ओघा धरा ।
चारों ओर वह थाली फिरे ।
मोती उससे एक न गिरे ॥ (आकाश)

एक नार ने अचरज किया ।
साँप मार पिंजरे में दिया ।
जों जो साँप ताल को खाए ।
सूखे ताल साँप मर जाए ॥ (दिया-बत्ती)

सिद्ध, नाथपंथी एवं अन्य सन्तों की वाणियों का अध्ययन करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज की हिन्दी का मूल खड़ीबोली (नागरी) रूप पंजाब में महाराष्ट्र तक और सिन्ध से बिहार-बंगाल तक किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव फैला रहा था अथवा भाषाओं या बोलियों में यत्र-तत्र उसकी सत्ता के दर्शन हो जाते थे। दक्क और अवधी भाषाओं के क्षेत्र के बाहर खड़ीबोली का प्रयोग अन्य भाषा के साथ और स्वतन्त्र रूप में हो रहा था। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवा जी के प्राश्नित भूषण (१७वीं शती) की कविता में खड़ीबोली के प्रयोग हैं। समर्थ रामदास (१७वीं शती) की रचनाएँ खड़ीबोली में हैं। गुजरात के मन्त दादू (१७वीं शती) और कवि दयाराम (१८वीं शती) की खड़ीबोली में रचनाएँ मिलती हैं। अठारहवीं शती में प्रायः सिन्ध गुजरात

पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र मर्वत्र खड़ीबोली में सन्तो की रचनाएँ लिखी जाती रही। इसका मूल कारण, जैसा कि पीछे उल्लेख किया गया है, पं० सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार खड़ीबोली का विस्तृत क्षेत्र हो, अथवा अन्य जो कारण रहे हो लेकिन यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि खड़ीबोली के स्वरूप में अन्य भाषाओं की आत्मसात् करने या उन भाषाओं में आत्मसात् होने की मिलनसारिता थी।

मुसलमान शासक—उर्दू और दक्खिनी हिन्दी हिन्दी कवियों द्वारा खड़ीबोली की उपेक्षा का कारण

जब दिल्ली में मुसलमानों की सल्तनत स्थापित हुई तब दिल्ली के आस-पास की इस खड़ीबोली को उसके राजपुरुषों और फौजी छावनियों ने अपना प्रश्रय देकर उसके प्रसार में विशेष सहयोग दिया। यद्यपि उनके प्रश्रय से उसके स्वरूप में कुछ अन्तर भी पैदा हुआ। और इस अन्तर के साथ सैनिकों द्वारा व्यवहृत होने के कारण फौजी बाजार के नाम पर इसका उर्दू नाम हुआ। फारसी का थोड़ा-बहुत प्रभाव भी उस पर पड़ा, लेकिन उतना ही जितना आदमभात हो सका। यह दक्षिण में पहुँची। आज इसे दक्खिनी हिन्दी कहते हैं। दक्खिनी हिन्दी में गद्य-पद्य का समृद्ध साहित्य है। आरम्भ में दक्खिनी हिन्दी में जो साहित्य लिखा गया वह आज की हिन्दी के बहुत निकट है, उत्तरोत्तर उसमें फारसी की छाप अधिक होती गई है। गोलकुंडा के शासक अली आदिल शाह (सत्रहवीं शती उत्तरार्ध) की दक्खिनी हिन्दी की रचना आज की हिन्दी की ही परम्परा में है, उनकी कविता का यह नमूना देखिए—

जोवन फड़क्कते है पिव मस्त हो मिलेंगे,
आलिंग बदल रहँ अब बँद खोल अंगिया का।

इस प्रकार एक प्रश्न हमारे सामने आता है—खड़ीबोली हिन्दी के रूप के इतना व्यापक होते हुए तथा आठवीं शती से ही उसके प्रयोग अभिलक्षित

होने पर भी साहित्यिक भाषा के रूप में उसका उत्थान उन्नीसवीं-बीसवीं शती में क्यों हुआ ? इसके दो समाधान हो सकते हैं, एक यह कि खड़ीबोली के प्रयोग में भाषा की वह मधुरता नहीं आती थी जो शृंगार तथा भक्ति-भाव के काव्य-गुप्तो के लिए आवश्यक थी, यह लोच और मृदुता ब्रज, अवधी और मैथिली भाषाओं में प्रकृत रूप से ही थी । दूसरा समाधान यह है कि ब्रज और अवधी भाषाएँ, जिनमें हिन्दी के मध्यकाल में धारासार प्रचुर साहित्य लिखा गया, भगवान् कृष्ण और राम की जन्मभूमि में बोली जाती है । राम और कृष्ण की भक्ति का जो प्रवाह ११वीं शती में दक्षिण में उत्तर की ओर चला, उसके संगम का केन्द्र मयोध्या और ब्रज की ही भूमि थी, अतः वहाँ की भाषा में ही राम और कृष्ण की भक्ति के पद तथा प्रबन्ध लिखे गए । तुलसीदास और सूरदास के पूर्व अवधी और ब्रज की भाषाओं में काव्य-रचनाएँ न हुई होगी ऐसी बात नहीं है, भक्ति के जिस प्रवाह में उस समय की जनता डूब रही थी, उससे तटस्थ होकर स्थिर होना उस समय के भाषा-कवियों के वश की बात नहीं थी । परन्तु वे समर्थ कवि नहीं थे, सूरदास और तुलसीदास जैसे तेजस्वी कवियों के उदय से वे विस्मृति के ग्रन्थकार में त्रिलीन हो गये । सूरदास के पूर्ववर्ती ब्रजभाषा के ऐसे कवियों और रचनाओं का इतिहास अब खोज में सामने आ रहा है । दूसरी ओर राम-कृष्ण की भक्ति से मुक्त होने के कारण कबीर की जागी में अवधी-ब्रज भाषाओं का प्रभाव नहीं रहा, उस समय देश के अन्य भागों में अपनाया जानेवाला खड़ी-बोली का रूप ही कबीर की रचनाओं में पाया जाता है—

आऊँगा न जाऊँगा, मरूँगा न जीऊँगा ।

गुरु के सबद रम रम रहूँगा ॥

रामकृष्ण के भक्ति-प्रवाह ने जो दूसरा काम किया, वह हिन्दी के लिए सजीवनी बन गया, मले ही वह हिन्दी ब्रज या अवधी रही हो । राम-कृष्ण की भक्ति के साथ उनकी जन्म भूमि की भाषा अवधी और ब्रज का भी प्रचार आसाम-बंगाल तथा अहिन्दी भाषी दक्षिणी प्रदेशों और पच्छिमी प्रदेशों

मे हो गया। राम और कृष्ण नामों की संजीवनी का यह ऋण हिन्दी को नहीं भूलना चाहिए। तेरहवीं शती के उत्तरार्ध में आसाम (नौगाँव) के कवि माधवदेव ने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति का गान किया है। बंगाल के भरत-चन्द्र ने और गुजरात के प्रेमानन्द, श्यामलभट्ट, दयाराम एवं भालण की कविताएँ भी हिन्दी में ही हैं। हिन्दी के श्रेष्ठ कवि विद्यापति तथा मीराबाई को भी लोग मूलतः बँगला एवं गुजराती का कवि मानते हैं, जो सम्भवतः अपनी कृष्ण-भक्ति के कारण हिन्दी में लिखने को प्रेरित हुए। अतः ब्रज और अवधी को जो सरक्षण कृष्ण और राम—नामों की छत्रछाया में मिला, जो छत्रछाया उन नामों के अनुगमन में लोक-हृदय का निस्सीम विस्तार थी, ऐसा सरक्षण खड़ीबोली हिन्दी के रूप को संभव न हुआ। मुसलमानी सल्तनत के साथ उसे जो आश्रय मिला, वह उसकी प्रकृति के विपरीत था, और उसने धीरे-धीरे न केवल नाम में ही अपने को रेखा और उर्दू कहा, बल्कि फारसी के निरन्तर प्रभाव में उसका स्वरूप हिन्दी में दूर होता गया, जब कि उसका मूल ठेठ खड़ीबोली ही है।

इतना होने पर भी हम इससे अस्वीकार नहीं कर सकते कि आज की परिनिष्ठित (मानक) हिन्दी के मूल—खड़ीबोली को प्रथम प्रश्न और विकास देनेवाले मुसलमान शासक हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है। खड़ीबोली गद्य के विकास का इतिहास भी सैयद इंशाअल्ला खाँ और उनकी कृति 'उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी' (सन् १८०३) के उल्लेख के बिना अधूरा ही कहा जायगा। और इन दोनों सीमाओं के बीच में उर्दू भाषा के नाम पर दक्खिनी हिन्दी में जो प्रचुर गद्य-पद्य लिखा गया, वह सब खड़ीबोली हिन्दी की वह समृद्धि है, जो उसे मुसलमान शासकों के कारण मिली है और इसी कारण हिन्दी के ऐतिहासिक जागरण के पूर्व उस साहित्य-समृद्धि को हिन्दी-साहित्य से अलग माना जाता रहा। अली आदिल शाह की रचना ऊपर उद्धृत की गयी है, ऐसे कई-एक कवि दक्खिनी हिन्दी के हैं जो अठारहवीं शती के पूर्व हुए हैं, उनकी रचनाएँ हिन्दी खड़ीबोली की परम्परा से भिन्न नहीं हैं। ऐसे ही एक कवि बर्ल

(औरंगाबाद, जन्म सन् १६६८) की ये पंक्तियाँ देखिए, जिन पर नाम मात्र को फारसीपन की छाया है—

बेवफाई न कर खुदा मूँ डर ।
जग-हँसाई न कर खुदा मूँ डर ।
आरसी देखकर न हो मगरूर
खुदनुमाई न कर खुदा मूँ डर ॥

... ..

फिर मेरी खबर लेने को सइयाद न आया ।

शायद कि उसे हाल मेरा याद न आया ॥

मुसलमान शासकों के उस संरक्षण को हिन्दी भुला नहीं सकती ।

आश्चर्य है कि राम और कृष्ण की भक्त हिन्दी-प्रेमी जनता के स्वर को मुखरित करतेवाले हिन्दी-कवियों ने ब्रज और अवधी को छोड़कर हिन्दी के समर्थ स्वरूप खड़ीबोली में रचना करने की प्रवृत्ति न दिखाई, न तो खड़ी-बोली में अन्तर्हित उस शक्ति की पहचान की, जो गद्य का प्रकृत स्वरूप, शैली और संजीवन है । कदाचित् इसका कारण भी यह रहा हो कि खड़ीबोली का प्रयोग शाही दरबार में होता था, वह फारसी के शब्दों से मिश्रित होकर रेख्ता, उर्दू और शाहजहानी उर्दू बन गई थी, अतः राम-कृष्ण का गुणगान करनेवाली कवि-परम्परा ने ऐसी भाषा का तिरस्कार किया हो ।

१८वीं और पूर्वार्ध १९वीं शती

मराठा शासकों और अंग्रेजों का हिन्दी के प्रति आकर्षण

हिन्दी के उक्त स्वरूप को मुसलमान शासकों के बाद वही प्रश्रय मुगल शासकों ने नहीं दिया । अकबर ने राजकाज में फारसी लिपि के प्रयोग की आज्ञा दी और यह परम्परा मुगल शासन के अन्त तक चलती रही । अठारहवीं शती में मुगल के पतन के साथ जब मराठा का उदय हुआ

तो पेशवाओं ने संस्कृत के साथ राजकीय पत्र-व्यवहार में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को भी अपनाया। उन्नीसवीं शती के आरम्भ में हिन्दी को आंग्लिक प्रथम भारत को विजय करनेवाली अंग्रेज जाति ने भी दिया, शासन और जनता के व्यवहार में आने योग्य हिन्दी के खड़ीबोली स्वरूप की पहचान उन्होंने की। यद्यपि बाद में उन्होंने ही किन्हीं कूटनीतिक कारणों से उर्दू और हिन्दी का भगडा भी खड़ा किया। और तभी सम्पूर्ण भारत के एक अंग्रेजी शासन में आबद्ध होने के साथ परम्परागत फारसी लिपि और भाषा के विरुद्ध अपनी हिन्दी भाषा और नागरी लिपि की शासन में प्रतिष्ठा की भावना जनता में जागी। और बीसवीं शती में देश के स्वाधीनता-सर्वश्रेष्ठ के साथ हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन भी खड़ा हुआ।

सन् १८०३ में फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के हिन्दी-उर्दू अध्यापक जान गिलक्राइस्ट ने उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं में अलग-अलग गद्य की पुस्तकें लिखवाने का प्रबन्ध किया, उस कालेज के आश्रय में ही लल्लू लाल जी ने 'प्रेम सागर' और सद्दल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा। अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में शासन-कार्य में जनता के व्यवहार की सुविधा की देखते हुए हिन्दी के पठन-पाठन की आवश्यकता समझी और शायद इससे भी अधिक आवश्यकता उनको अपने ईसाई धर्म के प्रचार में हिन्दी को माध्यम बनाने की थी। बंगाल के ईसाई मिशनरी के पादरी रेवरेण्ड एम्. टी. ऐडम ने सब से पहले हिन्दी का एक व्याकरण लिखा और वह सन् १८२७ में कलकत्ते में छप कर प्रकाशित हुआ। यह अब तक के उपलब्ध हिन्दी के व्याकरणों में सब से प्राचीन है। ईसाई धर्म के प्रचार-हेतु हिन्दी की इसी अध्ययन-परम्परा में ईसाई धर्म-प्रचारक विद्वान् रेवरेण्ड पादरी एस्. एच्. केल्लाग ने सन् १८७५ में हिन्दी भाषा और व्याकरण का एक विस्तृत अध्ययन अंग्रेजी भाषा में ईसाई धर्म के प्रचारक अंग्रेजों के लिए प्रस्तुत किया। आगरा, मिरजापुर, मुँगेर एवं बिहार का दक्षिणी भाग उस समय ईसाई-धर्म-प्रचारकों के केन्द्र थे

१६वीं पूर्वार्ध शती

हिन्दी-प्रचार के आरंभिक प्रयत्न

दूसरी ओर हिन्दी के उक्त स्वरूप को पहचान कर हिन्दी में राजकाज और आपसी व्यवहार के लिए उत्तरी भारत की जनता की ओर जब खुली और उसने हिन्दी को अपनाया, शासन में सर्वत्र हिन्दी और नागरी लिपि के प्रयोग की अपनी तमन्ना व्यक्त की, तब अंग्रेजों ने ही फारसी की शैली उर्दू के समर्थकों को खड़ा कर नागरी लिपि और हिन्दी के प्रयोग में अड़झा पैदा कर दिया। उस अवधि में कलकत्ता, बनारस और आगरा से हिन्दी के अखबार भी हिन्दी-प्रेमियों ने निकाले। पंडित जुगुलकिशोर का 'उदत्त मार्टीड' (सन् १८२६) और राजा राममोहनराय का 'बग दून' (सन् १८२६) अखबार कलकत्ता से प्रकाशित हुए। सन् १८४५ में बनारस के राजा शिवप्रसाद ने 'बनारस अखबार' निकाला और सन् १८५२ में आगरा के मुन्शी सदासुख लाल ने 'बुद्धि प्रकाश' समाचार-पत्र निकालना शुरू किया।

निस्सन्देह हिन्दी में अंग्रेजों को खतरा मालूम पड़ा था। और उनको अपनी ईमानदार स्थिति व्यक्त करने के लिए बहुत प्रबल आधार था, जब भारत के शासन पर उनका आधिपत्य हुआ तब सरकारी दफ्तरो और अदालत की कार्यवाहियों में फारसी भाषा और लिपि का व्यवहार हुआ करता था, उन्हें उस परम्परा को यथावत् जारी रखने में कोई लांछन नहीं था, न नया प्रयास करना था। परन्तु जनता की कठिनाइयों की उपेक्षा भी सरकार नहीं करना चाहती थी, अतः कम्पनी सरकार ने सन् १८०३ में एक आज्ञा निकाली उस आज्ञा के अनुसार जिले के कलक्टरों से यह कहा गया कि फारसी और नागरी दोनों भाषाओं और लिपियों में अदालत के काम जनता की सुविधा को दृष्टि में रख कर किये जायें। सन् १८३६ में ऐसा ही एक दूसरा इश्वरनामा निकला, जिसके अनुसार सभी अदालती कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने के लिए हुक्म हुआ। परन्तु १८३७ में एक दूसरा हुक्म निकला जिसके अनुसार इस उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरो

की भाषा उर्दू कर दी गई। यह उर्दू के समर्थक मुसलमानों के प्रयत्न का परिणाम था। किन्तु सरकार का उद्देश्य इस उर्दू भाषा में जनभाषा की ओर ही था।

सरकारी दफ्तरों में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि की उपेक्षा के प्रति हिन्दी-प्रदेशों—उत्तर प्रदेश (तब पश्चिमोत्तर प्रदेश), बिहार और मध्यप्रदेश (अब मध्यप्रान्त) में एक साथ सघर्ष चलता रहा। सन् १८३७ के आदेश के बाद सभी जगह उर्दू भाषा और फारसी लिपि का प्रयोग होने लगा था और भाषा उर्दू की आड़ में फारसी होती गई। १८३७ के आदेश का जितनी तत्परता से पालन सरकारी दफ्तरों में हुआ, उतनी तत्परता से उन आदेशों का पालन नहीं होता था जो हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रयोग के लिए होते थे। वस्तुतः इसमें अंग्रेज सरकार का उतना दोष नहीं था, जितना नीचे के उन कार्यकर्त्ताओं और छांटे प्रफसरो का, जो परम्परा से मुगल शासन के समय में ही फारसी भाषा और लिपि में काम करने के व्यसनी हो गये थे और जिनमें अधिकांश मुसलमान तथा कायस्थ थे। इस बिगड़ी हुई परम्परा की निन्दा अंग्रेज विद्वानों ने स्वयं की है। लिपि के सम्बन्ध में तो नहीं किन्तु भाषा के सम्बन्ध में, सरकार समय-समय पर जैसे-जैसे अदालती भाषा की कठिनाइयों और गलतियों की शिकायतें उसको मिलती, आज्ञा-पत्र जारी करती रहो कि फारसी-पूरित उर्दू न लिखी जाकर ऐसी भाषा का प्रयोग दफ्तरों में किया जाय जिसको फारसी से अनभिज्ञ रहनेवाला भी एक कुलीन हिन्दुस्तानी बोलता हो, जो सर्वसाधारण की भाषा हो। ऐसे आज्ञापत्र २८ अगस्त सन् १८४० और ६ मई सन् १८५४ को जारी किये गये। परन्तु भूल प्रश्न लिपि का था, भाषा से अधिक दुरुहता लिपि की थी और फारसी लिपि रहने पर दफ्तरों के कार्यकर्त्ता कभी सर्व-साधारण की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसलिए आगे चल कर सरकार ने यह निश्चय करना आरम्भ किया कि दफ्तरों की लिपि रोमन कर दी जाये और भाषा सर्वसाधारण की हो। यह विचार बहुत बाद (सन् १८६६) में दृढ़ हुआ। इधर सरकार फिर भी इसी प्रयत्न में रही कि सर्वसाधारण की भाषा की उपेक्षा न की जाये। उसने सन् १८५६ में एक नया आदेश जारी

किया कि मालविभाग के कर्मचारियों को नागरी-अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उन्हें इस सम्बन्ध में परीक्षा पास करना भी अनिवार्य है, यदि ऐसा वे नहीं करते हैं तो नौकरी से हटा दिये जायेंगे। इस आदेश का प्रभाव पड़ा और हिन्दू-मुसलमान सभी अहलकारों ने नागरी पढ़ना आरम्भ कर दिया। इसका और भी अच्छा प्रभाव पड़ता लेकिन तभी १८५७ की क्रान्ति आ गई। क्रान्ति की समाप्ति के बाद सरकार अपनी शासन-सुव्यवस्था और शक्ति सुदृढ़ करने में लग गई। नागरी-विषयक आदेश की चर्चा भी नहीं रही।

उन्नीसवीं शती के आरम्भ में हिन्दी और नागरी लिपि की ओर जो ध्यान हिन्दी भाषी प्रदेशों में सरकार का रहा उसका अनुकूल परिणाम न निकला और मध्य की शती तक उर्दू समर्थकों के बराबर प्रयत्न और आन्दोलन के कारण फारसी-पूरित उर्दू भाषा और फारसी लिपि ही अदालतों तथा दफ्तरों में छाई रही। हिन्दी और नागरी लिपि के समर्थक भी थे, उनके अखबार भी निकल रहे थे, पर इस प्रश्न को आन्दोलन का रूप देनेवाले समर्थ व्यक्तियों के अभाव से नागरी लिपि और हिन्दी भाषा को यथोचित स्थान न मिला।

सन १८६० से १९००

उत्तरी भारत में हिन्दी-प्रचार का जागरण

सन् १८६० के बाद १९०० ई० तक का समय हिन्दी के महत्व पूर्ण संघर्षों का रहा है, इसका कारण यह था कि उन्नीसवीं शती के इन अन्तिम दशकों में हिन्दी के आन्दोलन को मुखरित करनेवाले राजा शिवप्रसाद, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महामना मालवीय जैसे समर्थ एवं प्रतिभावान् व्यक्ति उसको प्राप्त हुए। ये तीनों व्यक्ति काशी के थे। इनके साथ पंजाब के पं० अद्धाराम फुल्लौरी और मेरठ के पं० गौरीदत्त शर्मा का भी नाम लिया जाना चाहिए। ये नाम आन्दोलन की आवाज को ऊँचा उठानेवाले व्यक्तियों के हैं। जिन्होंने आन्दोलन का नाम नहीं लिया पर स्वयं अपने कार्यों एवं भाषणों से हिन्दी का सम्यक् प्रचार-प्रसार करते रहे, ऐसे व्यक्तियों में आर्यसभा के

संस्थापक स्वामी दयानन्द है जिनके द्वारा हिन्दी की अनुपम सेवा हुई है। ऊपर प्रमुख व्यक्तियों के ही नाम लिये गये हैं, उनके साथ प्रदेश-व्यापी उनके अनु-आश्रितों का भी बहुत बड़ा समूह था। सन् १८६० के बाद १९०० ई० तक के हिन्दी के संघर्ष के इतिहास की प्रमुख तिथियों का उल्लेख इस प्रकार है—

(१) सन् १८६३ में स्वामी दयानन्द समाज-सेवा के क्षेत्र में आये और सन् १८७५ में उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में भूम-भूमकर उन्होंने मदा हिन्दी में व्याख्यान दिये और अपने धर्म-प्रचार के ग्रन्थ हिन्दी में लिखे। उनके कारण देश के निवासियों की एक बड़ी संख्या हिन्दी की ओर आकृष्ट हुई। पंजाब में हिन्दी का प्रचार आर्य-समाज की ही देन है। आर्य-समाज के अनुयायी के लिए हिन्दी भाषा और नागरी लिपि का प्रयोग अनिवार्य कर्तव्य था। वे हिन्दी को आर्य-भाषा कहते थे। स्वामी जी का हिन्दी में लिखा 'सत्यार्थप्रकाश' आज भी अध्ययन किया जाता है।

(२) स्वामी दयानन्द के समकाल ही पंजाब में पं० श्रद्धाराम फुल्लौरी ने हिन्दी को माध्यम बना कर धार्मिक व्याख्यानों और उपदेशों की धूम मचा दी, उनकी वक्तृताएँ बड़ी प्रभावकारी और आकर्षक होती थीं। और इन कारणों से हिन्दी के प्रति भी जनता में आकर्षण बढ़ता था।

(३) काशी के राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' सन् १८५६ में शिक्षा विभाग में इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए थे। उनके ही समकाल बाबू नवीन चन्द्र राय पंजाब में शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। दोनों व्यक्ति सरकार के शिक्षा विभाग में रह कर भी हिन्दी के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इनमें बाबू नवीनचन्द्र राय ने सन् १८६३ से १८८० के बीच हिन्दी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें स्वयं लिखी और दूसरों से लिखवाई। जिसमें पठन-पाठन में हिन्दी-पुस्तकों का अभाव उसके प्रचार में बाधक न बने। राजा शिवप्रसाद ने भी यद्यपि इसी उद्देश्य से पुस्तकें लिखी तो भी उनकी हिन्दी का रूप बहुत कुछ बीसवीं शती में परिकल्पित गाँधी जी की हिन्दुस्तानी भाषा का था, लिपि नागरी थी भाषा प्रायः उर्दू। सम्भवतः नागरी लिपि के प्रचार के लिए उन्होंने यह रास्ता रखा होगा

(४) सन् १८६८ में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी और साहित्य सेवा के क्षेत्र में आये, इसी वर्ष 'विद्यासुन्दर' बंगला नाटक का उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ। सन् १८७३ में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' (हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका) पत्रिका प्रकाशित की। इस पत्रिका में हिन्दी के स्वरूप और शैली का अद्यतन रूप पहली बार सँवर कर सामने आया। हिन्दी की इस शैली के साथ हिन्दी-हितैषी साहित्यकारों की एक बहुत-बड़ी मंडली लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सन् १८८६ (अपनी मृत्यु-पर्यन्त) तक हिन्दी के संघर्ष और आन्दोलन के प्रमुख कर्णधार रहे।

(५) सन् १८७३ में बंगाल सरकार ने (तब बंगाल प्रान्त में बिहार भी सम्मिलित था) पटना, भागलपुर तथा छोटा नागपुर—डिवीजनो के सरकारी दफ्तरों और अदालतों में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रयोग का आदेश जारी किया। अफसरों से हिन्दी अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया। जनता के लिए यह छूट थी कि वह अपनी याचिकाएँ हिन्दी या उर्दू किसी भाषा में दे। पर इसका पालन नहीं हुआ। सन् १८७४ में एक दूसरे परिपत्र द्वारा पुनः उक्त आदेश को पालन करने के लिए आग्रह किया गया, परन्तु जनता के बहुत चाहते हुए भी आदेश कार्यान्वित न हुआ।

(६) सन् १८८२ में मेरठ के हिन्दी-प्रेमियों ने देवनागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। और सरकारी दफ्तरों में हिन्दी तथा नागरी लिपि के प्रवेश के लिए बराबर प्रचार और आन्दोलन करते रहे। इसके प्रमुख संचालक प० गौरीदत्त शर्मा थे।

(७) सन् १८८२ ई० में भारत सरकार ने एक शिक्षा-आयोग नियुक्त किया जिसने विभिन्न प्रान्तों में जाकर शिक्षा-विषयक कठिनाइयों, समाधानों और स्थिति का अध्ययन किया। पश्चिमोत्तर प्रदेश के (जिसमें तब सागर और अजमेर के जिले भी सम्मिलित थे), मान्य लोगों ने आयोग के समक्ष जो बयान और उसकी प्रश्नावली के उत्तर दिये हैं, उस बयान और उत्तर में उर्दू और हिन्दी का वर्तमान संघर्ष एक प्रमुख भाग है, इन गण्यमान्य व्यक्तियों में हिन्दी के समर्थक भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र भी थे।

(८) १० मार्च १८६३ में नागरी प्रचारिणी सभा काशी का स्थापना हुई। उस समय इस सभा के दो उद्देश्य थे—नागरी अक्षरों का प्रचार और हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि करना। इसके प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास थे। और संचालकों में प्रमुख थे—ठाकुर शिवकुमार सिंह, पं० रामनारायण मिश्र और श्री हयामसुन्दर दास।

(९) सन् १८६६ में सरकार ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के नागरी और फारसी लिपि के विवाद को समाप्त करने के लिए अदालतों और सरकारी दफ्तरों में फारसी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को प्रचलित करने का मत व्यक्त किया। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के पास इसका विरोध किया, 'नागरी कैरेक्टर' नाम से एक पुस्तिका भी छापी। सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए जो समिति नियुक्त की, उसने रोमन लिपि प्रचलित करने के लिए अपना मत व्यक्त किया परन्तु सरकार ने स्वयं २७ जुलाई १८६६ को रोमन लिपि के प्रचार का अपना विचार त्याग दिया।

(१०) १९वीं शती के अन्त में, पं० मदनमोहन मालवीय ने नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के आन्दोलन का नेतृत्व किया। अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनका एक प्रभावशाली प्रतिनिधि-मण्डल २ मार्च १८६८ को लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर एण्टोनी मेकडानेल में प्रयाग के राजभवन में मिला। इस प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश के १७ गण्यमान्य व्यक्ति थे। लगभग ६० हजार हस्ताक्षर १६ जिल्दों में बाँध कर प्रार्थनापत्र के साथ दिये गये थे। इन हस्ताक्षरों को इकट्ठा करने में लोगों ने दिन-रात एक कर दिया था। मालवीय जी ने उस अवसर पर अंग्रेजी में एक पुस्तिका तैयार की थी—कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज (पश्चिमोत्तर प्रदेश अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा)। इस पुस्तक में हिन्दी के पक्ष में सभी सम्भावित तथ्य इकट्ठा किये गये थे। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने तत्काल कोई निश्चय तो नहीं किया लेकिन उन्होंने हिन्दी के पक्ष में कही गई अनेक बातों का स्वीकार किया।

(११) १८ अप्रैल सन् १९०० में सरकार ने एक नई विज्ञप्ति निकाली,

जिसके अनुसार उसने अदालतों में नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रयोग को भी फारसी लिपि और उर्दू भाषा के साथ अनिवार्य किया। जनता को उसके इच्छानुसार इसके प्रयोग की छूट रखी गई। क्लर्कों और अफसरों को उनकी निष्पत्ति के लिए दोनों लिपियों का ज्ञान आवश्यक था। यह निबन्ध केवल दीवानी, माल तथा राजस्व न्यायालयों के लिए था। पर हिन्दी के लिए यह आंशिक सफलता थी।

(१२) सन् १९०० में अखिल भारतीय सनातनधर्म-सभा की स्थापना दिल्ली में हुई। सभी प्रदेशों में सनातनधर्म-सभा को छोटी-छोटी शाखाओं को मिला कर यह अखिलभारतीय रूप दिया गया। आर्य समाज के विरोध में सभा का यह रूप खड़ा हुआ था। सभा से ४०० संस्थाएँ सम्बद्ध थीं। इस सभा से हिन्दी का बड़ा हित हुआ। हिन्दी भाषा और नागरी लिपि ही इस सभा के विचारों के प्रचार-प्रसार का माध्यम थी। अहिन्दी प्रदेशों में भी हिन्दी में प्रकाशित सामग्री प्रसारित की जाती थी।

(१३) सन् १९०० में प्रयाग के इंडियन प्रेस ने पं० महावीर प्रसाद-द्विवेदी के सम्पादकत्व में 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया। वे सन् १९२० तक सरस्वती के सम्पादक रहे। द्विवेदी जी की विद्वत्ता और योग्यता ने इस पत्रिका के द्वारा हिन्दी में सुयोग्य लेखकों का निर्माण किया और हिन्दी को प्रशस्त शैली तथा रूप दिया, इससे भी हिन्दी के गौरव और प्रचार में अभिवृद्धि हुई।

सन् १९०० तक के सषर्ष के तीन महत्त्वपूर्ण परिणाम रहे—(क) हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को उर्दू भाषा तथा फारसी लिपि के साथ १८ अप्रैल १९०० की राजकीय विज्ञप्ति के अनुसार अदालतों में स्थान मिल गया। (ख) आर्य-समाज, सनातनधर्म तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं एवं पत्रिकाओं द्वारा अत्यन्त वेग से हिन्दी भाषा और लिपि का प्रचार हुआ। (ग) हिन्दी की महत्त्वपूर्ण संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना सन् १८९३ में हुई, जिसने आरम्भ से ही नागरी लिपि और हिन्दी के लिए अमूल्य सेवाएँ अर्पित की हैं।

हिन्दी-प्रचार के उक्त परिणामों के अतिरिक्त इन अन्तिम चार दशकों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हिन्दी-भाषा के मानक रूप की प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा का पहला उज्ज्वल स्वरूप राजा लक्ष्मण सिंह के 'शकुन्तला नाटक' के अनुवाद (सन् १८६३) में प्रकट हुआ। राजा जी के इस नाटक में जिस हिन्दी का प्रयोग हुआ है, वह खड़ीबोली हिन्दी के ठोठ रूप का ही साहित्यिक रूपान्तर है। हिन्दी-भाषा का यह पहला एकमात्र रूप है। 'शकुन्तला नाटक' में प्रयुक्त छोटे वाक्य, शब्दों-प्रयोगों के स्वाभाविक प्रयोग और शब्दों की मौलिकता ने हिन्दी-भाषा के स्वरूप का नया प्रभाव किया। 'शकुन्तला नाटक' की भाषा जनता की भाषा और साहित्य की भाषा—दोनों थी, जब कि अरबी-फारसी के उन शब्दों का भी, जो जनता में बहुत प्रचलित थे, इस नाटक में प्रयोग नहीं हुआ और संस्कृत के वही शब्द इसमें व्यवहृत हुए जो जनता के व्यवहार में आते थे। राजा जी की हिन्दी ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' (सन् १८७३) की 'नई चाल में ढली हिन्दी' का आदर्श थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके अन्य प्रमुख सहयोगी—राधाकृष्णदास, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखकों ने हिन्दी के उस रूप को और निम्बारा, तथा उसे स्थायित्व प्रदान किया। इन लेखकों की प्रतिभा और सत्प्रयत्न का ही फल था कि हिन्दी के इस रूप में, 'सरस्वती' पत्रिका (सन् १९००) के आरम्भ के साथ, प्राजन काव्य-रचना भी होने लगी। हिन्दी-भाषा के मानक रूप की इस प्रतिष्ठा से हिन्दी-प्रचार को बहुत बल मिला।

राष्ट्रभाषा की खोज और हिन्दी

सन् १९०० तक हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जो भी कार्य हुए, उनमें हिन्दी की सहज लोकप्रियता साकार हो उठी। आर्य-समाज और सनातनधर्म-सभा के उपदेश तथा व्याख्यान सम्पूर्ण देश में हिन्दी में पढ़े और समझे जाने थे। जैसे हिन्दी भाषा की बोध-प्रकृति इस देश की जनवासी की प्रकृति थी। इन पिछले तीस वर्षों में भारतेन्दु-मण्डल के उदय के पश्चात् हिन्दी-नाट्य का प्रचुर साहित्य लिखा गया, उसकी यह प्रचुरता भाषा की प्रौढ़ता थी। सरकारी अदालतों और दफ्तरो में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि की जो उपेक्षा हुई उससे हिन्दी के प्रेमियों को हिन्दी की उन्नति के लिए सदैव प्रेरणा मिलती रही। पराधीन देश में अपनी भाषा की उन्नति के लिए संघर्ष करने में वह आत्मवृत्ति मिल रही थी, जो स्वतन्त्रता के संघर्ष में मिलनी। भारतेन्दु जी ने लिखा है—

निज भाषा उन्नति अहं, सब उन्नति को मूल ।
दिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटन न हिण का शूल ॥

उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का क्षेत्र हिन्दी-भाषी प्रदेशों तक ही था। पश्चिमोत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में सरकार से हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को अपनाये जाने के लिए माँग की जा रही थी। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में इस माँग ने व्यापक रूप की कल्पना की गई

और हिन्दी के सामने महान् लक्ष्य स्थिर हुआ—अर्थात् हिन्दी इस महान् देश की राष्ट्रभाषा होने की क्षमता रखती है, उसको इस क्षमता को साकार होने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए।

हिन्दी का यह महान् लक्ष्य तब स्थिर हुआ जब राष्ट्र नेताओं के सामने, जां याजादी के लिए सघर्ष कर रहे थे, सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रभाषा का प्रश्न आया, उस समय हिन्दी पूरे देश में इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी थी कि नेताओं के सामने उनके प्रश्न का उत्तर 'हिन्दी' ही था। जो लोग देश की स्वतंत्रता के भविष्य का सुनहला स्वप्न देख रहे थे, वे स्वतंत्र देश की अपनी राष्ट्रभाषा की खोज में भी थे। सन् १९१० में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग को स्थापना राष्ट्रभाषा की खोज का ही उद्देश्य था। राष्ट्रीय कांग्रेस के माने कार्य-कलाप अंग्रेजों के साध्यम से होते थे, महात्मा गाँधी को सन् १९१५-१६ में इन कार्य-कलाप में भाषा की राष्ट्रीयता का अभाव अनुभव हुआ। महात्मा जालबोध और गाँधी ने इस अभाव को दूर करने का प्रयत्न किया और सम्पूर्ण देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरणा दी। उनके सामने राष्ट्रभाषा की खोज का प्रश्न याजादी के प्रश्न के समानान्तर ही था। देश की याजादी के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रभाषा रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, दोनों एक समान ही सघर्ष-रत थे। महात्मा गाँधी की प्रेरणा से सन् १९१८ में मद्रास में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग का प्रचार-कार्यालय खोला गया, आगे चल कर उसने दशिश नारत हिन्दी-प्रचार-सभा का रूप लिया। सन् १९३८ में राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति उर्ध्व की स्थापना हुई। इन संस्थाओं की स्थापना अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए ही की गई। राष्ट्रभाषा की खोज ने एक नया मोड़ तब लिया जब १९४२ में हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति उर्ध्व की स्थापना महात्मा गाँधी की ही प्रेरणा से हुई। और राष्ट्रभाषा हिन्दी ने स्वरूप के सम्बन्ध में विकल्प उपस्थित हुआ। इस प्रकार दोसवीं शती के पूर्वार्ध का हिन्दी के सघर्ष का इतिहास राष्ट्रभाषा की खोज और उसे पद पर हिन्दी की प्रतिष्ठा का इतिहास है।

सन् १९१०-१९५०, राष्ट्रभाषा का आन्दोलन और दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार

हिन्दी के संघर्ष की एक सन्तोषप्रद सफलता सन् १९५० में भारतीय संविधान में हिन्दी के राजभाषा स्वीकृत हो जाने से सामने आयी परन्तु संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस अर्धशती में हिन्दी के प्रति जनता के सम्मान को देखते हुए उसके विरोध से अब उर्दू के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' को और हिन्दी के राष्ट्रभाषा पद में बाधा डालने के लिए प्रादेशिक भाषाओं का वैमत्य खड़ा कर अंग्रेजी को, हिन्दी-विरोधियों ने खड़ा किया। हिन्दुस्तानी का समर्थन हिन्दू-मुसलिम एकता के लिए प्रयत्नशील महात्मा गाँधी ने भी किया। और अंग्रेजी का समर्थन प्रकट रूप में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद किया जाने लगा। इस अर्धशती में हिन्दी के प्रचार-कार्य के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम हुए हैं, और हिन्दी अब समस्त भारत में पढ़ी तथा लिखी जाने लगी है, विशेष महत्त्वपूर्ण काम दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार था। इतिहास की प्रमुख तिथियाँ ये हैं—

(१) सन् १९१० में महामना मालवीय जी की प्रेरणा से नागरी-प्रचारिणीमण्डल काशी ने हिन्दी और नागरी लिपि के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारतीय साहित्यकारों का एक सम्मेलन काशी में बुलाया। दूसरे वर्ष ही इस सम्मेलन ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन संस्था का रूप ले लिया। इसका कार्यालय प्रयाग में हुआ। सम्मेलन द्वारा संचालित हिन्दी-परीक्षाओं ने नागरी लिपि और हिन्दी के प्रचार में एक विचित्र आकर्षण पैदा किया। इसके वार्षिक अधिवेशनों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए ठोस कदम उठाये जाने के जो संकल्प किये जाते थे उन कारणों से सन् १९१० में लेकर १९५० तक का हिन्दी-प्रचार का इतिहास अनेकानेक में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ही इतिहास है।

(२) सन् १९१३ में स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुन्शीराम) सम्मेलन के उद्घापति हुए वे के नेता थे और अत्यन्त वे उनके

नेतृत्व में हिन्दी-प्रचार को बड़ा बल मिला। नैटाल स्थित महात्मा गाँधी के २१ अक्टूबर १९१४ के अपने नाम आये अंग्रेजी पत्र की, हिन्दी का पक्ष लेकर, स्वामी जी ने जो शिकायत की, उससे गाँधी जी को हिन्दी की महत्ता का बोध हुआ।

(३) आजादी के लिए संघर्ष करनेवाली राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था में महात्मा गाँधी का प्रवेश सन् १९१५ में हुआ, उन्होंने १९१६ में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना सन् १८८५ में हुई थी तब से लेकर अब तक उसकी समस्त कार्यवाही, अधिवेशन का वक्तृताएँ आदि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होती थी। लखनऊ-कांग्रेस में पहली बार गाँधी जी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया, सभासदों और पत्रकारों ने बड़ा विरोध किया लेकिन गाँधी जी हिन्दी में ही बोलते रहे। सन् १९१७ में सरकार द्वारा आमंत्रित युद्ध-सम्मेलन में भी उन्होंने अपना एक वाक्य का भाषण हिन्दी में किया। हिन्दी के प्रति गाँधी जी के इस प्रेम ने हिन्दी के प्रचार में बिजली-सी शक्ति प्रदान की, दूसरी ओर हिन्दी के इस प्रेम में गाँधी जी की लोक-प्रियता में भी वृद्धि हुई। गाँधी जी की प्रेरणा के फलस्वरूप सन् १९१८ से कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी का भी प्रयोग होने लगा। कांग्रेस द्वारा हिन्दी का अपनाया जाना उसके राष्ट्र-भाषा पद की ही प्रकारान्तर से स्वीकृति थी। पर उस हिन्दी का स्वरूप गाँधी जी के मत में 'हिन्दुस्थानी' या 'हिन्दुस्तानी' का था, जो उर्दू-मिश्रित हिन्दी हो सकती थी। गाँधी जी सन् १९१८ और सन् १९३५ में दो बार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए।

(४) गाँधी जी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार करने के लिए सम्मेलन के १९१८ के इन्दौर अधिवेशन के अनुसार स्वामी सत्यदेव परित्राजक और देवदास गाँधी को मद्रास भेजा गया। और दक्षिण भारत में ३० युवक हिन्दी सीखने के लिए सम्मेलन के हिन्दी-विद्यापीठ प्रयाग आये, इनमें मुख्य थे श्री हरिहर शर्मा, श्री क० म० श्रीराम शर्मा, सीताराम और सन्नाथ। और तभी सन् १९१८ में मद्रास के जार्ज टाउन में हिन्दी-साहित्य

सम्मेलन का प्रचार-कार्यालय खोला गया। १९२७ में उस कार्यालय ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा—एक स्वतंत्र संस्था का रूप ले लिया।

(५) महात्मा गाँधी की प्रेरणा से सन् १९२० में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, जिसमें हिन्दी के माध्यम में शिक्षा दी जाती है। पहले नागरी और फारसी दोनों यहाँ पढ़ाई जाती थी। भविष्य में हिन्दी तथा नागरी लिपि के स्वीकार किये जाने के बाद विद्यापीठ ने भी फारसी लिपि का आग्रह छोड़ दिया है। इसी प्रकार सन् १९२१ में राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी-माध्यम से उच्च शिक्षा देने के लिए काशी-विद्यापीठ का स्थापना की।

(६) २० जनवरी सन् १९२७ को संयुक्त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) की सरकार की प्रेरणा से नजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 'हिन्दुस्तानी प्रकाशनी' की स्थापना प्रयाग में हुई। यह प्रकाशनी हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्य के प्रचार, अभिवृद्धि और प्रोत्साहन के लिए थी।

(७) राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से सन् १९३५ में हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद की स्थापना हुई।

(८) सन् १९३६ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन के अवसर पर महात्मा गाँधी की प्रेरणा में भारत के पच्छिमी और पूर्वी भाग में हिन्दी के प्रचार के लिए सम्मेलन की संगठित संस्था के रूप में हिन्दी-प्रचार-समिति का संगठन किया गया, इसका कार्यालय वर्धा में हुआ। सन् १९३८ में सम्मेलन के एक निर्णय के अनुसार इसका नाम राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा हुआ। प्रत्येक अहिन्दी भाषी प्रदेशों में, जिनमें उत्तर के कश्मीर और पंजाब भी सम्मिलित हैं, इसकी शाखाएँ स्थापित हुईं। समिति ने सम्मेलन से अलग अपनी नई परीक्षाएँ चलाई। उनमें अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी का अत्यन्त व्यापक प्रचार हुआ और हो रहा है।

(९) हिन्दी और हिन्दुस्तानी को लेकर सम्मेलन से महात्मा गाँधी का सन् १९४१ में मतभेद हो गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से 'हिन्दु-स्तानी' रूप में राष्ट्रभाषा की कल्पना की। २ मई सन् १९४२ का उनकी प्रेरणा से हिन्दुस्तानी प्रचार-समिति वर्धा की स्थापना हुई। इसके सदस्यों में

५० जवाहरलाल नेहरू, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुलकलाम आजाद जैसे राष्ट्रीय नेता थे। बाद में इसका काम गुजरात विद्यापीठ को सौंपा गया। इस समिति ने फारसी और नागरी दोनों लिपियों में अपनी परीक्षाएँ संचालित की।

(१०) ११ अप्रैल सन् १९४७ को बिहार की विधान-सभा ने बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना पटना में की। इसका उद्देश्य राष्ट्रभाषा में विविध विषयों के मौलिक ग्रन्थों का प्रकाशन और बिहार की बोलियों का अनुशीलन है। परिषद् का विधिवत् कार्य १९ जुलाई १९५० से श्री गिबपूजन सहाय के इसके मंत्री नियुक्त होने के साथ आरम्भ हुआ।

(११) इस अवधि में स्थापित तीन अन्य संस्थाओं का भी उल्लेख हिन्दी-प्रचार की दृष्टि में किया जाना चाहिए, इनकी परीक्षाओं और प्रकाशनों ने हिन्दी के प्रति अनुराग पैदा किया है और हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रचार एवं अभिवृद्धि में सहायता की है, ये संस्थाएँ हैं—(क) महिला विद्यापीठ प्रयाग (सन् १९२२), (ख) हिन्दी विद्यापीठ देवघर (संवत् १९८६ वि०—सन् १९२९) (ग) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा मंडल, पुणे (सन् १९४५)।

(१२) १५ अगस्त १९४७ में देश को स्वराज्य प्राप्त हुआ। उसी के साथ हिन्दी को समग्र रूप से राष्ट्रभाषा का पद मिलने की आशा भी राष्ट्रभाषा-प्रेमियों को थी। परन्तु जैसे स्वराज्य देश के विभाजन के साथ प्राप्त हुआ, वैसे ही २६ जनवरी १९५० को भारत का जो संविधान समझौता राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हुआ उसमें भी हिन्दी को राजभाषा का पद तो मिला किन्तु साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए पन्द्रह वर्ष की अवधि रखी गयी। अंग्रेजी के प्रयोग के साथ संविधान द्वारा राजभाषा हिन्दी और नागरी लिपि के प्रयोग की स्वीकृति, संयुक्त प्रान्त (अंग्रेज) सरकार की १८ अप्रैल १९०० की उस विज्ञप्ति के समकक्ष थी जिसमें अदालतों और दफ्तरों के कार्य में उर्दू भाषा और फारसी लिपि के साथ हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रयोग का आवश्यक कहा गया था, तथा सरकारी क्लर्कों और अफसरों को नागरी अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने का निदेश किया गया था। न तो सन्

१९०० के बाद सरकारी अदालतों में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को उचित स्थान प्राप्त हुआ और न आज पन्द्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी देश के सघात्मक गणनंत्र शासन में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि प्रतिष्ठित हो सकी।

संविधान में राजभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि की स्थापना का प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है—

“धारा ३४३ (१) सभ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। सभ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होनेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(२) सभ (१) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष का कालावधि के लिए सभ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती हैं—

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा सभ के राजकीय प्रयोजनों से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग अधिकृत कर सकेगे।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसा कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।”

संविधान के द्वारा राज्य के विधानमण्डल में अंग्रेजी, हिन्दी या राज्य की भाषाओं में से किसी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र है—

“धारा ३४३ अनुच्छेद २४६ और २४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से

सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य से प्रयुक्त होनेवाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को संघीवार कर भेजना ।

परन्तु जब तक राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा इसमें अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए संघेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक रहने वह प्रयोग की जाती थी ।

१९५० तक के संघर्ष का निष्कर्ष

इस प्रकार सन् १९०१ में १९५० तक की अवधि में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रचार का अत्यन्त व्यापक प्रयास हुआ । भारत के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में नागरी लिपि और हिन्दी को मान्यता के लिए सहज आकर्षण पैदा हुआ । अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी के समर्थ लेखक भी पैदा हुए, यह हिन्दी की व्यापकता और लोकप्रियता का प्रमाण है, इन लेखकों में डा० रामेश्वराय, श्री अनन्तगोपाल त्रिवेदी जैसे माने-जाने गुरु हैं ।

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग और उससे सम्बद्ध संस्थाओं ने हिन्दी-भाषा और नागरी लिपि के विस्तार में बड़े ही मनोयोग दिया जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए । अनेक अहिन्दी-भाषी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से राष्ट्रभाषा के योग्य हिन्दी की उपयुक्तता स्वीकार की है । जिनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री सुभाषचन्द्र बोस, श्री श्रीनिवास शास्त्री, डा० मुनीति कुमार चाटुर्ज्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्रीमती अम्बु जम्बाल, श्री नरसिंह चित्ता मणि, डा० रामकृष्ण भंडारकर, श्री फजल अली, श्री खज्जा हुसैन निजामी और श्री जांश मलीहाबादी के नाम प्रमुख हैं । इस अवर्षशती के पिछले वर्षों में गाँधी जी के प्रभाव से हिन्दुस्तानी का जो समर्थन प्रारम्भ हुआ उससे अब हिन्दी का संघर्ष उर्दू के स्थान पर हिन्दुस्तानी से ही रहा । परन्तु स्वराज्य प्राप्ति के बाद देश के बँटवारे में स्थिति बदल गई, जिस राष्ट्रीय एकता के लिए

हिन्दुस्तानी भाषा और नागरी लिपि एवं फारसी लिपि का समर्थन हो रहा था, उस एकता के भंग हो जाने पर हिन्दुस्तानी और फारसी लिपि का प्रश्न ही दूर हो गया। इस प्रश्न के दूर हो जाने पर हिन्दी के विरोधियों ने हिन्दी भाषा को अभी राजकाज के अनुपयुक्त बना कर तथा १४ विभिन्न भाषाओंवाले देश में एकता कायम रखने के लिए हिन्दुस्तानी के स्थान पर अंग्रेजी को खड़ा कर दिया और हिन्दी के दहिकार के लिए पूरा प्रयास करते रहे, इसमें वे अभी तक सफल हैं, आगे देखिए क्या होता है ? यथार्थ व्यवहार में राजभाषा आज भी अंग्रेजी है।

स्वराज्य मिलने के साथ राज्यों में उत्तरप्रदेश ने प्रभूवर्ष १९४७ में ही हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। मविधान के अनुसार पुनः उसने सन् १९५१ में राजभाषा अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार राज्य के राजकीय पयोजनाओं के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीकार किया गया। बिहार प्रदेश ने सन् १९५० में राजभाषा अधिनियम पारित किया और राजकाज के पूर्णतया हिन्दीकरण के लिए दस वर्षों की अवधि रखी, उसने नागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राजभाषा की मान्यता दी। राजस्थान सरकार ने सन् १९५० में राजस्थान-राजभाषा-अधिनियम पारित कर हिन्दी को प्रदेश की राजभाषा घोषित किया। मध्यप्रदेश ने राजभाषा अधिनियम पारित कर हिन्दी तथा मराठी दोनों भाषाओं को राज्य की राजभाषा घोषित किया। तब मध्यप्रदेश में मराठी भाषी जिले भी सम्मिलित थे।

किन्तु मही तथ्य यह है कि उत्तरप्रदेशों की सरकारों ने (केवल बिहार को छोड़ कर) हिन्दी को राजभाषा घोषित करके भी अपनी घोषणा का व्यवहार रूप में परिणाम न किया। घोषणा का व्यावहारिक रूप सन् १९६४ में दिखाई पड़ता है।

‘हिन्दी’ नाम का इतिहास

‘मन्धु’ का बिगड़ा हुआ रूप ‘हिन्दू’ ईरानी भाषाओं में प्रयुक्त शब्द है। ‘हिन्दु’ का पहला प्रयोग जर्जुश्न की लिखी पारसाधर्म की मूल पुस्तक जेन्दा-वेस्ता (७०० ई० पू०—२ वीं शती ई०) में मिलता है। ‘हिन्दु’ या ‘हिन्द’ देश का नाम है और ‘हिन्दी’ इस देश के निवासियों का सजा है। ‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग हिन्द देश के निवासी के अर्थ में किया गया है—

हिन्दी है हम वतन है हिन्दोस्तान हमारा। (डा० डकवाल)

कैम्ब्रिज हिन्दी ग्राफ इण्डिया भाग ३, पृष्ठ २ के अनुसार कालिजर के हिन्दू-नरेश ने बिना हाँदे और महावत के हाथियों पर मरलता से सवारी करेवाले तुर्कों की प्रगत्या में हिन्दी भाषा में कुछ पद्य लिखे जिसे महमूद गजनवी ने अपने दरबार में हिन्दू विद्वानों को दिखाया था। महमूद गजनवी का आक्रमण सन् १००१ से १०२३ तक १७ बार भारत पर हुआ, अतः मानना पड़ेगा कि व्यापक गति में भारतीयों की भाषा के लिए हिन्दी की सजा प्रचलित हो गई थी। प्राचीन मुसलमान-इतिहासकारों में प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता ने बम्हनीराज्य (सन् १३४७) में राजकाज के लिए हिन्दी जुबान के प्रयोग का बान लिखी है। इतना तो निश्चित है कि भारत के मध्य भाग में बोली जानेवाली भाषा के लिए ‘हिन्दी’ नाम मुसलमानों का हो दिया हुआ है। क्योंकि मुसलमानों के समकाल ही हिन्दी के वरिष्ठ कवियों ने सस्कृत का तुलना में अपनी काव्य-वाणी की भाषा कहा है। त्रिद्यापति (चौदहवीं शती उत्तरार्ध) ने लिखा है—

बालचंद विज्जावड भासा ।

दुहं नहि जागइ दुज्जन हासा ॥

कबीर (पन्द्रहवीं शती) ने भाषा को बहता हुआ निर्मल जल कहा है—

कबिरा रासकुत कूप जल, भाखा बहता नीर ।

तुलसीदास (सोलहवीं शती उत्तरार्ध) का निवेदन था—

भाषा-भनिति सोरि मति थोरी ।

हौमवे जोग हौमे नहि खोरी ॥

हमारी इस भाषा की 'हिन्दुस्तानी' संज्ञा भी दी गयी है । यह नाम अंग्रेजों ने दिया । फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के प्रिंसिपल जान गिल-क्राइस्ट ने सन् १८०३ में हिन्दी-मध्य की जो पुस्तकें लिखवाईं उनकी भाषा को वे हिन्दुस्तानी कहते थे । पर उनका 'हिन्दुस्तानी' नाम विशुद्ध हिन्दी से भिन्न उर्दू-प्रभावित शैली के लिए था । वे विशुद्ध हिन्दी को अशिष्ट शैली या हिन्दवी कहते थे । कैप्टेन विलियम प्राइस (सन् १८२३) ने, जो फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के हिन्दुस्तानी-विभाग के अध्यक्ष थे, हिन्दुस्तानी को हिन्दी से अलग एक भाषा के रूप में स्वीकार किया और हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी दोनों को सत्ता स्वीकार की । उनके पीछे राजकाज में रहनेवाले अंग्रेजों ने प्रायः हिन्दी को हिन्दुस्तानी भाषा कहा है और भाषा का अध्ययन करने वाले अंग्रेजों ने इसे हिन्दी नाम से पुकारा है । हिन्दी के प्रथम समाचारपत्र उदंत मार्टंड (सन् १८२६) ने खड़ीबोली को 'मध्य देश की भाषा' कहा था । फ्रेडरिक जातेशोर (सन् १८३६) के मत में कुमायूँ तथा गढ़वाल प्रान्तों के पुलिस की रिपोर्ट तथा कचहरी के कागज हिन्दुस्तानी भाषा तथा नागरी लिपि में लिखे जाते थे । डा० ग्रियर्सन (सन् १८८२) के मत में उक्त हिन्दुस्तानी या हिन्दी भाषा अंग्रेज सरकार के आदेशानुसार उन्नीसवीं शती के आरम्भ में नहीं बनाई हुई भाषा थी, हिन्दी का अस्तित्व एक बोली से अधिक नहीं था । सन् १८३६ के एक सरकारी इस्तहारनामा में हिन्दी बोलो में हुक्म लिखने का निर्देश किया गया था और फारसी को जवान संज्ञा दी गई थी । पादरी केल्लाग (सन् १८७५) ने स्वीकार किया था कि भारत के एक चौथाई भाग अर्थात् २५ करोड़ की आबादी में ६-७ करोड़ की भाषा हिन्दी है ।

‘हिन्दी’ नाम का इतिहास

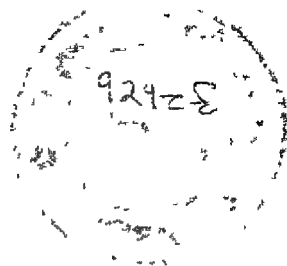
२६

फ्रांसीसी विद्वान् गार्सी द तामी (सन् १८५२) ने हिन्दुस्तानी उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहा है जो पश्चिमोत्तर प्रदेश की सरकार की भाषा नियत की गई थी । हिन्दी उससे अलग थी । मुसलमान बादशाह फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, साथ में वे एक हिन्दी-नकाश भी रखते थे, अंग्रेज-सरकार ने फारसी के स्थान पर हिन्दुस्तानी उर्दू को अपने राजकाज की भाषा बनाया और हिन्दी का भी पहले की तरह गौण स्थान बना रखा । यहाँ हिन्दुस्तानी उर्दू से गार्सी द तामी का तात्पर्य उर्दू में ही है । गियमन के पूर्व इन्होंने भी हिन्दी को एक बोली से अधिक महत्त्व नहीं दिया है । जान गिलक्राइस्ट ने सन् १८०३ में हिन्दुस्तानी का जो रूप समझा था, गार्सी द तामी की हिन्दुस्तानी उससे भिन्न थी ।

महात्मा गाँधी ने राष्ट्रभाषा के लिए जो हिन्दुस्तानी नाम प्रस्ताव किया वह हिन्दी और उर्दू के बीच की, दोनों की निकटतम सरल शैली थी, सच पूछा जाय तो गाँधी जी के प्रयास से सन् १९३५ के बाद एक नई हिन्दुस्तानी भाषा बनाई गई । इस हिन्दुस्तानी के लिए नागरी और फारसी दोनों लिपियाँ अपनाई गई । इसमें संस्कृत के साथ अरबी-फारसी शब्दों का बहिष्कार तो हुआ पर इसका झुकाव फारसी की ओर ही रहा । हिन्दुस्तानी का वह निर्माण राजनीतिक बुनियाद पर राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से हुआ था ।

आज ‘हिन्दी’ नाम से सर्वमान्य या सार्धित्विक—खड़ीबोली हिन्दी का तात्पर्य ग्रहण किया जाता है । खड़ीबोली (नागरी) ही हिन्दी का मानक रूप है, इसके प्रचार-प्रसार की लम्बी कहानी का, जिसका विस्तार तेरहवीं शती से बीसवीं शती तक है, पीछे एक सिंहावलोकन किया गया है और इसके इतिहास की प्रायः सभी प्रमुख तिथियों की चर्चा कर दी गई है । खड़ीबोली हिन्दी का मूल स्वरूप है, खड़ीबोली नाम इसकी प्रकृति और गुण पर मिला है । इस बोली का क्षेत्र मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के जिले, बुलन्दशहर जिला का कुछ भाग और दिल्ली के आस-पास का क्षेत्र है, प्रार्चालकाल में इस भूभाग को कुह-प्रदेश कहा जाता था, महागण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इसीलिए इस बोली को ‘कौरवी’ नाम दिया है ।

हिन्दी-भाषी प्रदेश, भारत के मध्य भाग या मध्यदेश, की हिन्दी-बोलियों में खंडीबोली का स्वरूप अन्य बोलियों की अपेक्षा व्यापक और क्षमता-पूर्ण है। इसकी व्यापकता की चर्चा पीछे की गई है, भारत के अन्य भागों के हिन्दी कवियों की वाणी में भी इसके स्वरूप का प्रयोग हुआ है। यह व्यापकता भी इसकी क्षमता की छोनक है। नागरी लिपि में जो वैज्ञानिकता है, हिन्दी के इस स्वरूप में भी भाषा की दृष्टि से वही वैज्ञानिकता है। राम और कृष्ण के धार्मिक एवं सांस्कृतिक ग्रन्थोल्लेखों की भूमि की बोली न होने के कारण इसे अपने विकास में पीछे रह जाना पड़ा, लेकिन जब इसको अवरगर सिन्हा तब इसने न केवल बज और अवर्धा भाषाओं को ही आक्रान्त कर लिया उनका सत्ता बोली मात्र में सीमित कर दी, और अपने वैज्ञानिक स्वरूप के कारण पूरे राष्ट्र के लिए यह प्रिय बन गई भारत में पहली बार इसने भाषा का दृष्टि से वह स्थान प्राप्त किया जो कभी सम्स्कृत को प्राप्त था। आर्य-समाज ने इससे महत्त्व का आकलन उल्लोमवी शक्ती के अन्त में ही कर लिया था और इसे वे आर्य-भाषा कहते थे। हिन्दी के महत्त्वपूर्ण विकास और बढ़ती हुई लोकप्रियता में उसकी वैज्ञानिक लिपि नागरी का भी बहुत बड़ा योगदान है, यह तथ्य भी हिन्दी-प्रचार के इतिहास का एक पक्ष स्वीकार किया जाना चाहिए।



४

संस्थाएँ

हिन्दी और नागरी लिपि के प्रचार-कार्य का आन्दोलनात्मक रूप भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय में ही शुरू हुआ था। तब इस प्रचार और आन्दोलन में हिन्दी के लेखकों और पत्रों के सम्पादकों ने ही प्रमुख रूप से भाग लिया, हिन्दी केहित की विशेष चिन्ता जिनको हुई उनमें हिन्दी में लिखने-पढ़ने का शौक था और वे साहित्य के जिज्ञासु थे। हिन्दी के प्रचार-कार्य के लिए संस्थाओं की स्थापना भी हुई परन्तु तब की वे संस्थाएँ पत्रकारों या लेखकों की संस्थाएँ थीं। हिन्दी के प्रचार और प्रसार की संस्थाओं में लेखकों के अनि-रिक्त जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व भारतेन्दु जी के बाद दिखाई पड़ता है। उनके समय में स्थापित बाबू तानाराम द्वारा संचालित 'भाषा सर्वध्वनी सभा अली-गढ़', प्रयाग की 'हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा' (सन् १८८४) ऐसी ही संस्थाएँ थी, जो अपने संचालकों के साथ ही समात हो गईं। भारतेन्दु जी स्वयं अपने में एक संस्था थे। उस काल के इन लेखकों द्वारा संचालित पत्र-पत्रिकाओं को भी एक संस्था का ही छोटा-मोटा रूप समझना चाहिए। भारतेन्दु की 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' (सन् १८७३), प० बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी-प्रदीप' (सन् १८७६) और प० प्रताप नारायण मिश्र का 'ब्राह्मण' पत्र ऐसे मासिक अखबार थे, जिनके लेखक-पाठक अपने को उनका अंग समझते थे और सभी का उद्देश्य था—हिन्दी तथा नागरी का प्रचार करना। 'भाषा-सर्वध्वनी सभा' के संस्थापक बाबू तानाराम भी 'भारत-वन्धु' नाम का पत्र निकालते थे। दूसरे (शब्दों में पत्र अखबार) ही संस्था थे बीसवीं शती के म

पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'सरस्वती पत्रिका' भी उनके समय तक बहुत कुछ एक सस्था का रूप थी, जिसका उद्देश्य रचनात्मक था अर्थात् हिन्दी में योग्य लेखक पैदा करना, हिन्दी के साहित्यिक रूप का सुधार करना, उसकी शैली को विकृत होने से बचना। ऐसी सस्थाएँ व्यक्तियों के साथ ही जीवित रह रही थीं।

हिन्दी का प्रचार करनेवाली जनता की सस्था के रूप में सर्वप्रथम नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी का नाम सामने आता है। तो भाँ नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी के पूर्व भारतेन्दु काल की एक अन्य सस्था का विस्तृत परिचय हिन्दी के प्रचार-कार्य के प्रसंग में यहाँ आवश्यक है, वह है—मेरठ की देवनागरी-प्रचारिणी-सभा।

१—देवनागरी प्रचारिणी सभा, मेरठ

इस सभा की स्थापना पं० गौरीदत्त शर्मा तथा मेरठ के हिन्दी-प्रेमियों की प्रेरणा से सन् १८८१ में की गई थी। पं० गौरीदत्त जी शर्मा इस सभा के उपमंत्री रहे हैं। इस सभा को महाराज रीवाँ, टिहरी-नरेण और कूटेइवरा-धीन श्री राव उमराव सिंह ने आर्थिक सहायताएँ दी थी।

उस समय सरकारी दफ्तरो में हिन्दी में कामकाज करने के लिए जो कठिनाई उत्पन्न होती थी उन कठिनाइयों में हिन्दी सीखने के लिए व्याकरण की पुस्तक का और हिन्दी शब्द-कोश का भी अभाव था। हिन्दी को सम्पन्न भाषा कहने के लिए इसमें किन्नी समृद्ध शब्द-कोश का होना बहुत जरूरी था। बहुत याद में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने बृहत् हिन्दी शब्दसागर तैयार करवा कर इसकी पूर्ति की। परन्तु इस प्रसंग में देवनागरी प्रचारिणी सभा, मेरठ का आरंभिक प्रयास भी प्रससनीय है, सभा के निश्चय के अनुसार और अन्य विद्वानों के अनुरोध पर उनकी सहायता लेकर पं० गौरीदत्त शर्मा ने पाँच वर्ष के थम के बाद एक 'गौरी नागरी-कोष' तैयार किया, जो सन् १९०१ में प्रकाशित हुआ था। इस कोष में जीवन के व्यवहार और अदालती, दफ्तरो के प्रयोग में आनेवाले हिन्दी-उर्दू शब्दों का संग्रह है, जिनका अर्थ

पहले नागरी लिपि और हिन्दी भाषा में दिया गया है और पुनः उसी के साथ रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा में भी उनका अर्थ है। अंग्रेजी भाषा में अर्थ देने का अर्थ ही है कि यह कोश अंग्रेजी सरकार की अदालतों और दफ्तरो में हिन्दी के प्रचार की दृष्टि से तैयार किया गया था। पं० गौरीदत्त शर्मा ने उर्दू को हिन्दी से अलग नहीं माना है, उन्होंने कोश की भूमिका, पृष्ठ ५ में लिखा है—“यह देशी भाषा (वर्नेक्यूलर) का नागरी अक्षरों में कोष है (जो भाषा इस देश के बड़े-बड़े गृहों के बाजारों में बोली जाती है वह देशी भाषा कहलाती है), इसी देशी भाषा को हिन्दू हिन्दी और मुसलमान उर्दू कहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दी-उर्दू दोनों एक हैं।” यह कोश ५२८ पृष्ठों का है, इसमें लगभग १६००० शब्द हैं। नागरी अक्षरों और हिन्दी के प्रचार के लिए शर्मा जी ने अन्य पुस्तकें भी लिखी थी, उनमें उल्लेखनीय है—अक्षर-दीपिका, नागरी के दफतर, उर्दू और फारसी अक्षरों से हानि।

सन् १८८२ में सरकार ने जो शिक्षा-आयोग कायम किया था, उसके समक्ष देवनागरी प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधि दल ने भी नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के समर्थन में अपना प्रतिवेदन दिया था। उक्त कोश की भूमिका में इसका जिक्र है, साथ ही पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय के १८ अप्रैल १९०० के, दफतरो में नागरी प्रवेश के, आदेश पर सन्तोष प्रकट किया गया है—“सन् १८८२ ई० में हम लोगों ने इन्ज्यूकेशनल कमीशन के रूबरू यह सिद्ध कर दिया था और प्रकट किया था कि इस देश के सर्वसाधारण में नागरी अक्षरों के द्वारा प्राईमरी शिक्षा बहुत जल्दी फैल सकती है इस नियम पर कि इस देश के दफतरो में नागरी अक्षर जारी कर दिये जायँ। अन्य देश की भाषाओं के अक्षरों द्वारा इस देश के सर्वसाधारण में कदापि प्राईमरी शिक्षा नहीं फैल सकती। तब से अब तक हम लोग अपने अभिप्राय को मजबूत करने के लिए अपनी गवर्नमेन्ट को बराबर याद दिलाते रहे और मिमोरियल भेजते रहे और सच्चे दिल से बड़ी आधीसतई के साथ प्रार्थना करते रहे। १८ वर्ष से यह हमारा मुकद्दमा गवर्नमेन्ट में पेश था अन्त को शीघ्रतः श्रीमान महाराजाधिराज सर एन्टोनी मेकडानल पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और अवध देश

के चीफ कमिश्नर बहादुर ने १८ तारीख एप्रिल मन् १९०० को रिजोल्यूशन पास करके इस देश के दफ्तरों में नागरी प्रचार की आज्ञा दे दी और इसी तारीख के गवर्नमेन्ट गजट में छाप दिया।” (भूमिका पृष्ठ ४)

ऊपर शर्मा जी ने सरकार को बराबर मिमोरियल भेजने की बात लिखी है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि २ मार्च १८६८ ई० को जब नागरी-प्रचारिणी सभा काशी के प्रयत्नों में पं० मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गवर्नर महोदय की नागरी के सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रार्थना-पत्र दिया गया तब उसका अनुमरण करते हुए देवनागरी प्रचारिणी सभा मेरठ ने भी १८९९ में एक मिमोरियल गवर्नर महोदय के पास भेजा था।

सभा के पास एक देवनागरी पुस्तकालय भी रहा है।

यद्यपि उक्त कार्यों में पं० गौरीदत्त शर्मा ही प्रमुख रहे हैं तो भी उन्होंने देवनागरी प्रचारिणी सभा के नाम पर ही सारा काम किया है। सभा के सदस्य के रूप में उनके सहयोगियों की सम्मति और सहायता से सारा काम होता रहा है। अब सभा का अस्तित्व नहीं है तो भी सभा की देख-रेख में निर्मित ‘गौरी नागरी कोष’ के लिए हिन्दी की प्रचार-संस्थाओं के इतिहास में देवनागरी प्रचारिणी सभा, मेरठ का नाम अवश्य लिया जाना चाहिए।

२—नागरी प्रचारणी सभा, काशी

इस सभा की स्थापना नागरी-प्रचार के उद्देश्य से सौर २७ फाल्गुन संवत् १९४९ (१० मार्च १८९३) को हुई। यह महत्वपूर्ण काम काशी-क्वींस कालेज की ५वीं कक्षा के कुछ उत्साही छात्रों का था। उन्होंने अपने उद्देश्य के अनुसार इसका नाम नागरी-प्रचारिणी-सभा रखा। इन छात्रों में प्रमुख कार्यकर्ता थे—गोपाल प्रसाद खत्री, रामसूरत मिश्र, उमराव सिंह, शिवकुमार सिंह तथा रामनारायण मिश्र। बाद में श्याममुन्दर दास जी का सहयोग इस सभा को प्राप्त हुआ और वे इसके मंत्री नियुक्त हुए। आगे चल कर शीघ्र ही छात्रों की इस सभा की तत्कालीन गण्यमान महानुभावों, विद्वानों और हिन्दी-प्रेमियों का सहयोग

प्राप्त हुआ। उन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार की। श्री राधाकृष्ण दास (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के फुफेरे भाई) इसके प्रथम अधिवेशन के सभापति हुए। सभा के प्रथम वर्ष में ही अन्य प्रमुख सहयोगियों और सदस्यों के नाम हैं—महामना मदनमोहन मालवीय, कालाकाकर नरेश रामपाल मिह, राजा शशिशेखर राय, अम्बिकादत्त व्यास, चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमघन', राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, ज्वालादत्त शर्मा (लाहौर), नन्दकिशोर देव शर्मा (अमृतसर), कुँवर जोधसिंह मेहता (उदयपुर), समर्थदान (अजमेर), डॉ० सरजार्ज ग्रियर्सन। पं० मदनमोहन मालवीय ने सभा के माध्यम से ही हिन्दी-प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य सरकार में भंडारण ले कर किया।

उद्देश्य

नागरी लिपि और हिन्दी के प्रचार के साथ सभा ने ठोस रचनात्मक कार्यों का भी हाथ में लिया, वे कार्य हैं—प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज, हिन्दी के वृहत् शब्द कोश का निर्माण, हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास का निर्माण, अन्य विषयों के मानक ग्रन्थों का प्रकाशन।

कार्य

सन् १८९६ में सरकार जब अपने दफ्तरो और अदालतों में रोमन लिपि के प्रयोग का संकल्प दृढ़ कर रही थी और नागरी लिपि के प्रयोग की भांग का दरवाजा सदा के लिए बन्द कर रही थी तब सभा ने 'नागरी कैरेक्टर' नाम की अंग्रेजी में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें नागरी लिपि के प्रयोग की अच्छाइयों और रोमन लिपि के दोषों पर मलीमोति प्रकाश डाला गया था। उसका वितरण सभा ने सरकार, अफसरों और जनता में किया। फलतः सरकार ने अपनी नियुक्त-समिति की सिफारिश पर भी रोमन अक्षरों के प्रयोग का विचार बदल दिया।

२ मार्च १८९८ ई० को इलाहाबाद में लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर एण्टोनी मेकडनेल महोदय की महामना पं० मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में १६ जिल्लों में ६० हजार हस्ताक्षरों से संयुक्त जो प्रार्थना-पत्र अदालतों में नागरी

लिपि के प्रयोग के लिए दिया गया, उसके लिए इतने हस्ताक्षर इकट्ठे करने का श्रमसाध्य कार्य सभा के उत्साही कार्यकर्ताओं ने सम्पन्न किया था, उन्होंने दिन को दिन और रात को रात न समझ कर अनवरत प्रयास किया था। इस प्रयास का भी यह परिणाम था कि १८ अप्रैल १९०० को गवर्नर महोदय ने विज्ञप्ति निकाल कर फारसी लिपि और उर्दू भाषा के साथ नागरी लिपि और हिन्दी भाषा का प्रयोग भी अदालतों में अनिवार्य कर दिया, यद्यपि प्रयोग की यह अनिवार्यता अदालतों को एक सीमा तक ही थी।

सभा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हिन्दी के वृहत् कोश का निर्माण था। उसने इस उद्देश्य से सात खंडों में 'हिन्दी शब्द सागर' का प्रकाशन किया है। यह अत्यन्त श्रम-साध्य और व्यय-साध्य कार्य था। इसके सम्पादन में सन् १९०८ से सन् १९२८ तक का २१ वर्ष का समय लगा है। इसमें ४२८१ पृष्ठ हैं और कुल शब्द-संख्या ९३११५ है। शब्दकोश को लेकर इतना गौरव-मय प्रकाशन सभा ने ही किया। ३० वर्ष बाद जब हिन्दी का शब्द-भंडार बहुत बढ गया, ज्ञान-विज्ञान के अनेक नये शब्द अपने आप अस्तित्व में आने लगे तब इस शब्दसागर के सशोधन और परिवर्धन की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रसन्नता की बात है कि सभा ने उसमें हाथ लगाया, उसे केन्द्रीय सरकार का इमके लिए आर्थिक अनुदान भी प्राप्त हुआ, यह कार्य सभा ने सन् १९५४ में आरम्भ किया था और अब सशोधन-परिवर्धन का कार्य समाप्त हो चुका है, सशोधित, परिवर्धित शब्दसागर का पहला खंड सन् १९६५ में प्रकाशित हुआ। उसके प्रकाशन का उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा सन् १९६५ को प्रयाग के राजभवन में सम्पन्न हुआ है।

हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज की ओर सर्वप्रथम ध्यान सभा ने दिया। शुरु में उसने यह कार्य एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) के माध्यम से करवाया, सन् १९०० के बाद उसने यह कार्य स्वतंत्र रूप से आरम्भ किया। उसे इस महत्त्वपूर्ण कार्य में डा० काशीप्रसाद जायसवाल, महामहोपाध्याय गरीशंकर हीराचन्द्र ओझा और डा० हीरालाल जैसे सुविख्यात विद्वानों का सहयोग प्राप्त रहा है। इन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज से हिन्दी-साहित्य ने

इतिहास-लेखन की सामग्री परिपूर्ण हुई है। सन् १९२८ तक मभा को खोज में ६०० महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थ मिले थे। इधर मभा ने जो सक्षिप्त खोज-विवरण दो भागों में प्रकाशित किया है उनमें ६५६० ग्रंथकारों एवं १५८८२ ग्रंथों में सम्बद्ध तथ्यों की टिप्पणी-सहित नामानुक्रमणी दी गई है। मभा ने यह खोज-कार्य हिन्दीभाषी प्रदेशों में करवाया है। द्रव्याभाव में यह काम उतनी तेजी से नहीं हो सका है जितना चाहिए था। हस्तलिखित ग्रन्थों के खोज-विवरण को क्रमशः सम्पादित कर प्रकाशित किया जा रहा है, यह सम्पादन अधिकारी विद्वान कर रहे हैं।

मभा ने अपनी स्थापना के साथ ही नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के संरक्षण तथा प्रसार के लिए 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' के नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित की थी। आगे चल कर यह पत्रिका त्रैमासिक हो गई। इसमें शोध तथा अनुगोलन के लेख प्रकाशित होते हैं, ये लेख हिन्दी-साहित्य के विविध अंगों के विवेचन, भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनुसंधान एवं प्राचीन-पूर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला के पर्यालोचन को लेकर लिखे जाते हैं। आज यह पत्रिका हिन्दी-जगत् की सबसे प्राचीन पत्रिका है। इसमें प्रकाशित होनेवाली सामग्री ज्ञान और प्रमाण का उच्चस्तर रखती है।

मभा ने 'हिन्दी' और 'विधि पत्रिका' नाम के हिन्दी-मासिक तथा 'हिन्दी-रिव्यू' नाम का अंग्रेजी-मासिक भी प्रकाशित किये थे, पर आर्थिक अभाव से उनको बन्द कर देना पड़ा। इधर सन् १९६६ में उसने पुनः हिन्दी-साहित्य और देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार से संबद्ध समाचार और सूचनाओं की परिचायिका एक नई 'नागरी पत्रिका' प्रकाशित की है।

मभा जिस समय स्थापित हुई, उस समय हिन्दी का किसी हिन्दी-विद्वान् द्वारा लिखा हुआ अपना व्याकरण नहीं था। इस अभाव के कारण हिन्दी के पठन-पाठन का उचित प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता था। अब तक दो अंग्रेजों के ही हिन्दी-व्याकरण उपलब्ध थे, जो वस्तुतः ईसाई-धर्म-प्रचारकों के लिए लिखे गये थे। एक था १८२७ में लिखा गया पादरी एडम का व्याकरण और दूसरा था पादरी कैलाश का व्याकरण जो सन् १८७५ में लिखा गया। कैलाश

का व्याकरण बड़ा और सर्वाङ्ग था परन्तु अंग्रेजी में था। एडम का व्याकरण यद्यपि हिन्दी में था लेकिन बहुत पुराना पड़ गया था, छोटा था तथा हिन्दी के अद्यतन रूप की व्याख्या नहीं करता था। सभा ने व्याकरण लिखवाने के लिए योजना-बद्ध कार्य किया और पं० कामताप्रसाद गुरु को यह काम सौंपा। उनका लिखा हुआ हिन्दी-व्याकरण ग्रन्थ सन् १९१६ में प्रकाशित हुआ। उसका संक्षिप्त संस्करण भी पाठकों की सुविधा के लिए निकाला गया। व्याकरण का सम्बन्ध भाषा के विकास और भाषा-विज्ञान से होता है, वर्तनी आदि की समस्याएँ भी उसके भीतर आती हैं, इस दृष्टि से हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में जो अध्ययन और अनुशीलन पिछली दशाब्दियों में होता रहा उससे हिन्दी व्याकरण के नये सिरे से परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह कार्य सभा ने इस विषय के अधिकारी विद्वान् पं० किशोरीदास वाजपेयी से करवाया और सन् १९६० में उनका लिखा हुआ 'हिन्दी-शब्दानुशासन' प्रकाशित किया।

सन् १९२८ में सभा ने हिन्दी साहित्य के इतिहास और उसके अनुशीलन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रामाणिक एवं सर्वांग ग्रन्थ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का लिखा हुआ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' प्रकाशित किया, जो अब भी उतना ही प्रामाणिक और अपने काल-निरूपण में मौलिक है।

हिन्दी में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए सभा ने देश के हिन्दी-प्रेमी श्रीमानों से सहायता प्राप्त की है, स्वयं भी इस दिशा में अपने साधनों का उपयोग किया है। अतः सभा के महत्त्वपूर्ण सभी प्रकाशन विभिन्न व्यक्तियों की स्मृति रूप पुस्तकमालाओं में प्रकाशित हुए हैं। अब तक सभा ने लगभग ६०० ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। इन ग्रन्थों से हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों की पूर्ति हुई है।

सन् १९५३ में सभा ने अपनी हीरक जयन्ती मनाई। इस जयन्ती-समारोह का सभापतित्व भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने किया था। सभा ने अपनी इस जयन्ती के साथ हिन्दी की समृद्धि के लिए नये कार्यों को पूरा करने का संकल्प किया हिन्दी शब्द सागर का

संशोधन और परिवर्धन भी इन्हीं संकल्पों में था। अन्य शुभ-संकल्प थे—
अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों का प्रकाशन, हिन्दी साहित्य के बृहत् इतिहास
का १७ भागों में प्रणयन, हिन्दी-विश्वकोश का प्रणयन और प्रकाशन।
प्रसन्नता की बात है कि सभा के सचालक गण बड़े श्रम और लगन से इन
कार्यों को पूरा कर रहे हैं, सरकार का आर्थिक सहयोग भी सभा को प्राप्त
है। अब तक इस संकल्प के बाद एक दर्जन से अधिक हस्तलिखित ग्रन्थों का
सम्पादन और प्रकाशन हो चुका है। हिन्दी साहित्य के बृहत् इतिहास के चार
भाग—प्रथम, द्वितीय, पष्ठ और पोंडश प्रकाशित हो चुके हैं, दोष भागों का
लेखन और सम्पादन हो रहा है। हिन्दी विश्व कोश (इन साइक्लोपीडिया)
१० भागों में प्रकाशित होगा, अब तक इसके छह भाग छप चुके हैं।

‘हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली’ नाम से अंग्रेजी-हिन्दी का शब्द-संग्रह भी सभा
ने सन् १९०१-१२ में प्रकाशित किया है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशन
है। इसके सम्पादन और प्रणयन में पूर्ण विचार-विमर्श के साथ छानबीन कर
सामग्री एकत्र की गई थी। इसमें ज्योतिष, रसायन, भौतिकविज्ञान, गणित,
वेदान्त, भूगोल, अर्थशास्त्र, पुरातत्त्व आदि विषयों के शब्द संगृहीत हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सभा ने ‘राजकीय शब्दकोश’ का कार्य
भी आरम्भ किया था। बाद में सहायता न मिलने पर अर्थाभाव से उसे बन्द
कर देना पड़ा।

सभा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण काम उसका ‘आर्य भाषा-पुस्तकालय’ है।
पहले सभा के पुस्तकालय का नाम ‘नागरी भंडार’ था। १८९४ ई० में
श्रीगदाधर सिंह के अपने आर्यभाषा पुस्तकालय को सभा के लिए दान करने
पर ‘नागरी भंडार’ का नाम बदल कर ‘आर्यभाषा-पुस्तकाल’ कर दिया गया।
इसमें ५००० हस्तलिखित ग्रन्थ और ४०००० छपी पुस्तकें संगृहीत हैं। पत्र-
पत्रिकाओं का पुराना संग्रह भी पुस्तकालय में है। हिन्दी के शोधछात्र निरन्तर
इस पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं।

सन् १९५१ में सभा ने हिन्दी-मकेत लिपि का निर्माण करवाया और
उसमें परिष्कार करती रही सभा के उद्योग से प्रदेश की सर

कारों में हिन्दी-संकेत लिपि का व्यवहार होने लगा है । सभा का संकेत लिपि और टंकण का एक विद्यालय भी चलता है ।

ज्वालानपुर (हरिद्वार) में श्री स्वामी सत्यदेव ने 'सत्यज्ञान निवेदन' नाम का अपना आश्रम बनवाया था, उसको उन्होंने पश्चिमोत्तर अंचल में हिन्दी के प्रचार के लिए सभा का अर्पित कर दिया था । सभा ने वहाँ एक पुस्तकालय-भवन बनवा दिया है और स्वामी जी के उद्देश्यानुसार उसका संचालन करती है ।

आयोजन

सभा प्रति वर्ष स्वर्गीय कवि जयशंकर प्रसाद की स्मृति में एक साहित्य गोष्ठी और व्याख्यान माला का संचालन करती है ।

सभा हिन्दी के लेखकों का सम्मान करने के लिए और नूतन विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों के प्रणयन का प्रेरणा देने के लिए लेखकों को पुरस्कार और पदक प्रदान करती है । इन पुरस्कारों और पदकों की हिन्दी जगत में बड़ी प्रतिष्ठा है । पुरस्कारों के नाम ये हैं, जो अपने-अपने विभिन्न विषयों के अनुसार प्रति चौथे वर्ष दिये जाते हैं—(१) राजा बलदेवदास बिड़ला-पुरस्कार—२००) (२) बटुकप्रसाद पुरस्कार—२००) (३) रत्नाकर पुरस्कार प्रथम—२००) (४) रत्नाकर पुरस्कार-द्वितीय—२००) (५) डा० छान्दूलाल पुरस्कार—२००) (६) जोधसिंह पुरस्कार—२००) (७) माधवो देवी महिला पुरस्कार—१००) (८) डा० श्याम सुन्दरदास पुरस्कार प्रथम—१०००), द्वितीय—२००) (९) मांडलिक पुरस्कार—२००) । पदकों का विवरण इस प्रकार है—(१) डा० हीरालाल स्वर्णपदक (प्रति तीसरे वर्ष) और (२) द्विवेदी स्वर्णपदक (प्रति दूसरे वर्ष) अपने विषय के अनुसार सर्वोत्तम रचनाओं पर स्वतंत्र रूप से लेखकों को दिये जाते हैं, शेष आठ पदक रजतपदक हैं और उक्त पुरस्कारों के साथ सम्बद्ध हैं—(३) सुधाकर पदक (४) श्रीवज्र पदक (५) राधाकृष्णदास पदक (६) बलदेवदास पदक (७) गुलेरी पदक (८) रेडिचे पदक (९) वसुमति पदक (१०) भगवानदेवी बाजोरिया पदक ।

संचालन-संगठन

सभा का एक स्वन, निर्जी प्रेम—नागरी-मुद्रण और अथिति-भवन है। एक नये प्रत्य दिनाल-भवन के निर्माण की योजना है।

सभा का संचालन एक प्रबन्ध-समिति करती है। इस प्रबन्ध-समिति में ११ कार्यधिकारी और अन्य सदस्य होते हैं। प्रबन्ध-समिति ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य समितियों का निर्माण करती है। प्रबन्ध-समिति का चयन मतदान-प्रणाली से साधारण-सदस्यों द्वारा होता है। प्रबन्ध समिति में उत्तर-प्रदेश के अनिरिक्त भारत के अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि और विदेश के भी प्रतिनिधि होते हैं। देश के विभिन्न अंचलों में स्थित समानधर्मी संस्थाओं से सभा सम्बन्ध स्थापित रखती है। इस समय (१९६४ में) ऐसी ५८ संस्थाएँ सभा से सम्बद्ध हैं।

सभा का इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल रहा है। उसको सदैव योग्य और लगनवाले संचालक एवं कार्यकर्ता प्राप्त होते रहे हैं। अतः हिन्दी को प्रशस्त सेवा सभा द्वारा सतत होती चल रही है। हिन्दीवालों के लिए यह गौरव की बात है कि ७३ वर्ष पुरानी उनकी सबसे प्राचीन संस्था अब भी अपने नये रक्त से ही हिन्दी की सेवा में जुटी हुई है।

३—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अन्तर्ग हिन्दी के देश-व्यापी प्रचार-प्रसार का कार्य प्रयाग की हिन्दी साहित्य सम्मेलन—संस्था ने किया।

सन् १९०६ ई० में प्रयाग के 'अभ्युदय' पत्र में महामना प० मनदमोहन मालवीय ने कई लेख इस आशय के लिखे कि पूरे देश में हिन्दी भाषा और उसकी नागरी लिपि के प्रचार के लिए एक योजनाबद्ध कार्य का आरम्भ किया जाना चाहिए, जिससे हम भविष्य में देश की एक सर्व सम्मत राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा कर सकें। तब १० अक्टूबर १९१० को महामना मालवीय की ही उसप्रेरणा से नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने भारतीय साहित्यकारों का एक

सम्मेलन काशी में इस उद्देश्य से बुलाया कि हिन्दी तथा नागरी लिपि के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में उपयुक्त साधनों तथा प्रयत्नों पर विचार किया जाय। इसके उपयुक्त सभापति के लिए अखबारों में पहले से चर्चा भी होती रही और मालवीय जी से ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मत निवेदन किया गया। तदनुसार सम्मेलन पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में ही सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में मालवीय जी ने हिन्दी-प्रचार के उक्त कार्य के लिए वही पैसा-संग्रह किये जाने का प्रस्ताव रखा। कोश-संग्रह के लिए हिन्दी-पैसा-फंड समिति बनाई गई। कोश-संग्रह में पैसा देना वही पर लोगों ने शुरू कर दिया। हिन्दी-पैसा-फंड में शीघ्र ही २२५४६ पैसे जमा हो गये। उक्त अधिवेशन में ही सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन पं० गोविन्द-नारायण मिश्र की अध्यक्षता में प्रयाग में किये जाने का निश्चय हुआ। प्रयाग के अधिवेशन में सम्मेलन की एक नियमावली प्रस्तुत हुई, वह स्वीकार भी कर ली गई, और नियमावली के अनुसार सम्मेलन का कार्य नियमित रूप से चलने लगा। मालवीय जी के मुकाब के अनुसार, क्योंकि काशी में नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दी का कार्य कर ही रही थी, सम्मेलन का कार्यालय प्रयाग में रखा गया। इस प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की नींव पड़ी। और चन्द ही वर्षों में इसने अखिल भारतीय संस्था का रूप ले लिया।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग भारत की एक ऐसी संस्था है जो अपनी व्यापकता और लोकप्रियता में कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद दूसरा स्थान रखती थी। इसके वार्षिक अधिवेशन भारत के विभिन्न स्थानों में हुए हैं और देश के गण्यमान्य नेताओं, सामाजिक कार्य-कर्तियों तथा साहित्य-मनीषियों ने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सम्मेलन के संचालक सदैव अत्यन्त सक्रिय रहे हैं। इस कार्य में सम्मेलन का योगदान सब में अधिक है। महामना मालवीय, स्वामी अख्यानन्द, महात्मा गाँधी, पं० रामावतार शर्मा, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, डा० भगवानदास, पं० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, आचार्य पं० पद्मसिंह शर्मा अयोध्या सिंह

‘हरिऔध’, श्रीगणेश शंकर ‘विद्यार्थी’, महाराज सर सयाजीराव गायकवाड (बडौदा), डा० राजेन्द्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज, प० बाबूराव विष्णु पराडकर, डा० अमरनाथ झा, प० माखनलाल चतुर्वेदी, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, श्री जयचन्द्र विद्यालङ्कार जैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्मान्य व्यक्तियों ने सम्मेलन के अध्यक्षपद पर काम किया है।

हिन्दी-प्रचार-कार्य का एक सुव्यवस्थित सिलसिला जो सम्पूर्ण भारत में व्यापक होता गया उसका मूल श्रेय हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ही है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को सम्मेलन ने ही जन्म दिया। आज राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रचार-कार्य का क्षेत्र सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में व्यापक हो गया है। और मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा ने दक्षिण भारत में न केवल हिन्दी को लोकप्रिय बनाया है, अहिन्दी-भाषा-भाषियों में हिन्दी के विद्वान् एवं लेखक पैदा किये हैं।

एक समय था, जब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए, सम्मेलन के कार्यों में सहयोग देने के लिए जनता में अपार श्रद्धा और प्रेम था। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हिन्दी के इतिहास का एक भाग है, हिन्दी की लोकप्रियता और प्रचार कार्य का स्वर्ण-युग है।

परीक्षा-संचालन

सम्मेलन का चतुर्थ अधिवेशन सन् १९१३ में भागलपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द थे। इसमें सम्मेलन ने हिन्दी की परीक्षाएँ आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और उसकी नियमावली तैयार की गई। अगले वर्ष सम्मेलन ने तीन परीक्षाएँ शुरू की—प्रथमा, मध्यमा (विशारद), उत्तमा (साहित्यरत्न)। अन्तिम दो परीक्षाएँ उपाधि परीक्षा थी। हिन्दी-प्रेम में आकृष्ट होकर उत्साही युवक इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने लगे, उत्तर प्रदेश में तब कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता श्री कृष्णदत्त पालीवाल सम्मेलन के प्रथम साहित्य रत्न हैं। परीक्षाओं की लोकप्रियता बढ़ती रही सम्मेलन

ने इन परीक्षाओं को हिन्दी-विश्वविद्यालय का रूप दिया और इनके संचालन के लिए अलग से परीक्षा-समिति बनाई गई। परीक्षाओं का भी विस्तार हुआ, सम्प्रति सम्मेलन निम्नलिखित परीक्षाएँ लेता है—

प्रथमा, उपदेद्य, मध्यमा (विशारद), आयुर्वेद विशारद, उत्तमा (साहित्य-रत्न, विज्ञानरत्न, आयुर्वेद रत्न), कृषि विशारद, व्यापार विशारद, शिक्षा विशारद, सम्पादनकला विशारद, शीघ्र लिपि विशारद, मुनीमी अर्जनिवीसी।

इन परीक्षाओं को केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकारों ने विभिन्न मान्यताएँ दी हैं। उन मान्यताओं के अनुसार इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजकीय सेवाओं तथा शिक्षा-संस्थाओं में कार्य करने की सुविधा प्राप्त होती है प्रति वर्ष तीस हजार से अधिक परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन परीक्षार्थियों में हिंदी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त अहिन्दी भाषी प्रदेशों के—सुदूर द्रविड़ भाषी प्रदेशों के भी परीक्षार्थी होते हैं, जो बड़ी श्रद्धा से सम्मेलन की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं और दीक्षान्त-समारोह के अवसर पर उतनी दूर से प्रयाग में अपना प्रमाणपत्र लेने आते हैं।

परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का तीन वर्षों का लेखा यह है—

वर्ष	प्रथमा	मध्यमा	उत्तमा प्र० खं०	उत्तमा द्वि० खं०	अन्य विशारदादि	सम्पूर्ण संख्या
संवत् २०१७ (१९५६)	७५०७	१३६४२	५२६५	२७१५	८२६२६	३२०५५
संवत् २०१८ (१९६०)	७६२७	१४६८६	५३३१	२६०३	३३१६	३४१६६
संवत् २०१९ (१९६१)	७७५६	१४७४०	५६८५	३२३४	४२६०	३६००५

संवत् २००८ (सन् १९५०) में परीक्षार्थियों की कुल संख्या ४६२५४ थी।

सच पूछा जाय तो इन परीक्षाओं ने ही हिन्दी के प्रचार में बिजली का-सा काम किया है। परीक्षाओं के संचालन का, चतुर्थ सम्मेलन का निर्णय बहुत

ही यशस्वी प्रमाणित हुआ। इन परीक्षाओं ने हिन्दी-प्रचार और सम्मेलन के कार्य-कलाप दोनों को व्यापकता प्रदान की। आज सम्मेलन के कार्यालय का आधा हिस्सा परीक्षा-विभाग ही है।

इन परीक्षाओं के साथ सम्मेलन उत्तमा परीक्षा-उत्तीर्ण अपने हिन्दी स्नातको को उनके किसी विषय के मौलिक शोध-प्रबन्ध पर साहित्यमहोपाध्याय की उपाधि प्रदान करता है। यह उपाधि पीएच्० डी० के समकक्ष है और इसके शोध-प्रबन्ध का परीक्षण भी उसी क्रम से होता है। अब तक (१९६५ ई० तक) १५ शोधस्नातको के शोधप्रबन्ध इस उपाधि के लिए स्वीकार किये जा चुके हैं और उनको उपाधि प्रदान की गई है।

दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार की योजना

सन् १९१६ में लखनऊ राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार महात्मा गाँधी सम्मिलित हुए थे। अब तक कांग्रेस अधिवेशन की समस्त कार्यवाही और भाषण अंग्रेजी में हुआ करते थे, गाँधी जी ने बहुत विरोध करने पर भी अपना भाषण हिन्दी में किया। इसका हिन्दी-प्रचार में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। सम्मेलन के संचालको ने इससे प्रभावित होकर सन् १९१७ में इन्दौर में होनेवाले सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति महात्मा गाँधी को निर्वाचित किया। इन्दौर का अधिवेशन प्रचार-कार्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। गाँधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड भाषी प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता बताई और उस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करने की अपील की। गाँधी जी की माँग पर इन्दौर-नरेश महाराज यशवन्त राव होल्कर और नगरसेठ हनुमन्चन्द जी ने दस-दस हजार रुपये हिन्दी-प्रचार-कार्य की सहायता में दिये। इस धन का उपयोग दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार करने में किया गया। इस अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि दक्षिण भारत के कुछ युवक हिन्दी सीखने के लिए प्रयाग भेजे जायें और उत्तर भारत के

छह युवक दक्षिण की भाषाओं को सीखने तथा हिन्दी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत भेजे जायें।

सन् १९१८ में मद्रास के 'भारत सेवा संघ' (इंडियन सर्विस लीग) के हिन्दी-प्रेमी युवकों ने गाँधी जी को लिखा कि हम हिन्दी सीखना चाहते हैं, हमारे लिए एक हिन्दी-प्रचारक भेजा जाय। गाँधी जी ने अपने पुत्र श्री देवदास गाँधी को, उस समय उनकी अवस्था १८ वर्ष थी, शीघ्र ही हिन्दी-प्रचार के लिए मद्रास भेजा। श्री देवदास गाँधी ने अपने कार्य में सहयोग देने के लिए एक और व्यक्ति की माँग की, तब उनके सहायताार्थ सम्मेलन ने स्वामी मत्स्यदेव परिव्राजक को भेजा। श्री देवदास गाँधी ने मद्रास में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक कार्यालय खोल दिया और इस प्रकार वे हिन्दी-प्रचार का कार्य करते रहे। बाद में श्री हृषीकेश शर्मा और श्री हरिहर शर्मा भी दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-कार्य के लिए गये। श्री हृषीकेश शर्मा ने आन्ध्र प्रदेश में और श्री हरिहर शर्मा ने मद्रास में उक्त कार्य को किया। एक वर्ष पश्चात् जब श्री देवदास गाँधी गुजरात लौटे तब मद्रास-स्थित हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के कार्यालय का भार उन्होंने श्री हरिहर शर्मा को सौंप दिया।

सन् १९२७ तक मद्रास-स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन—प्रचार कार्यालय के नाम से ही हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम किया जाता रहा, पुनः महात्मा गाँधी की सलाह से इस प्रचार-कार्यालय का नाम दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार-सभा, मद्रास कर दिया गया। अतः १९२७ से सम्मेलन का उक्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से एक नई संस्था बन गया।

सम्मेलन ने मद्रास की भाँति हिन्दी-प्रचार के लिए एक दूसरा केन्द्र वर्धा में प्रवर्तित किया। सन् १९३६ में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का २५वाँ अधिवेशन नागपुर में देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ। उसी अधिवेशन में गाँधी जी की सलाह से हिन्दी-प्रचार-समिति वर्धा का संगठन किया गया, जिसका उद्देश्य उन चार अहिन्दी भाषी प्रदेशों को छोड़ कर जिनमें हिन्दी का प्रचार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास कर रही थी, शेष अहिन्दो

भाषी प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना निश्चित हुआ। १९३८ में इसका नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा कर दिया गया, उसकी शाखाएँ भारत के पूर्वी-पश्चिमी सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हैं और यह संस्था अब भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का ही अंग है।

हिन्दी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था

सम्मेलन ने अपने एक प्रस्ताव के अनुसार सन् १९१८ में हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग का संचालन किया था, इस विद्यापीठ में अहिन्दी भाषी प्रदेशों के युवक आकर सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का अध्ययन करते थे। इस विद्यापीठ से निष्णात होकर निकले युवक दक्षिण भारत में हिन्दी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह विद्यापीठ यमुना के दक्षिण भाग में महेवा गाँव में स्थित है और नगर के वातावरण से अलग है, इसके साथ ५२ एकड़ भूमि सम्बद्ध है। सम्मेलन के कार्य-कलाप में जो अव्यवस्था इधर के वर्षों में आ गई थी, उसके कारण यह विद्यापीठ प्रायः बन्द रहा। प्रसन्नता की बात है कि अब उसे और भी व्यापक रूप से आरंभ करने का विचार सम्मेलन कर रहा है। वैसे सम्मेलन प्रति वर्ष अगस्त से दिसम्बर तक एक साहित्य-विद्यालय चलाता है, जिसमें सम्मेलन की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। विद्यालय की व्यवस्था नगर में होती है।

हिन्दी संग्रहालय

सन् १९२२ में सम्मेलन का १३वाँ अधिवेशन कानपुर में हुआ, इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने हिन्दी का एक बृहत् संग्रहालय स्थापित करने का निश्चय किया, तदनुसार हिन्दी-संग्रहालय का आरम्भ हुआ। आज यह संग्रहालय पर्याप्त विस्तार पा चुका है। इसका एक पाण्डुलिपि कक्ष है, उसमें प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है। उसी के साथ हिन्दी-लेखकों की स्मृति-स्वरूप वस्तुएँ भी सुरक्षित हैं। एक राजर्षि टंडन जी का कक्ष है, राजर्षि टंडन के जीवन में प्राप्त राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तुओं का संग्रह इस कक्ष

मे किया गया है। स्वर्गीय मेजर वामनदास वसु द्वारा प्रदत्त इतिहास की ४७८६ पुस्तकें संग्रहालय में अलग से रखी गयी हैं, ये अंग्रेजी और बंगला भाषा में हैं। सम्मेलन हिन्दी में प्रकाशित सभी मौलिक पुस्तकों को क्रय कर संग्रहालय में रखता है, हिन्दी में प्रकाशित महत्व के समाचार पत्र और पत्रिकाएँ भी नियमित रूप से संग्रहालय में आती हैं और उनकी फाइल रखी जाती है। इस समय (१९६६ में) संग्रहालय में ४३८६० मुद्रित पुस्तकें और लगभग ८००० हस्तलिखित पोथियाँ हैं। संग्रहालय का अलग से विशाल भवन है। संग्रहालय के साथ एक पुस्तकालय भी सम्बद्ध है जहाँ से उसके सदस्यों को पढ़ने के लिए पुस्तकें बाहर निर्गत की जाती हैं। पुस्तकालय में लगभग दस हजार पुस्तकें हैं, संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि होती रहती है।

हिन्दी और हिन्दुस्तानी के मतभेद पर सम्मेलन के निर्णय (१९३८-१९४६)

सन् १९३४ में सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन के महात्मा गाँधी पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तब तक हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्रगति प्रगति हो चुकी थी। सन् १९३६ के नागपुर अधिवेशन में उन्हीं की प्रेरणा से हिन्दी प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में की गयी। परन्तु कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा हिन्दू-मुसलिम एकता के प्रति अधिक जागरूक हो रही थी और उसका यह भी विचार था कि हिन्दी के स्थान पर राष्ट्रभाषा को हिन्दी-उर्दू-मिश्रित शैली का 'हिन्दुस्तानी' रूप देने से उक्त एकता में एक और कड़ी जुड़ सकती है। गाँधी जी का ध्यान इस ओर अधिक था, फलतः उन्होंने हिन्दुस्तानी का समर्थन किया। सम्मेलन हिन्दुस्तानी का समर्थक नहीं था। अध्यक्ष होने के नाते वे सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य थे। हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रश्न को लेकर गाँधी जी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भी मतभेद हो गया और उन्होंने सन् १९४४ में सम्मेलन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। सन् १९४२ में ही उन्होंने हिन्दुस्तानी-प्रचार-समिति की स्थापना करवा दी थी।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप को लेकर सम्मेलन ने अपने अधिवेशनों में समय-समय पर जो निर्णय किये हैं, वे उक्त प्रश्न के ऐतिहासिक अनुशीलन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। नीचे शिमला (१९३८), पूना (१९४०), अंबाहर (१९४१) और उदयपुर (१९४५) के निर्णयों का प्रमुख अंश दिया जा रहा है, इन अंशों को पढ़ कर हम अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार सम्मेलन का दृष्टिकोण पहले उदारवादी था, वह हिन्दी को फारसी लिपि में लिखे जाने का तथ्य भी स्वीकार कर रहा था परन्तु राजनीतिक विवादों में उसका उदारवादी दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया और उसने इस आशका में, कि कहीं उर्दू तथा हिन्दुस्तानी के पीछे हमारे उच्च दृष्टिकोण का लाभ उठा कर उर्दू भाषा और फारसी लिपि ही राष्ट्रभाषा के पद को आत्मसात् न करने लगे, अपना खरा निर्णय किया एवं राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर एक निश्चित नीति निर्धारित की—

“इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी के आधुनिक साहित्य-निर्माण के लिए ऐसी भाषा उपयुक्त है जिसका परम्परागत सम्बन्ध संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से है जिसकी शक्ति कबीर, तुलसी, सूर, मलिक मुहम्मद जायसी, रहीम, रसखान और हरिश्चन्द्र की कृतियों से आई है, जिसका मूल-धार देशी और लघु-शब्दों का भंडार है और जिसके पारिभाषिक शब्द प्राकृत अथवा संस्कृत के क्रम पर ढाले गये हैं; किन्तु जिसमें रूढ़, सुलभ और प्रचलित देशी शब्दों का भी स्थान है।” (शिमला-अधिवेशन, १९३८)

“इस सम्मेलन को मालूम हुआ है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रांतों में कुछ गलत-फहमी फैली हुई है, और लोग इनके लिए अलग-अलग राय रखते हैं। इसलिए यह सम्मेलन घोषित करता है कि राष्ट्रभाषा की दृष्टि में हिन्दी का वह स्वरूप मान्य समझा जाय, जो हिन्दू, मुसलमान आदि सब धर्मों के ग्रामीण और नागरिक व्यवहार करते हैं, जिसमें रूढ़ सर्वसुलभ अरबी, फारसी या अंग्रेजी शब्दों या मुहावरों का बहिष्कार नहीं होता और जो साधारण रीति से राष्ट्रलिपि नागरी में तथा फारसी लिपि में लिखा जाना है।” (पूना-अधिवेशन, १९४०)

“प्रारम्भ में ही सम्मेलन ने अपनी भाषा, और राष्ट्रभाषा को हिन्दी कहा है और भाषा तथा नागरी लिपि की उन्नति और प्रचार ही उसका उद्देश्य रहा है। द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में जो पहिली नियमावली प्रयाग में स्वीकृत हुई उसमें तथा उसके पश्चात् अब तक जितने भी संशोधन उस नियमावली में हुए हैं उन सबमें यह प्रकट है कि सम्मेलन की भाषा का नाम हिन्दी है—यद्यपि साहित्यिक अथवा प्रचार की दृष्टि में, और स्थानों की विभिन्नता के कारण, उसके रूप में शब्दावली का कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है।

×

×

×

“उर्दू को साहित्यिक शैली, जो गाँडे में आदमियों में सीमित है, हिन्दी में इस समय इतनी विभिन्न हो गई है कि इसकी पृथक् स्थिति सम्मेलन स्वीकार करता है और हिन्दी की शैली से भिन्न मानता है।

“हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग मुख्यकर इसलिए हुआ करता है कि वह देशी शब्द-व्यवहार से प्रभावित हिन्दी शैली तथा अरबी-फारसी शब्द-व्यवहार में प्रभावित उर्दू शैली दोनों का एक शब्द ने एक समय में निर्देश करे।

×

×

×

“इस प्रकार निश्चित अर्थों में उर्दू और हिन्दुस्तानी शब्दों का प्रचलन है। इस विषय में सम्मेलन का कोई विरोध नहीं है, किन्तु सम्मेलन साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से अपने और अपनी समितियों के काम में हिन्दी शैली का और उसके लिए हिन्दी शब्द का ही व्यवहार और प्रचार करता है।”

(अबोहर-अधिवेशन, १९४१)

“महात्मा गाँधी के इस मत से कि प्रत्येक देशवासी नागरी और फारसी दोनों लिपियाँ सीखे, सम्मेलन सहमत नहीं हो सकता। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सम्मेलन इस मत को नितान्त अव्यावहारिक तथा अग्राह्य समझता है। केवल नागरी लिपि में राष्ट्र लिपि होने की योग्यता है यम”

है, देश की बहुत बड़ी जन-संख्या ऐसी लिपियों का व्यवहार करती है जो नागरी लिपि के बहुत समीप है और उसके लिए नागरी सीखना अति सुगम है। यह मानी हुई बात है कि फारसी लिपि का आधार वैज्ञानिक नहीं है, सीखने में वह कष्ट-माध्य है। हमारे देश में साक्षरता की कमी है। अपनी प्रान्तीय लिपि के साथ दो अन्य लिपियाँ सीखना माधारण जनता के लिए संभव नहीं।

“सम्मेलन की दृष्टि पूर्ण रूप से राष्ट्रीय है। देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ सम्मेलन चलता आया है और चलना चाहता है और भाषा और लिपि के प्रश्न पर साम्प्रदायिक दृष्टि से विचार करना अनुचित समझता है।”

(उदयपुर-अधिवेशन, १९४५)

हिन्दी-हिन्दुस्तानी का यह विवाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए सन् १९३७ से ही विशेष आकृष्ट कर रहा था जब पहली बार प्रान्तों में कांग्रेस की मर-कार बनी थी। विवाद राष्ट्रभाषा के स्वरूप का कम, राजनीतिक पहलुओं का ही अधिक था, राजर्षि टंडन जी ने इस विवाद में हिन्दी के मही स्वरूप के प्रति दृढ़ रुख अपनाया था। सन् १९४४ के सम्मेलन के जयपुर अधिवेशन में इस विवाद की पूरी चर्चा हुई। इस अधिवेशन के एक निश्चय के अनुसार ही रेडियों की भाषा-नीति में हिन्दी के हिन्दुस्तानी स्वरूप के कारण साहित्य-कारों ने रेडियों का बहिष्कार किया, इस बहिष्कार का अच्छा प्रभाव पड़ा। सन् १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इस विवाद को और भी उधर कर सामने आना पड़ा। और जब भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा हिन्दी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का भी बहुमत रहा तब हिन्दी का स्वरूप क्या हो, इसका निर्णय करना आवश्यक हो गया।

राष्ट्रभाषा के पक्ष में हिन्दी का निर्णय लिए जाने का महत्वपूर्ण कार्य सम्मेलन के मेरठ अधिवेशन (सन् १९४८) के बाद सन् १९४९ में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रभाषा-व्यवस्था-परिषद् में हुआ, यह आयोजन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्मिलित प्रयास से किया गया था। राष्ट्रभाषा के

सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए यह परिषद् अहिन्दी-भाषी विद्वानों और राष्ट्रीय सेवा के प्रमुख स्तम्भों की थी। परिषद् ६-७ अगस्त १९४६ को श्री एन्० एन्० गोडबोले की अध्यक्षता में हुई और इसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में निर्णय हुआ, यह बड़ी ही सुखद घटना थी, क्योंकि निर्णय करनेवाले अहिन्दी भाषा-भाषी थे। आयोजन का सर्वाधिक श्रेय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को था। सम्मेलन ने उस समय अपनी 'सम्मेलन पत्रिका' का 'राष्ट्रभाषा विशेषांक' प्रकाशित किया था।

राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में हिन्दी के पक्ष में निर्णय हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में हिन्दी के स्वरूप को लेकर हिन्दी-विरोधी पक्ष ने विवाद खड़ा किया। यह विवाद हिन्दी और हिन्दुस्तानी का था। इस विवाद का निपटारा १२-१४ सितम्बर १९४६ की संविधान-परिषद् की ऐतिहासिक बैठक में हुआ। जिसमें अन्ततः बहुमत ने हिन्दी का समर्थन किया। माननीय जवाहरलाल जी नेहरू हिन्दुस्तानी के समर्थन के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहे पर वैसा सम्भव न हुआ। हाँ, एक निर्णय हिन्दी के विपरीत हुआ, नागरी अंको के स्थान पर रोमन अंको के प्रयोग की ही बात स्वीकार की गई, साथ ही पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी में ही कार्य करने का निर्णय लिया गया, तब तक हिंदी को इस योग्य बनाने की बात रक्खी गई, जिससे उसमें प्रशासन के सारे कार्य किये जा सकें।

संविधान-परिषद् के उक्त निर्णय के विरोध में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने अपनी स्थायी समिति की २८-२९ सितम्बर १९४६ की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, और उसकी प्रति संविधान-परिषद् को भेजी। उस प्रस्ताव का प्रमुख अंश नीचे है—

“(क).....यह समिति सम्पूर्ण निर्णय को देखते हुए, उससे अपना अमन्तोष प्रकट करती है और संविधान-परिषद् को यह सूचना देना चाहती है कि देवनागरी लिपि का अंग्रेजी अंको द्वारा विरूपण देश की जनता को कदापि स्वीकार न होगा। संविधान परिषद् से समिति का निवेदन है कि संविधान की अन्तिम स्वीकृत से पहले वह एक सम्बन्धी अपने

निर्णय को परिवर्तित करे। अंग्रेजी भाषा के चलने का समय भी अधिक सीमित करे।

“(ख) सब से अधिक अनर्गल और अनधिकृत निर्णय संविधान-परिषद् का यह हुआ है कि देवनागरी लिपि में प्राचीन देवनागरी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों का उपयोग किया जाय, जिसको उसने भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप देकर अपने निर्णय के दोष को छिपाने का प्रयत्न किया है।”

सचमुच सम्मेलन इतना शक्त संगठन था कि वह संविधान-परिषद् को, आज नहीं तो कल उसके निर्णय को बदलने के लिए बाध्य करता, किन्तु म्वय उसका अपना गठन गतिरोध की जिस भूमिका में पहुँच रहा था, उसके कारण संविधान-परिषद् का वह निर्णय आज (१९६६ में) भी ज्यों का त्यों बना है। सम्मेलन में उसके सन् १९५० के चुनाव के बाद ही गतिरोध के काले बादल छा गये, आगे उसका विवरण दिया जा रहा है।

वार्षिक अधिवेशन

सम्मेलन का संगठन और संचालन आरंभ से ही जनतांत्रिक प्रणाली पर होता रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा स्थायी समिति संगठित की जाती थी, स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या प्रायः दो सौ के लगभग रहा करती थी। पुनः स्थायी समिति कार्य समिति एवं अन्य समितियों का निर्माण करती थी। प्रत्येक वर्ष यह निर्वाचन हुआ करता था, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों—प्रधान मंत्री, प्रवन्ध मंत्री, परीक्षा मंत्री, प्रचार मंत्री, साहित्य मंत्री, अर्थ मंत्री, सग्रह मंत्री और राष्ट्रभाषा प्रचार मंत्री—का निर्वाचन भी प्रत्येक वर्ष होता था। नया अध्यक्ष ही प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन को संचालित करता था और पूरे वर्ष भर सम्मेलन के उत्थान तथा हिन्दी के अभ्युदय, प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक समुचित प्रयास एवं कार्य-संचालन करता था।

वार्षिक अधिवेशन के समय अन्य विषयों की परिषदें भी आयोजित की जाती थी जैसे—साहित्य परिषद्, राष्ट्रभाषा परिषद्, दर्शन परिषद्, समाज

शास्त्र परिषद्, विज्ञान परिषद् । इन परिषदों की अध्यक्षता उनके विषय के विख्यात अधिकारी विद्वान् किया करते थे ।

सम्मेलन के अधिवेशनों में बड़े उल्लास के साथ देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । और अधिवेशन में हिन्दी के उत्थान के लिए किये गये निर्णयों का सभी हृदय से स्वागत करते थे । इस वातावरण का हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता था । सम्मेलन का अन्तिम अधिवेशन दिसम्बर सन् १९५० में कोटा में हुआ, उसके अध्यक्ष प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं० जयचन्द्र विद्यालंकार थे ।

सम्मेलन में गतिरोध

सन् १९५० के बाद सम्मेलन के संगठन और संचालन में नियमावली के प्रश्न को लेकर गतिरोध पैदा हो गया । यह गतिरोध सम्मेलन और हिन्दी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ । नियमावली के प्रश्न ने न्यायालय में विवाद का रूप ले लिया । कटुता इतनी बढ़ गई कि न्यायालय की ओर से एक आदेश सम्मेलन की देख-रेख के लिए निगुप्त हुआ । आजादी के बाद ठीक उस समय जब कि सरकार द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहृत कराने-हेतु अथक प्रयासों की आवश्यकता थी, सम्मेलन की यह पंगुता हिन्दी के लिए अन्धकार का युग था । कहा यही जाना चाहिए कि हिन्दी-प्रेमी और सम्मेलन के कर्णधार ही इसके लिए दोषी थे ।

सम्मेलन के इस गतिरोध की पूर्व भूमिका इसके बम्बई-अधिवेशन (१९४७ ई०) में आरम्भ होती है । सम्मेलन का यह दुर्भाग्य था कि गतिरोध की उक्त भूमिका में उसके प्रमुख कर्णधार राजर्षि बाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन भी अपने को अलग न रख सके, बल्कि एक पार्टी बन गये । बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष महापंडित राहुल सांकृत्यायन और प्रधान मंत्री के निर्वाचन में ही सम्मेलन के सदस्यों में खुल कर दो पक्ष हो गये । बात यह थी कि बम्बई अधिवेशन के पूर्व विगत दस वर्षों से सम्मेलन की रीति-नीति राजर्षि टंडन जी से ही प्रेरित होती थी १९४७ ई० में मिलने के बाद

जनतंत्र की प्रकृति ने साहित्यकारों को सम्मेलन के संचालन में बहुमत-सम्मति रीति-नीति के लिए आगे किया। यद्यपि इस प्रकार के प्रश्न उस समय भी पैदा हुए, ये जब अधोहर-अधिवेशन (सन् १९३९) में देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद राजर्षि टंडन जी की इच्छा के विरुद्ध सम्मेलन के सभापति न निर्वाचित हो सके तथापि हिन्दो के हितों को देखते हुए वे प्रश्न उसी समय विलीन हो गये थे, १९४७ ई० के बाद जनतंत्र के नीतिगत विचारों ने सम्मेलन के संचालन में जो करवट ली, तो राजर्षि टंडन जी की नीतियों को सम्मेलन में यथावत् भौत स्वीकार कर लेने की परम्परा टूट गई। राजर्षि टंडन जी का पक्ष अल्पमत में होता गया और इस अल्पमत को उस समय बहुत अधिक निराशा हुई, जब कोटा-अधिवेशन (१९५० ई०) के अध्यक्ष श्री जयचन्द्र विद्यालङ्कार निर्वाचित हुए। उसके बाद ही सम्मेलन की नियमावली के प्रश्न को लेकर उत्पन्न विवाद न न्यायालय की शरण ली और सन् १९५१ में न्यायालय द्वारा सम्मेलन का संचालन एक आदाता को सौंपा गया।

सम्मेलन की नई नियमावली का प्रश्न भी ऐसा था, जो उसके अब तक के नियम और जनतांत्रिक संचालन को सर्वतः उनट देनेवाला था। इस नई नियमावली के समर्थक राजर्षि टंडन जी भी थे, उससे पुनः नये कार्यकर्ताओं को सम्मेलन की सेवा का अवसर बहुत कम रह जाता। जनतंत्र के युग में ऐसा सम्भव नहीं था। वह नियमावली बहुमत से स्वीकार न हो सकी, इसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन पटना में (३० जून १९५० में) बुलाया गया। पर उस अधिवेशन में कोई सही हल सामने न आ सका, जिससे इस विवाद का अन्त होता।

नियमावली का वही प्रश्न न्यायालय में उपस्थित हुआ। न्यायालय के निर्णयों के लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब तक सम्मेलन निष्क्रिय हो रहा था जब कि उसे अत्यन्त क्रियाशील होने की आवश्यकता थी। आदाता से सम्मेलन की रक्षा तो हो रही थी, पर वह अकेला व्यक्ति इस अश्विल भारतीय संस्था का संचालन क्या करता? सम्भवतः इस परिस्थिति का अनुभव राजर्षि टंडन और दूसरा पक्ष दोनों कर रहे थे। अतः समझौता-वास्त

का प्रयत्न शुरू हुआ, पर वार्ता सफल न हुई। अन्ततः राजर्षि टंडन ने उत्तर प्रदेश की सरकार को अनेक हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थना पत्र देकर उम्मत सन १९५८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए एक विधेयक पारित करवाया। दूसरे पत्र ने उच्च न्यायालय में विधेयक के विरुद्ध अपील कर दी और सन् १९५९ में विधेयक उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। सम्मेलन की निष्क्रियता वैसी ही चलती रही, इधर राजर्षि टंडन जी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, वे सम्मेलन के लिए अत्यन्त चिन्तित रहने लगे। पुनः उन्होंने केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-विभाग को एक प्रार्थना पत्र भिजवाया, जिसमें लगभग ढाई सौ हिन्दी-प्रेमियों और सम्मेलन के पुराने हितैषियों के हस्ताक्षर थे, उसमें भारत सरकार से हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पुनर्गठन और संचालन के हेतु विधेयक बनाने का विनीत आग्रह किया गया। इसके पूर्व (१९६१ में) उच्च न्यायालय प्रयाग ने सम्मेलन के नियमावली-सम्बन्धी विवाद पर अपना निर्णय दे दिया और पुरानी नियमावली को मान्यता दे दी थी। आदाता महोदय जब उस नियमावली के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर चुनाव कराने जा रहे थे तब भारत सरकार से विधेयक बनाने के लिए प्रार्थना की गई। फलतः मार्च १९६२ में पुरानी लोक सभा की अन्तिम बैठक ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन का विधेयक (अधिनियम सं० १३) पारित कर दिया गया। विधेयक के द्वारा पन्द्रह व्यक्तियों का एक प्रथम शासन निकाय बना, जो सम्मेलन की नई नियमावली बना कर और उसके अनुसार नया चुनाव करा कर समाप्त हो जायगा। सम्भवतः उस समय ऐसी आशा थी कि नई नियमावली छह महीने में बन जायगी और एक वर्ष के भीतर नया चुनाव हो जायगा। परन्तु (१९६६ में) चार वर्ष हो गये, अभी प्रथम शासन निकाय बना है, उसके दो अध्यक्ष और तीन सचिव बदल चुके। सम्मेलन नये चुनाव की आशा में निष्क्रिय बना बैठा है। राजर्षि टंडन जी जब रोग-शय्या पर थे तब प्रथम शासन निकाय की बैठक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भवन में हुई थी, उसकी कार्रवाई अंग्रेजी के माध्यम से हुई थी, कदाचित् राजर्षि टंडन जी के लिए यह उससे भी अधिक कष्टकर बात थी, जो दो दलों के संघर्ष के बीच सम्मेलन का

जनतांत्रिक संचालन हो रहा था। विधेयक में सम्मेलन के कार्यों में रोमन अक्षरों के व्यवहार की ही बात कही गई है, जो भारत सरकार की भाषा-नीति है। राजपि टंडन जो ने इसको हटाने के लिए उसी समय भारत सरकार का लिखा था। इसी बीच १ जुलाई मन् १९६२ को ही टंडन जी की मृत्यु हो गयी।

अन्य आयोजन

सम्मेलन हिन्दी की मौलिक उच्च कोटि की कृतियों पर पुरस्कार देकर हिन्दी के लेखकों को सम्मानित करना है। उन पुरस्कारों के नाम ये हैं—

१—ममला प्रसाद पारितोषिक (प्रति वर्ष) १२००) २—सेकसरिया महिला पुरस्कार ५००), ३—मुरारका पुरस्कार ५००) ४०, ४—राधामोहन गोकुल पुरस्कार २५०) २५०, और ५—रत्नकुमारी पुरस्कार २५०) २५०।

ये पुरस्कार अपने निदिष्ट विषय की पुस्तकों पर नियुक्त की गई पुरस्कार-समिति के निर्णय के अनुसार दिये जाते हैं। हिन्दी-जगत में इन पुरस्कारों के प्रति बड़ा सम्मान-भाव है।

सम्मेलन उच्चकोटि के विद्वानों को अपने कार्य समिति ने प्रस्तावित निर्णय के अनुसार 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि देकर उनको सम्मानित करता रहा है। यह उपाधि तात्पर्य पर अंकित करा कर वार्षिक अधिवेशन के समय अथोचित अर्चना-पूर्वक दी जाती है।

सम्मेलन प्रतिवर्ष सुप्रसिद्ध हिन्दी-कवियों की जयन्तियाँ मनाता है। विदेशों से अथवा हिन्दी-विद्वानों के सम्मानार्थ अथवा ऐसे ही अन्य अवसरों पर सभाएँ आयोजित किया करता है।

सम्मेलन के कार्य-विभाग

मुख्य रूप से सम्मेलन के कार्यकलाप के दो भाग हैं—१—कार्यालय, २—मुद्रणालय। सम्मेलन के मुद्रणालय की गिनती हिन्दी के उच्च कोटि के प्रेसों में की जाती है। यह मुद्रणालय पूर्ण साधन-सम्पन्न और सुव्यवस्थित है। कार्यालय के विभाग हैं—

१—प्रबन्ध विभाग, २—परीक्षा विभाग, ३—साहित्य विभाग, ४—संग्रहालय, ५—प्रचार विभाग, ६—अर्थ विभाग ।

परीक्षा विभाग के सम्बन्ध में पहले विस्तार से कहा जा चुका है । दूसरा महत्त्वपूर्ण विभाग साहित्य विभाग है । इस विभाग द्वारा महत्त्वपूर्ण विषयों की पुस्तकों का निर्माण, सम्पादन, पुस्तकों का प्रकाशन और पुरानी हस्त लिखित दुर्लभ गोथियों का प्रकाशन होता है । साहित्य विभाग द्वारा शासन और वैज्ञानिक-शिक्षण के कार्य में हिन्दी के व्यवहार को सुलभ बनाने के लिए योजना-बद्ध कोशों का निर्माण और प्रकाशन हुआ है । अब तक ऐसे पाँच काश प्रकाशन हो चुके हैं—शासन शब्द कोश, प्रत्यक्ष शरीर कोश, जीव रसायन कोश, भूतत्त्व विज्ञान कोश और चिकित्सा कोश । (गौरी शंकर हीरा चन्द—) ओम्ना—अभिन्दन ग्रन्थ के रूप में 'भारतीय अनुशीलन' नाम से एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन सम्मेलन ने सन् १९३४ में किया था । सम्मेलन के साहित्य विभाग ने अब तक लगभग २०० पुस्तकों का प्रकाशन किया है । साहित्य विभाग से 'सम्मेलन पत्रिका' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसमें उच्च कोटि के शोध-पूर्ण, गवेषणात्मक और अनुशीलनात्मक लेख प्रकाशित होते हैं । सम्मेलन-पत्रिका के पाठक देश और विदेश में हैं । इस पत्रिका का आरम्भ सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन के परीक्षा-संचालन के निर्णय के साथ हुआ था । इसका प्रथम अंक आश्विन शुक्ल १० सवत् १९७० (मन् १९१३) में प्रकाशित हुआ । पहले यह पत्रिका मासिक थी, बाद में त्रैमासिक कर दी गई और इसमें शोध-पूर्ण लेख-सामग्री का प्रकाशन होने लगा ।

सम्मेलन सम्प्रति दो और पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है—राष्ट्रभाषा सन्देश (पाक्षिक) और माध्यम (मासिक) । इनमें पहला पत्र हिन्दी के प्रचार-प्रसार में गति लाने के लिए प्रकाशित किया जाता है और दूसरा साहित्यिक मासिक है ।

सम्मेलन के पास कार्यालय और मुद्रणालय के लिए अलग-अलग भवन हैं । और साहित्यिक अतिथियों के ठहरने के लिए कविरत्न सत्यनारायण का स्मृति में निर्मित 'तुलसी कुटीर' नाम की एक अतिथिशाला है ।

अंगभूत सस्थऐं

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा सम्मेलन का प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त भी प्रादेशिक सम्मेलन तथा अन्य संस्थाएँ सम्मेलन में अपने को सम्बद्ध रखती हैं। उनके प्रतिनिधि वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुआ करते थे और स्थायी समिति के संगठन में स्थान पाते थे। इन संस्थाओं में मुख्य हैं— उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१९२१), दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१९४४), बंग प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बम्बई राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन, विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन नागपुर (१९१९), बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१९१९), मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर, हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, भारतेन्दु समिति कोटा, मध्यभारतीय हिन्दी साहित्य सभा ग्वालियर, बागड प्रदेश-साहित्य परिषद् डूंगरपुर (राजस्थान)।

४—दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार की योजना को लक्ष्य कर १९१८ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का सूत्रपात मद्रास में हिन्दी-साहित्य—सम्मेलन के प्रचार-कार्यालय के रूप में हुआ था, इस सूत्रपात की कहानी पीछे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इतिहास में विस्तार से आ चुकी है। १९२६ में गाँधी जी की सलाह में इस प्रचार कार्यालय को दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का नाम दिया गया और इसका मविधान बना कर इसे स्वतंत्र रूप में संगठित किया गया। महात्मा गाँधी इसके आजीवन अध्यक्ष चुने गये और मद्रास के प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक 'हिन्द' के सम्पादक श्री ए० रंग स्वामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष। आठ प्रचारको काण्क दल योजना-बद्ध हिन्दी के प्रचार-कार्य में अग्रसर हुआ, जिसमें ५० हरिहर अर्मा, श्री जोट्टारि सत्यनारायण, ५० रघुवरदण्डु मिश्र, ५० देवदूत विद्यार्थी, ५० अवधनन्दन, श्री एस० रामचन्द्र शास्त्री श्री पी० सुब्बाराव और श्री दामोदर उप्पा थे

इस प्रकार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास का स्वतंत्र संस्था के रूप में वास्तविक अस्तित्व १९२७ से हुआ।

सभा को जिन राजनीतिक और सामाजिक नेताओं का सहयोग समय-समय पर मिलता रहा है उनमें प्रमुख हैं—~~स्वर्गीय~~ श्री सत्यमूर्ति, डा० गृहार्थि सीतारामैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री नागेश्वर राव पन्तुलु, श्री के० भाष्यम, श्री रामदास पन्तुलु, श्री मंजीव कामन और श्री जगन्नाथ दास। आरम्भ से सन् १९३६ तक प० हरिहर गार्गी सभा के प्रधान मन्त्री रहे हैं। उनके बाद श्री मोटूरि सत्यनागप्प ने प्रधान मन्त्री का कार्य संभाला। सन् १९६० से श्री एस्० आर्० शम्शरी सभा के प्रधान मन्त्री हुए। दक्षिण भारत में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का येय इस सभा को है। इसका कार्य-क्षेत्र मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और केरल प्रदेश अर्थात् तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा-भाषी प्रदेश रहे हैं।

कार्य और प्रगति—

कार्यकर्ताओं (प्रचारकों) का निर्माण और हिन्दी प्रचार-विद्यालय

सभा ने मद्रास के बाहर हिन्दी का प्रचार-कार्य सन् १९२१ से ही आरम्भ किया। उसने इस कार्य के लिए अहिन्दी भाषियों को ही हिन्दी की शिक्षा दे कर लियुक्त किया। १९२२ से सभा के द्वारा परीक्षाओं का आरम्भ होने पर इस कार्य में बड़ी तीव्रता आई। और आज सभा के ७००० हिन्दी-प्रचारक दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रशिक्षण और प्रचार में संलग्न हैं।

हिन्दी की सेवा के लिए सुशोध्य प्रचारकों के निर्माण की योजना का आरम्भ १९२१ से होता है। हिन्दी की शिक्षा के लिए उस वर्ष दो विद्यालय खोले गये—पहला आन्ध्र में, गोदावरी के तट पर राजमहेन्द्री के पास धक्-लेखरम् नामक स्थान में और दूसरा तमिलनाडु में, कावेरी के तट पर ईरोड नामक स्थान में। ये दोनों विद्यालय एक वर्ष तक चले और इनमें शिक्षित युवक हिन्दी के प्रचार में लग गये। प्रचारकों की माँग बढ़ने पर १९२४-२५ में मद्रास में एक विद्यालय संचालित हुआ, जिसमें दक्षिण भारत के सभी भागों के

विद्यार्थी हिन्दी-शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए तथा पढाई पूरी करने के बाद हिन्दी के प्रचार में जुट गये । इस समय सभा मद्रास, तिरुचिरापल्ली और हैदराबाद तीन स्थानों में हिन्दो-प्रचारक विद्यालय चलाती हैं । राजमहेन्द्री और तेनाली के हिन्दी-प्रचारक विद्यालय भी सभा से मान्यता-प्राप्त हैं ।

प्रचार-कार्य की प्रगति

प्रचारको की संख्या बढ़ने के साथ प्रचार-कार्य भी बढ़ता गया । आन्ध्र के गाँवों में भी लोग हिन्दी पढने की ओर उन्मुख हुए । बहुत ही शीघ्र तिरु-वनतपुरम, एरणाकुलम, मंगलोर, कालिकट, मद्रास, तंजौर, कुम्भकोणम, बंगलोर, मैसूर, हुबली, वेलगाँव, चित्तूर, बेजवाड़ा, गुण्टूर आदि नगर हिन्दी-प्रचार के केन्द्र हो गये । १९३२ के बाद हाई स्कूल में हिन्दी का प्रवेश हुआ और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हिन्दी-पढाई की व्यवस्था होने लगी । १९३५ में काका कालेलकर जी ने हिन्दी-प्रचार-कार्य को महयोग देने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की । उन्होंने शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव देने के लिए सभा के अन्तर्गत एक शिक्षा-परिषद् का गठन किया । और हिन्दी प्रचार-कार्य को सुगठित करने के लिए सभा की अग्रभूत प्रान्तीय सभाओं की स्थापना की । इन प्रान्तीय हिन्दी-प्रचार सभाओं के कार्यालय बेजवाड़ा (आन्ध्र), तिरु-चिरापल्ली (तमिल), एरणाकुलम (केरल) और बंगलोर (कर्नाटक) में स्थापित हुए । बंगलोर का कार्यालय अब धारवाड में है । इनके प्रान्तीय मंत्री क्रमशः पी० मुब्बाराव, रघुवरदायानु मिश्र, देवदत्त विद्यार्थी तथा सिद्धनाथ पन्त नियुक्त हुए । इधर सभा की एक शाखा दिल्ली में भी स्थापित हो गई है । इस प्रकार पाँच प्रान्तीय सभाएँ, केन्द्रीय सभा-मद्रास से सम्बद्ध होकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसकी लोक-प्रियता को बढ़ाने में आज कार्य कर रही हैं—

१. तमिलनाडु हिन्दी प्रचार-सभा ।
२. आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार-संघ ।
३. कर्नाटक हिन्दी प्रचार-सभा

४. केरल हिन्दी प्रचार-सभा ।

५. सभा की दिल्ली-शाखा ।

१९३२ में 'ज्ञानयात्री मण्डल' तथा १९३४ में 'यात्री दल' स्थापित हुआ । पहले के सस्थापक श्री सिद्धनाथ गन्त थे । 'ज्ञानयात्री मण्डल' के सदस्यों ने उत्तर भारत के प्रमुख हिन्दी-विद्या-केन्द्र प्रयाग, काशी आदि स्थानों में जा कर हिन्दी-साहित्य का उच्चस्तरीय अध्ययन किया । और तब दक्षिण भारत लौटने पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उनको अधिक सफलता मिली । 'यात्री दल' के लोगो ने उत्तर भारत में आकर दक्षिण भारत की भाषाओं, वहाँ हिन्दी के प्रति प्रेम और संस्कृति के सम्बन्ध में जानकारी दी । सन् १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में जब नेता तथा कार्यकर्ता जेलों में बन्द कर दिये गये तब वहाँ जेलों में भी उन्होंने हिन्दी का प्रचार किया ।

१९५० तक दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रवेश हो गया । केरल तथा आन्ध्र के स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने लगी, इसलिए हिन्दी अध्यापकों की माँग बढ़ी । इसकी पूर्ति के लिए मद्रास की केन्द्रीय सभा ने आन्ध्र, मद्रास, केरल, मैसूर प्रदेशों के अपने प्रमुख हिन्दी-प्रचार-केन्द्र के नगरों में हिन्दी के विद्यालय संचालित किये ।

हिन्दी-प्रचार के लिए पाठ्य-पुस्तकें

प्रारम्भ में जब इन प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार का कार्य शुरू हुआ तब हिन्दी पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तकों का अभाव सामने आया । सन् १९२३ में सेठ जमुनालाल बजाज ने 'हिन्दी-प्रचार-श्रेंस' एक छापाखाना का प्रबन्ध किया । जिसमें प्रचार-कार्य के अनुकूल पुस्तकों के निर्माण तथा प्रकाशन की सुविधा प्राप्त हुई । श्री हरिहर शर्मा तथा श्री क० म० गिराराम शर्मा ने सबसे प्रथम 'हिन्दी-स्वबोधिनी' पुस्तक तैयार की, यह पुस्तक तमिल तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से थी । प० हृषीकेश शर्मा ने तमिल भाषा में 'स्वबोधिनी' तैयार की । इनके ही आधार पर कन्नड और मलयालम में भी 'स्वबोधिनी' तैयार

की गई। इन पुस्तकों से हिन्दी के प्रचार-कार्य में बड़ी सहायता मिली। बाद में आवश्यकतानुकूल इनका संशोधन और परिवर्धन हुआ। पुनः प्रचार-कार्य में प्रगति तथा परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ नई पाठ्य पुस्तकों नैवार हुई।

परीक्षा-संचालन

परीक्षाएँ प्रचार-कार्य का सफल माध्यम रही हैं। सभा ने प्रचार-कार्य के अनन्तर ही सन् १९२२ से हिन्दी-परीक्षाओं का संचालन प्रारम्भ किया। प्रचार-केन्द्र परीक्षाओं के केन्द्र का भी काम करने लगे।

सन् १९३० तक परीक्षाओं की प्रगति बहुत धीमी रही, तब तक केवल ७५ केन्द्रों में परीक्षाएँ होती थी तथा इसी वर्ष की अवधि में प्रारम्भिक परीक्षाओं में ६११६ तथा उच्च परीक्षाओं में ३२ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। सन् १९३५ में केन्द्रों की संख्या ३६४ हो गई, सन् १९४० में ५७८, सन् १९५० में ७४०, सन् १९५५ में १०६४ और १९६० में १३२६ केन्द्रों में परीक्षाएँ होने लगी। सन् १९४० में प्रारम्भिक परीक्षाओं में ७८६९ और उच्च परीक्षाओं ११५४७ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, परीक्षार्थियों की यह संख्या १९६० में क्रमशः ११५८५९ तथा २६०४५ हो गई। इन संख्याओं से दक्षिण भारत में हिन्दी पढ़ने-पढ़ाने की जागरित रुचि का पता लगता है। १९६१ में परीक्षा केन्द्रों की संख्या १३५० हो गई। सभा की हिन्दी-परीक्षाओं में तीन प्रारम्भिक परीक्षाएँ हैं—प्राथमिक, मध्यम और राष्ट्रभाषा। इन परीक्षाओं का संचालन सभा की प्रास्तोय मास्टरों (सभाओं, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है) करती है, उच्च-परीक्षाओं का संचालन सभा स्वयं करती है, उच्च-परीक्षाएँ ये हैं—प्रवेशिका, विशारद प्रवेशी, विशारद उत्तरार्ध, प्रवीण, और हिन्दी प्रचारक। राष्ट्रभाषा विशारद और राष्ट्रभाषा प्रवीण उपाधि परीक्षाएँ हैं, इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्नातकों को उपाधियाँ देने के लिए सभा प्रति वर्ष पदवीदान-समारोह का आयोजन करती है।

कार्य का विस्तार और विभाग

सभा के कार्यों में विस्तार आ जाने पर सन् १९४९ में भिन्न-भिन्न विभागों के कार्यों का संचालन करने के लिए अलग-अलग मन्त्री भी नियुक्त हुए, वे हैं—साहित्य-मन्त्री, परीक्षा-मन्त्री, शिक्षा-मन्त्री। प्रधान मन्त्री के कार्यों में सहायता के लिए 'संयुक्त मन्त्री' का पद निर्मित हुआ। प्रथम संयुक्त मन्त्री प० रघुवर दयाल मिश्र हैं।

प्रकाशन-कार्य

सभा के पास अपना प्रेम है। उसने हिन्दी में उच्चस्तर की पुस्तकों और दक्षिण भारतीयों को हिन्दी सीखने के लिए प्रारम्भिक पुस्तकों, रीडर एव कोश प्रकाशित किये हैं, इन पुस्तकों की मख्या लगभग ३५० है। पुस्तकों के प्रकाशन और विक्री का काम सभा का विक्री-विभाग करता है।

सभा दो पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती है—'दक्षिण भारत' और 'हिन्दी प्रचार-समाचार'। पहली पत्रिका द्वैमासिक है, इसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के साहित्य, संस्कृति, इतिहास, समाज और इन क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के परिचय से सम्बद्ध सामग्री रहती है। दूसरी पत्रिका—'हिन्दी प्रचार-समाचार' मासिक है, इसमें हिन्दी के विद्यार्थियों और प्रचारकों के लाभार्थ हिन्दी-साहित्य की विविध सामग्री प्रकाशित होती है।

आयोजन

सभा सन् १९३१ से प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण स्नातकों को उपाधि देने के लिए पदवीदान-समारोह का आयोजन करती है। पदवीदान समारोह का दोक्षान्त-भाषण देश के दण्यमान नेताओं, विद्वानों और साहित्यकारों ने किया है। इनमें उत्तर भारत के भी व्यक्ति हैं जिनको सभा ने दोक्षान्त-भाषण के लिए आमन्त्रित किया था—पं० रामनरेश त्रिपाठी (१९३३), बाबू प्रेमचन्द (१९३४), पंडित सुन्दरलाल (१९३५), बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन (१९३६),

राजकुमारी अमृतकौर (१९४६), डा० जाकिर हुसैन (१९४८), श्री श्रीप्रकाश (१९५२), डा० राजेन्द्रप्रसाद (१९५६), श्री जगजीवनराम (१९५७)।

पदवीदान-समारोह के अतिरिक्त सभा अपने केन्द्रीय और प्रांतीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अन्य आयोजन भी करती है, इन आयोजनों के लिए प्राग्नाय स्तर पर सुव्यवस्थित संगठन किया गया है, इस संगठन के दो मुख्य भाग हैं—हिन्दी-प्रेसी-मण्डल और उनके द्वारा संचालित हिन्दी-प्रचार-केन्द्र। जो आयोजन किये जाते हैं उनका उद्देश्य हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के साथ हिन्दी का उच्च ज्ञानार्जन भी है, आयोजनों के नाम हैं—प्रचारक-सम्मेलन, वाक्-स्पर्धा, लेखन-स्पर्धा, नाटकों का अभिनय, हिन्दी-सप्ताह पमुख व्यक्तियों के भाषण आदि।

राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था

ऊपर सभा का जो परिचय दिया गया है, उससे उसके कार्य-विस्तार और दांशगु भारत में हिन्दी-प्रचार के उसके ऐतिहासिक महत्त्व का आकलन होता है। इस समय सभा का कार्यालय मद्रास के त्यागराय नगर में है, वहीं उसके विद्यालय और अन्य भवन हैं।

भारत सरकार ने १९६२ में सभा की महत्त्वपूर्ण हिन्दी-सेवा को देखते हुए एक विधेयक दत्ता कर इसका नया संगठन करने की योजना प्रस्तुत की है और इसे राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित किया है।

५-राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

सन् १९३६ में नागपुर—हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर देश के पूर्वी और पश्चिमी अंचल में हिन्दी-प्रचार के लिए गाँधी जी की प्रेरणा से हिन्दी-प्रचार-समिति का गठन किया गया था, यह गठन सम्मेलन का ही अंग था। सन् १९३८ में सम्मेलन का २७वाँ अधिवेशन शिमला में हुआ, उस अधिवेशन में एक निर्णय द्वारा समिति का नाम राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति कर दिया गया और इसका मुख्य कार्यालय वर्धा में ही रहा। समिति की



पहला बैठक ४ जुलाई १९३६ को सेवाग्राम-वर्धा में महात्मा गांधी के निवास स्थान पर हुई थी। सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन के समय समिति १५ सदस्यों की बनाई गई थी, सेवाग्राम की बैठक में ६ अन्य सदस्य मयोजित किये गये और समिति के सदस्यों की संख्या २१ हुई, इनमें चार पदाधिकारी चुने गये, सदस्यों की यह प्रथम नामावली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसे देखने से यह पता चलता है कि सन् १९३६ में राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम के हमारे प्रमुख कर्णधारों की दृष्टि में हिन्दी-प्रचार का प्रश्न कितना महत्त्वपूर्ण था, पूरी नामावली यह है— १—देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष, पदेन सम्मेलन के अध्यक्ष) २—महात्मा गांधी, ३—पं० जवाहरलाल नेहरू, ४—बाबू पुष्पोत्तमदास टंडन, ५—सेठ जमनालाल बजाज (उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष), ६—श्री ब्रजलाल विसाणो, ७—आचार्य नरेन्द्रदेव, ८—काका कालेलकर, ९—पं० हरिहर शर्मा, १०—श्री विद्योगीहरि, ११—बाबा राधवदास, १२—श्री शंकरराव देव, १३—पं० माखनलाल चतुर्वेदी, १४—सरदार नर्मदाप्रसाद सिंह (पदेन सम्मेलन के प्रबान मंत्री), १५—ठा० श्रीनाथ सिंह (पदेन—सम्मेलन के प्रबन्ध मंत्री), १६—श्रीमती लोक सुन्दरी राम, बगलूर, १७—श्रीमती पेरीनबेत केप्टेन, बम्बई, १८—श्रीमती रमादेवी चौधरानी, कटक, १९—श्रीयुक्त गुरुमुरीय गोस्वामी, आसाम, २०—श्री मोहरि मत्त-नारायण, मद्रास, २१—श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल (सयुक्त मंत्री)।

समिति की स्थापना का उद्देश्य

सन् १९३६ में समिति की यह स्थापना न केवल हिन्दी-प्रचार के लिए बरञ्च अहिन्दी-भाषी प्रांतों में हिन्दी का प्रचार करनेवालों सभी संस्थाओं का एक सम्मिलित संगठन बनाने के लिए भी हुई थी। इस समिति की स्थापना के पूर्व सन् १९३० के बाद से ही हिन्दी-प्रचार की ओर सर्वा अहिन्दी-भाषी प्रदेश उन्मुख हो रहे थे, स्वराज्य के प्रश्न के साथ हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न भी मुखर हो गया था। प्रदेशों का यह हिन्दी-प्रचार कहीं पर स्वतंत्र रूप से कोई मण्डल या सच स्थापित कर किया जा

रहा था, कहीं पर सम्मेलन के परीक्षा-केन्द्र स्थापित कर अथवा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास से सम्बद्ध संस्था स्थापित कर। जिन प्रदेशों में वर्धा-समिति की स्थापना के पूर्व से ही हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्र प्रयत्न किये जा रहे थे, वे प्रदेश हैं—गुजरात, उत्कल, बंगाल, आसाम और सिन्ध। गुजरात प्रदेश में सन् १९३५ में राष्ट्रभाषा प्रचार मण्डल, सूरत की स्थापना हुई थी और श्री मोहनलाल भट्ट ने सन् १९३५ में ही गुजरात विद्यापीठ तथा 'नवजीवन' के तत्वावधान में हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्भ कर दिया था। उत्कल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के १९३२ के पुरी अधिवेशन के अनन्तर १९३३ में ही राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना हो गई थी, इस स्थापना की मूल प्रेरणा बाबा राघवदास, देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद, श्री सीताराम जी मेक्सरिया और श्री वसन्तलाल जी मुरारका की थी एवं कार्य श्री अनुसूयाप्रसाद पाठक का था। बंगाल में कलकत्ते की 'पूर्व भारत हिन्दी प्रचार सभा' १९३४ से ही कार्य कर रही थी। आसाम में १९३४-३५ में ही महात्मा गाँधी ने और उनको प्रेरणा से बाबा राघवदास ने हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्भ कर दिया था। सिन्ध में १९११ से ही शिकारपुर की प्रीतिम धर्म मभा तथा हैदराबाद में स्थापित ब्रह्मचारी आश्रम—गिद्धमल संस्कृत पाठशाला द्वारा हिन्दी का प्रचार किया जा रहा था। तथा स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने हैदराबाद में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, जो हिन्दी पढ़ने के लिए रात्रि-पाठशालाएँ चलाती थी। पंजाब में प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन और साहित्यसदन अमृतसर के द्वारा १९२५ के पूर्व से ही हिन्दी के प्रचार का कार्य चल रहा था और सम्मेलन की परीक्षाएँ हुआ करती थी, अमृतसर में सदन का भव्य भवन, उसमें पुस्तकालय तथा हिन्दी का बहुमूल्य संग्रहालय है। बम्बई प्रदेश में सन् १९१९ (सम्मेलन के इन्दौर-अधिवेशन के बाद) से ही हिन्दी के प्रचार का कार्य आरम्भ हो गया था और १९२१, १९२४ में हिन्दी पढ़ाने के लिए वर्ग खोले गये थे सन् १९३१ में उत्माही हिन्दी-प्रेमी युवकों ने हिन्दी-प्रचार-सभा की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री बंजो नखनसी नणू तथा मंत्री श्री रा० शंकरन थे।

इस प्रकार वर्धा की समिति की स्थापना के पूर्व अहिन्दी-भाषी प्रान्त स्वतः हिन्दी-प्रचार के कार्य में रुचि ले रहे थे और इस प्रसंग में व्यापक प्रयत्न किये जा रहे थे। महात्मा गाँधी ने इस परिस्थिति का अध्ययन किया था और वे स्वतंत्र रूप में चलनेवाली इन सभी प्रान्तीय संस्थाओं को एक सूत्र में बाँधना चाहते थे। इस उद्देश्य से ही हिन्दी-प्रचार-समिति की स्थापना वर्धा में हुई और व्यापकता की दृष्टि से १९३८ में उसका नाम राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा किया गया। एक सूत्र ने गठित होकर संस्थाओं के प्रचार-कार्य में संलग्न होने में सबसे बड़ा लाभ यह था कि सभी प्रदेशों में अपने आप हिन्दी के स्वरूप में एकरूपता स्थापित हो जाती है। वर्धा-समिति की स्थापना के साथ ही सभी प्रान्तीय प्रचार-संस्थाएँ समिति से सम्बद्ध हो गईं। और वर्धा-समिति की परीक्षाओं में सभी प्रान्तों से परीक्षार्थी सम्मिलित होने लगे।

पीछे का इतिहास अध्ययन करने से यह अनुमान होता है कि इस प्रेरणा के पीछे गाँधी जी का भाषा-सम्बन्धी राजनीतिक प्रश्न का समाधान भी अन्तर्हित था। वे हिन्दी का प्रचार चाहते थे, पूरे देश के लिए व्यवहार की एक भाषा वे हिन्दी को स्वीकार करते थे, इसमें तो दो मत हो ही नहीं सकते। परन्तु उनके सामने प्रश्न हिन्दी के स्वरूप का था, कम से कम जिस स्वरूप को आगे चल कर अहिन्दी-भाषियों में प्रचारित किया जाता। उस स्वरूप के निर्माण के लिए भी सभी हिन्दी-प्रचार-संस्थाओं की केन्द्रभूत संस्था वर्धा में स्थापित की गई। वर्धा की हिन्दी-प्रचार-समिति हिन्दी के भावी स्वरूप के प्रश्न और समाधान का एक मात्र अन्तिम निर्णायक करती। गाँधी जी का यह उद्देश्य शीघ्र ही सामने आया, वस्तुतः वे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग का हिन्दी-सम्बन्धी स्थापनाओं से सहमत नहीं हो रहे थे, अतः हिन्दी प्रचार-समिति दो वर्ष के अनन्तर ही १९३८ में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के रूप में सामने आयी और तब गाँधी जी ने उसे १९४२ में अपना अभीमन—हिन्दु-स्तानी-प्रचार-समिति का रूप देना चाहा। हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रश्न लेकर महात्मा गाँधी और सम्मेलन की नीतियों में मतभेद उत्पन्न हो गया, और राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति सम्मेलन का ही अंग बनी रही अतः गाँधी जी हिन्दी के

स्वरूप के सम्बन्ध में सम्मेलन और समिति की नीति में सहमत नहीं हुए। और न सम्मेलन तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संचालक महात्मा गाँधी की भाषा-नीति को स्वीकार कर सके। ५ अक्टूबर १९४० को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की एक बैठक महात्मा गाँधी के सेवाश्रम में हुई और उस बैठक में इस झिन्गाव का पूरा स्पर्ष्टाकरण हो गया। इसके फलस्वरूप गाँधी जी और उनके अनुयायी राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति से अलग हो गये और उन्होंने २ फरवरी १९४२ को हिन्दुस्तानी प्रचार-समिति की स्थापना की। इस भौति अध्ययन करने पर राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति की स्थापना दूरगामी लक्ष्यों से पूर्ण है और हिन्दी के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। आरम्भ से ही भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में समिति को उलझना पड़ा है। जब १४ सितम्बर १९४६ को सविधान-समिति में हिन्दी राजभाषा स्वीकार कर ली गई तब समिति की भाषा-नीति का स्पष्ट रूप सामने आया।

समिति की भाषा-नीति

सन् १९४६ के अनन्तर जब सविधान-परिषद ने बहुमत से हिन्दी के स्वरूप को ही राजभाषा माने जाने की स्वीकृत दी, समिति ने भी हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट घोषणा की है और हिन्दी के सहज रूप को (कृत्रिम हिन्दुस्तानी में भिन्न) राष्ट्रभाषा का स्वरूप स्वीकार किया है। समिति के पारित प्रस्तावों के मुख्य अंश ये हैं—

“जो हिन्दी पुराने समय में देशभर में फैली हुई है उसी के क्रमिक विकास में हिन्दी का भावी रूप निखरेगा। हाल में कुछ भाइयों ने यह दिग्वाते का यत्न किया है कि राष्ट्रीय हिन्दी और प्रांतीय हिन्दी में भेद है। इस समिति के विचार में इस प्रकार का भेद सर्वथा निर्मूल है और इसमें हिन्दी के विकास में कोई लाभ नहीं हो सकता है।

“स्थानीय बोलियों के अनिरिक्त हिन्दी का कोई रूप राष्ट्रीय हिन्दी से भिन्न नहीं है। साहित्यिक और सांस्कृतिक हिन्दी एक है। वही सब प्रदेशों में प्रचलित है उसी के द्वारा राष्ट्रीय कार्य सम्पन्न हो सकेगा और उसी के

क्रमिक विकास में भविष्य के अनुसार संस्कृत तथा देश की अन्य भाषाओं का भग्न होगा।”

“इस भाषा की लिपि नागरी है। उसमें सब भाषाओं के शब्दों का, जो चालू है, समावेश और नये शब्दों के निर्माण में किसी भाषा के उपयुक्त शब्दों का बहिष्कार नहीं है।

“विशेष वैज्ञानिक विषयों की शब्दावली को छोड़ कर यह भाषा सरल और जनता की बोलचाल की भाषा से मिलती हुई होनी चाहिए।

“इस समिति की धारणा है कि भारतीय संविधान में भी नागरी लिपि में लिखित हिन्दी के इसी रूप की कल्पना की गई है और वह मानती है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का जो रूप आगे विकसित होगा उसके निर्माण में देश की समस्त भाषाओं का सहयोग होगा।”

“राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की भाषा नीति के बारे में कभी कभी यह प्रश्न उठा है कि वह विधान में स्वीकृत हिन्दी का प्रचार करती है या उससे भिन्न किसी भाषा का? समिति का विश्वास है कि समिति की भाषा नीति इतनी स्पष्ट रही है कि उसके सम्बन्ध में ऐसी कोई शंका उठनी नहीं चाहिए। इतना होने पर भी समिति की कार्य-समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि क्योंकि विधान में नागरी लिपि और हिन्दी के स्वीकार करने में समिति का भी कुछ प्रयत्न और हाथ रहा है, इसलिए हमारा तो कर्तव्य तथा निश्चय है कि हम विधान की ३५१वीं धारा के अनुरूप हिन्दी का प्रचार करें और केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की भी हिन्दी के प्रचार और प्रसार के कार्य में सहयोग और सहायता प्रदान करें।”

परीक्षा-संचालन

समिति ने स्थापना के साथ ही हिन्दी की परीक्षाएँ शुरू कीं। प्रारम्भ को दो वर्षों में उसने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर में हिन्दी-प्रवेश, हिन्दी-परिचय और हिन्दी-कोविद—तीन परीक्षाएँ लीं। १९३८ से इन परीक्षाओं का संचालन समिति स्वयं करने लगी। और जनवरी १९३८ में उसने अपनी

परीक्षा-समिति गठित कर ली। इस समय समिति द्वारा १३ परीक्षाएँ ली जाती हैं—

१—राष्ट्रभाषा प्राथमिक, २—राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक, ३—राष्ट्रभाषा प्रवेश, ४—राष्ट्रभाषा परिचय, ५—राष्ट्रभाषा कोविद, ६—राष्ट्रभाषा रत्न, ७—राष्ट्रभाषा आचार्य, ८—राष्ट्रभाषा अध्यापन विचारद, ९—राष्ट्रभाषा अध्यापन कोविद, १०—राष्ट्रभाषा प्रान्तीय भाषा परीक्षा (प्रारम्भिक तथा प्रवेश परीक्षा), ११—राष्ट्रभाषा महाजनी प्रवेश, १२—राष्ट्रभाषा वातचीत, १३—राष्ट्रभाषा आलेखन कोविद। 'परिचय उर्दू' की परीक्षा भी पहले ली जाती थी, अब हटा दी गई है।

समिति की परीक्षाओं का प्रचार अन्यन्त वेग से हुआ है, इस सम्बन्ध में कुछ आँकड़े ये हैं—सन् १९३७ में समिति की परीक्षाओं के १८ केन्द्र थे, ७ प्रचारक थे और ६१९ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे; सन् १९४० में केन्द्र १५०, प्रचारक २२६ और परीक्षार्थी १५६८५ रहे। सन् १९५० में यह संख्या क्रमशः १७२१, २३४१ और १८५७४४ हो गई। सन् १९६० में इस संख्या में लगभग दूना वृद्धि हुई—केन्द्रों की संख्या ३२५५ रही, प्रचारकों की संख्या ६९४० हो गई और परीक्षाओं में २२८४८३ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। अब समिति की परीक्षाएँ वर्ष में दो बार हुआ करती हैं। परीक्षाओं में ३० प्रतिशत संख्या महिलाओं की होती है।

समिति की सर्वोच्च परीक्षा राष्ट्रभाषा रत्न और राष्ट्रभाषा आचार्य है। रत्न का आरम्भ १९४४ में हुआ, तब उसमें ७९ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, परीक्षार्थियों की यह संख्या १९५० में ३०२ और १९६० में १४१६ हो गई। आचार्य परीक्षा का आरम्भ १९५८ से हुआ, पहली बार उसमें २६ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। यह संख्या प्रायः यही बनी रही।

प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ इन परीक्षाओं में अपने परीक्षार्थी बेंठाती हैं।

परीक्षा का पूरा संचालन वर्षा से होता है। केवल 'राष्ट्रभाषा प्राथमिक' परीक्षा को स्वयं लेने का अधिकार वर्षा-समिति ने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार

समिति पुणे और उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक को सौंप दिया है।

इन परीक्षाओं (विशेष रूप से कोंविद और राष्ट्रभाषा रत्न) को भारत सरकार, अनेक राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है।

समिति का संगठन

समिति का संगठन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की अगभूत संस्था के रूप में सम्मेलन की नियमावली नियम ५३-५८ के अनुसार हुआ था किन्तु इसका अपना विकास स्वतन्त्र संस्था के रूप में ही सामने आया। अपनी भाषा-सम्बन्धी रीति-नीति के लिए यह पूर्ण स्वतन्त्र है। सम्मेलन के अधिकारी पदेन इसके सदस्य होते हैं। आरम्भ में इसकी स्थापना के समय २१ व्यक्तियों की समिति बनी थी, यह उल्लेख पहले किया जा चुका है। शीघ्र ही जब इसका विस्तार सभी प्रान्तों में हो गया तब प्रत्येक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार-समितियों के प्रतिनिधियों को भी संगठन में स्थान देना पड़ा। अब समिति का संगठन ३५ सदस्यों का है, इनमें १६ सदस्य प्रान्तीय समितियों के प्रतिनिधि होते हैं, ७ सदस्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के पदाधिकारी होते हैं और ६ सदस्यों का निर्वाचन सम्मेलन की स्थायी समिति करती है। इन्हीं में से ही मंत्रों का चुनाव तीन वर्ष के लिए किया जाता है। आरम्भ में समिति के मंत्री श्री मोहम्मद सत्यनारायण जी थे। उनके मद्रास की सभा के कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण ५ जुलाई १९३८ को श्री श्रीमन्नारायण अन्नवाल मंत्री निर्वाचित हुए। १९४२ ई० में गाँधी जी की हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना हुई, तब श्रीमन्नारायण अन्नवाल उस संस्था में चले गये और उनका मंत्री-पद संभाला। उस समय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की प्रेरणा से श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मन्त्रित्व स्वीकार किया। सन् १९५१ तक वे इसके मंत्री रहे। उनके बाद से गाँधी जी के 'नवजीवन' के व्यापक श्री मोहनलाल भट्ट समिति के मंत्री हैं। इन्होंने एक नम्बे भरसे से समिति के व्यापक कार्य भार को संभाल रखा है।

परीक्षाओं का संचालन करने के लिए अलग से एक परीक्षा-समिति भी है, जिसके सदस्यों की संख्या २१ है। इनमें १५ सदस्य उन प्रान्तीय समितियों के प्रतिनिधि होते हैं जिनमें समिति की परीक्षाओं का संचालन होता है।

समिति अपने प्रान्तीय समितियों को विद्यालय-संचालन एवं भवन-निर्माण के लिए यथाशक्ति अनुदान भी देती है। प्रान्तीय समितियों को प्रदेशीय सरकारों से भी अनुदान एवं समय-समय पर अन्य सहायता प्राप्त होती रहती है। सभी प्रान्तीय समितियों के अपने भवन हैं और उनमें कई एक विद्यालयों का संचालन भी करती हैं। कुछ अपनी पत्रिकाएँ भी निकालती हैं और उनका निजी प्रकाशन भी है। इन समितियों ने भी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए उसे जिला स्तर पर विभक्त कर रखा है। वर्धा समिति ने सम्बद्ध प्रान्तीय समितियों की सूची निम्नलिखित है। इस सूची में उनकी स्थापना का वर्ष, प्रकाशित होनेवाली पत्रिका का नाम, उसका प्रकाशन वर्ष तथा वर्तमान संचालक मंत्री का नाम भी दे दिया गया है—

- (१) गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद (१९३७)
पत्रिका—राष्ट्रवीणा (१९५०)
मन्त्री-संचालक—श्री जेठालाल जोशी
- (२) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणे (१९३७)
पत्रिका—जगशरणी (१९४७), अब बन्द है।
मन्त्री-संचालक—श्री पं० मु० डांगरे।
- (३) बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई (१९३७)
मन्त्री-संचालक—श्री कान्तीलाल जोशी
- (४) उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक (१९३७)
पत्रिका—राष्ट्रभाषा-पत्र
मन्त्री-संचालक—श्री अनुसूया प्रसाद पाठक
- (५) असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, शिलांग (१९३८)
मन्त्री—श्री जीतेन्द्रचन्द्र चौधुरी

(६) पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कलकत्ता (१९३६)

मन्त्री-संचालक—श्री रेवलीरजन सिनहा

(७) मध्य-राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जयपुर (१९३६)

मन्त्री-संचालक—श्री दौलतराम शर्मा

(८) पंजाब प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अमृतसर (१९५८)

संचालक—श्री दौलतराम शर्मा

इन प्रान्तों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा (१९३६) की स्थापना के पूर्व से ही हिन्दी-प्रचार का कार्य किसी न किसी सच या सभा आदि से हो रहा था। वर्षा-समिति की स्थापना हो जाने पर उस संस्थाओं ने अपने को वर्षा-समिति में सम्मिलित कर लिया और प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के रूप में परिणत हो गईं।

(९) त्रिदम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर (१९३८)

मन्त्री-संचालक—प० हृषीकेश शर्मा

(१०) मथुरा राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, इम्फाल (१९४०)

मन्त्री-संचालक—श्री लखवज्ज शर्मा

(११) दिल्ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दिल्ली (१९४०)

मन्त्री-संचालिका—श्रीमती राजलक्ष्मी रायचन

(१२) मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल (१९४२)

मन्त्री-संचालक—श्री वैजनाथ प्रसाद दुबे

(१३) मराठवाड़ा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, औरंगाबाद (१९४६)

मन्त्री-संचालक—श्री विष्णुदत्त शर्मा

(१४) कर्नाटक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हुबली (१९४७)

संचालक—श्री वासुदेव चिन्तामणि वस्ता

(१५) जम्मू-काश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्रीनगर (१९४९)

संचालक—श्री जम्मूनाथ जी पारिभू

(१६) बेलगाँव जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बेलगाँव (१९५१)

जिला सगठक—श्री द० पा० साठम

इस प्रकार राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा का पूरे देश में एक सुसंगठित परिवार है, जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार के कार्य में निष्ठा के साथ मंलग्न है। १९५१ से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग में आपसी मतभेद के कारण जो गतिरोध पैदा हुआ और अहिन्दी भाषी-प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार के कार्य को सम्मेलन द्वारा कोई गति नहीं मिली, उस अभाव को वर्धा-समिति ने पूरा किया है।

राष्ट्रभाषा-अध्ययन-मन्दिर

वर्धा-समिति की स्थापना के साथ ही हिन्दीतर प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार का काम करने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः सन् १९३७ में राष्ट्रभाषा-अध्ययन-मन्दिर की स्थापना वर्धा-समिति ने की। ७ जुलाई १९३७ को महात्मा गाँधी ने इस मन्दिर का उद्घाटन किया था। सन् १९४२ में समिति द्वारा राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा का संचालन किये जाने के बाद उक्त अध्ययन-मन्दिर का कार्य बन्द कर दिया गया। इसके प्रधाना-ध्यापक पं० हृषीकेश शर्मा थे। पाँच वर्ष की अवधि में इस अध्यापन-मन्दिर से ४६ हिन्दी-प्रचारक निष्णात हो कर निकले।

हिन्दी-पढ़ाई की व्यवस्था

समिति ने १९५३ में 'राष्ट्रभाषा महाविद्यालय' की स्थापना की। श्री रमूल अहमद अबोध इसके प्रधानाध्यक हुए। समिति ने अपनी संचालित परीक्षाओं की शिक्षण-व्यवस्था के लिए यह एक प्रशासनीय कार्य किया है। इस विद्यालय में राष्ट्रभाषा रत्न तथा अध्यापन विशारद तक की पढ़ाई होती है। आसाम-मणिपुर के नागा विद्यार्थियों को भी हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था यहाँ की गई है, प्रत्येक वर्ष १०-१२ नागा विद्यार्थी यहाँ शिक्षा देने के लिए बुलाये जाते हैं समिति उनको छात्रवृत्ति देती है। जो नागा विद्यार्थी यहाँ पढ़ कर निष्णात हुए हैं वे लौट कर अपने प्रदेश में हिन्दी का कार्य कर रहे हैं।

वर्धा के इस 'राष्ट्रभाषा महाविद्यालय' के अन्तर्गत प्रत्येक प्रांतीय समिति

द्वारा महाविद्यालयों का संचालन होता है। वर्धा-समिति प्रत्येक प्रान्तीय समिति को इस कार्य के लिए ५०० रु० प्रतिवर्ष अनुदान देती है। इसके अनिवार्यतः अन्य संचालित हिन्दी-विद्यालयों को भी प्रतिमात्र ५० रु० सहायता समिति से मिलती है। शिक्षण-व्यवस्था का स्वरूप तीन भागों में विभक्त है—(१) शिक्षण केन्द्र, (२) राष्ट्रभाषा विद्यालय, (३) राष्ट्रभाषा महाविद्यालय। पहले में पारिचय तक की पढ़ाई होती है। दूसरे में 'बोर्ड' तक की पढ़ाई की व्यवस्था रहती है। और तीसरे में 'ग्रेजुएट' तक की पढ़ाई की जाती है। १९६२ के आँकड़ों के अनुसार प्रत्येक प्रान्तीय समितियों का योग मिला कर ५५७ शिक्षण केन्द्र, ५३४ राष्ट्रभाषा विद्यालय और ३६ महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

प्रकाशन-कार्य

वर्धा समिति का मासिक पत्र प्रकाशित करती है। पहला है 'राष्ट्रभाषा'। यह मासिक पत्र जुलाई १९४३ में निकल रहा है और समिति का मुख पत्र है इसके पूर्व 'मन की बोली' एवं 'राष्ट्रभाषा समाचार' कमजोर समिति द्वारा प्रकाशित हुए थे, जिनका स्थान अब राष्ट्रभाषा ने लिया है। राष्ट्रभाषा में परीक्षार्थियों के उपयोगी लेख, हिन्दी-प्रचार एवं परीक्षा-सम्बन्धी सामग्री होता है।

समिति ने १९५० से दूसरे मासिक पत्र 'राष्ट्रभारती' का प्रकाशन आरम्भ किया। यह सांस्कृतिक और साहित्यिक पत्रिका है। इसमें हिन्दोत्तर भाषाओं का साहित्य भी हिन्दी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

समिति का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 'कविश्री'—माला है। इस माला में देश की १४ भाषाओं के प्रतिनिधि कवियों की रचनाएँ मूल तथा हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित की गई हैं। मूल भी नागरी लिपि में है। अब तक इस माला में २५ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

समिति के पास अपना प्रेस 'राष्ट्रभाषा प्रेस' है। समिति ने अब तक ७५ पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

मूर्ति-स्थापना

वर्धा-समिति के निर्माण में महात्मा गाँधी, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन और सैठ जमनालाल बजाज का बड़ा हाथ रहा है। १९६२ में समिति ने जब अपनी रजत-जयन्ती मनाई तब उक्त तीनों महापुरुषों की स्मृति में उनकी प्रतिमा की स्थापना समिति के प्रांगण में की गई। इन प्रतिमाओं का अनावरण क्रमशः स्वराष्ट्र-मन्त्री माननीय लालबहादुर शास्त्री, सैठ गोविन्ददास और मध्य-प्रदेश के राज्यपाल श्री ह० वि० पाटस्कर ने किया था।

राष्ट्रभाषा पुस्तकालय

उक्त नाम में समिति का अपना एक विद्यालय-पुस्तकालय है। जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी गुजराती आदि भाषाओं की १२ हजार पुस्तकें संग्रहीत हैं। इसके साथ एक द्विन्दी मन्दिर पुस्तकालय भी है जिसमें डेढ़ हजार पुस्तकें हैं, वह गृह में संचालित होता है।

आयोजन

सन् १९४६ से समिति अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन किया करती है। १९६२ में उसने अपना ११ वाँ प्र० भा० रा० प्र० सम्मेलन किया है और अपनी रजत-जयन्ती मनाई है। इस अवसर पर प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्घाटन-सन्देश समिति को भेजा था, उसका एक अंश यह है—

“राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इन २५ वर्षों में जो काम किया है उसको सब लोग जो हिन्दी में दिलचस्पी लेते हैं जानते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैंने इस काम को अक्सर देखा है और मुझे बहुत पसन्द आया है, विशेष कर समिति ने जो राष्ट्रभाषा का ढग निकाला है, यानी मादी और सरल हो, वह मुझे खासतौर से पसन्द आया है। अक्सर आज कल हमारी हिन्दी बहुत कठिन हो गई है जिसको आम लोग नहीं समझते। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रभाषा समिति की हिन्दी का प्रयोग अधिकतर हो। उसमें हिन्दी को भी लाभ होगा और उसके पढ़नेवालों को भी।”

समिति ने हम रजत-जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रभाषा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए उनको 'राष्ट्रभाषा गौरव' की उपाधि प्रदान कर अभिनन्दित किया है, उपधिप्राप्त सभी आठ हिन्दी-कार्यकर्ता अहिन्दी भाषी-प्रदेशों के हैं।

इसके पूर्व समिति ने अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी को सेवा करनेवाले तीन कर्मठ सेवकों—पं० हृषीकेश शर्मा, श्री जेटालाल जोशी और पं० हरिहर शर्मा का विशेष सम्मान अपने तीन विभिन्न अधिवेशनों—१९५६, १९५८, १९६०—में किया है।

महात्मा गाँधी पुरस्कार

समिति ने अपने दूसरे अहमदाबाद-अधिवेशन (१९५०) में अहिन्दी-भाषी हिन्दी-लेखकों को १५०१ रु० का महात्मा गाँधी-पुरस्कार देने का निश्चय किया था। यह धनराशि समिति अपने ही बजट से देती है, जिस एक महत्त्वपूर्ण निश्चय कहा जाना चाहिए। अब तक यह पुरस्कार ६ अहिन्दी-भाषी हिन्दी-लेखकों को मिल चुका है।

समिति समय-समय पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार और परस्पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भाषण एवं निबन्ध की स्पर्धाएँ (प्रतियोगिताएँ) भी आयोजित करती है। एवं इसी प्रकार के अन्य आयोजन प्रवर्तित करती है।

समाचार भारती

समिति ने अपने नवें दिल्ली अधिवेशन (१९५६) के अवसर पर एक निश्चय के अनुसार 'समाचार-भारती' सस्या की स्थापना की है। जिसका लक्ष्य देश की भाषाओं के माध्यम से समाचारों का प्रसारण है। १ जनवरी १९६७ से हिन्दी, गुजराती और मराठी भाषाओं में इसका कार्यारम्भ किया जा चुका है।

समिति के कार्य-विभाग और भवन

समिति का कार्य १० विभागों में बँटा हुआ है—१ प्रचार २ परीक्षा

३. साहित्य निर्माण, ४. प्रकाशन, ५. पुस्तक-विक्री, ६. राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-भारती, ७. पुस्तकालय, ८. प्रेस, ९. भवन और १०. अर्थ ।

समिति के इस समय ८ भवन हैं, जिनकी लागत ६ लाख रुपये होगी । समिति के पास कुल १६ एकड़ भूमि है । समिति अपनी प्रान्तीय समितियों के भवन-निर्माण के लिए भी मचेष्ट रही है और उन्हें अनुदान दिया है ।

वर्धा-समिति का पूरा इतिहास और परिचय १९३६ से अब तक के हिन्दी के संघर्ष और प्रगतियों का एक प्रमुख अंश है ।

६—हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद

दक्षिण भारत की हिन्दी-प्रचारिणी संस्थाओं में सभा का इतिहास वर्धा समिति से पूर्व का और -क्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा मद्रास के बाद का है । राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि के प्रचार-प्रसार को लक्ष्य कर इस सभा की स्थापना सन् १९३५ में हुई । और अपने इस लक्ष्य के प्रति सभा सदैव दृढ़ रही है । दिसम्बर सन् १९४६ (स० २००६) में सभा के आमन्त्रण पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का ३७वाँ अधिवेशन यहाँ सम्पन्न हुआ था ।

अहिन्दी-भाषियों में हिन्दी का प्रचार करना, हिन्दी साहित्य के प्रति रुचि जागरित करना और प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी का परस्पर आदान-प्रदान एवं स्नेह बढ़ाना—सभा के प्रकट उद्देश्य है । इनकी पूर्ति के लिए सभा हिन्दी परीक्षाओं का संचालन, उपयुक्त साहित्य का निर्माण तथा पुस्तकालयों का संचालन करने के अतिरिक्त सदा जन-सम्पर्क एवं सरकारी शिक्षा-विभाग के सहयोगों के प्रति प्रयत्नशील रहती है ।

परीक्षा-संचालन

सभा की परीक्षाओं का आरम्भ सन् १९४१ से हुआ । उच्च परीक्षाओं के नाम हैं—हिन्दी शिक्षक, विशारद, भूषण, विद्वान । ये परीक्षाएँ सम्प्रति ४५० केन्द्रों में होती हैं और लगभग ४० हजार विद्यार्थी इनमें बैठते हैं, जिनमें

३० प्रतिशत महिलाएँ होती है। परीक्षार्थियों में ६० प्रतिशत अहिन्दी-भाषी होते हैं। परीक्षाएँ वर्ष में दो बार होती हैं।

सभा की परीक्षाओं को भारत सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश, मैसूर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश की सरकारों ने अपनी-अपनी मान्यताएँ प्रदान की हैं।

साहित्य-निर्माण

सभा ने अपने साहित्य विभाग के द्वारा हिन्दी साहित्य की पुस्तकों का प्रादेशिक भाषाओं में तथा प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का हिन्दी में अनुवाद करा कर पुस्तकें प्रकाशित की हैं। गम्भीर और उच्च साहित्य के निर्माण के प्रति भी सजगता सभा ने दिखाई है। 'अजन्ता' नाम की एक साहित्यिक पत्रिका सभा द्वारा कई वर्षों तक प्रकाशित होती रही है।

भारत सरकार की सहायता से सभा कुछ विशिष्ट प्रकाशनों के लिए काम कर रही है। इन प्रकाशनों में मराठी, तेलुगु, कन्नड और उर्दू साहित्य का इतिहास, हिन्दी-उर्दू कोश तथा उर्दू-हिन्दी कोश हैं।

दक्खिनी हिन्दी के साहित्य को हिन्दी के निकट लाने के लिए यहाँ 'दक्खिनी प्रकाशन समिति' नाम की एक संस्था काम करती है। सभा ने इसे आर्थिक और बौद्धिक सहयोग दिया है।

पुस्तकालय-योजना

हिन्दी-साहित्य के प्रति पठन-पाठन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रादेशिक भाषा के पुस्तकालयों को सभा हिन्दी-पुस्तकों का अनुदान देती है। यह कार्य कई जिलों में सम्पन्न हुआ है।

इन कार्यों के अनिरिक्त सभा बराबर सरकार को हिन्दी-प्रचार के कार्यों में सहयोग देती रही है और इस विषय में वह प्रदेशीय सरकार के शिक्षा-विभाग का पूरक अंग है।

हिन्दी-प्रचार के कार्य में सभा का गौरव-पूर्ण स्थान है और आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी के प्रसार का श्रेय इसको है।

७-महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे

इस संस्था की स्थापना महामहोपाध्याय श्रीदत्तोवामन जी पोतदार और श्री गो० प० नेने ने सन् १९४५ में किया। इसके पूर्व वे वर्धा-समिति से सम्बद्ध महाराष्ट्र प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संचालक थे। परीक्षाओं और विद्यालयों का संचालन तथा प्रकाशन आदि कार्यों द्वारा सभा ने हिन्दी के प्रचार में स्तुत्य कार्य किया है। १९४६ में अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना होने पर यह सभा उससे सम्बद्ध हो गई।

परीक्षाएँ

सभा १९४६ से निम्नांकित परीक्षाओं का संचालन करती है—

राष्ट्रभाषा-पहली, राष्ट्रभाषा-दूसरी, राष्ट्रभाषा-प्रबोध, राष्ट्रभाषा-प्रवीण, राष्ट्रभाषा-पंडित, राष्ट्रभाषा-सम्भाषण-योग्यता, अनुवाद-पंडित।

सभा की परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यताएँ प्राप्त हैं। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इनमें सम्मिलित होते हैं।

शिक्षण और प्रचार कार्य

सभा स्थान-स्थान पर शिक्षण-वर्गों का प्रबन्ध करती है। उच्च परीक्षाओं के लिए शिक्षक तैयार करने के हेतु विद्यालय चलाती है। व्याख्यान-मालाओं का आयोजन करती है।

सभा के पास २० हजार पुस्तकों का एक बृहद् ग्रन्थालय है।

प्रकाशन

सभा के पास निजी बड़ा प्रेस है। उसने उपयुक्त पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और 'राष्ट्रवाणी' नाम की एक सांस्कृतिक, साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है।

८—मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्, बंगलौर

इस परिषद् की स्थापना १९४३ में हुई। इसने कन्नड़भाषी मैसूर राज्य में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का स्तुत्य कार्य किया है। परीक्षा-संचालन, शिक्षण-व्यवस्था और प्रकाशनो द्वारा इस संस्था के कार्यों का विस्तार हुआ है।

परीक्षाएँ

परिषद् की ओर से प्रथमा, मध्यमा, प्रवेश, उत्तमा, हिन्दी रत्न (उपाधि परीक्षा) परीक्षाएँ ली जाती हैं। आरम्भ से ही मैसूर सरकार द्वारा इन परीक्षाओं को मान्यता प्राप्त है, अब भारत सरकार ने भी अपनी मान्यताएँ परिषद् की परीक्षाओं को प्रदान की हैं। परिषद् के २०० परीक्षा केन्द्र हैं और परीक्षाओं में लगभग २५ हजार विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। परीक्षाएँ वर्ष में दो बार होती हैं।

परिषद् हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं का केन्द्र भी है।

शिक्षण-व्यवस्था

परिषद् की ओर से उसके केन्द्रीय कार्यालय में अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। हिन्दी उत्तमा और हिन्दी रत्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण के विशेष वर्ग चलाये जाते हैं। वाक्स्पर्धा, प्रचारक-सम्मेलन, विचारक-गोष्ठी आदि कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। 'हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण केन्द्र' भी परिषद् की देख-रेख में मैसूर सरकार की आर्थिक सहायता से चलता है।

परिषद् का अपना एक पुस्तकालय है, जिसमें २० हजार से अधिक पुस्तकें हैं। राज्य के मुख्य नगरों में परिषद् द्वारा हिन्दी-पुस्तकालयों का संचालन होता है।

प्रकाशन

परिषद् ने अपनी प्रारम्भिक परीक्षाओं के लिए पाठ्यग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। इन प्रकाशनो में हिन्दी-कन्नड़ अनुवादमाला और हिन्दी-कन्नड़ व्याकरण जैसी पुस्तकें भी हैं।

६-अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली

भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा हिन्दी के निर्माण, विकास एवं सर्वजन को लेकर १९४६ में इस परिषद् की स्थापना नई दिल्ली में हुई। इस उद्देश्य से काम करनेवाली संस्थाओं को सम्बद्ध करना भी संस्था का लक्ष्य है, सम्प्रति १३ संस्थाएँ परिषद् से सम्बद्ध हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद थे। श्री शंकरराव देव और श्री मो॰ सत्यनारायण इसके संयोजक चुने गये थे, जो बाद में मन्त्री रहे।

परिषद् की ओर से आगरा में एक विद्यालय का संचालन हुआ। जहाँ ग्रहिन्दी प्रदेश के विद्यार्थी हिन्दी की वैज्ञानिक योग्यता प्राप्त करने के हेतु आते हैं। यहाँ से उत्तीर्ण स्नातको को पारंगत उपाधि दी जाती है। इस विद्यालय का संचालन और नियमन अब भारत सरकार का केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय किया करता है।

अन्य संस्थाएँ

आगे अन्य ऐसी संस्थाओं का उल्लेख किया जाता है, जिनका इतिहास पूर्व-उल्लिखित संस्थाओं से कुछ भिन्न है, ये ऐसी संस्थाएँ हैं, जो अब प्रचार-कार्य के अतिरिक्त परीक्षाओं के संचालन की ओर अधिक उन्मुख रहते हैं या जिन्होंने हिन्दी के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' भाषा की स्थापना का प्रयास किया है अथवा अब जिनके प्रचार-कार्य की गति धीमी पड़ गई है।

१०-बम्बई हिन्दी विद्यापीठ

इस विद्यापीठ की स्थापना १९३८ में हुई। यह विद्यापीठ हिन्दी को कई परीक्षाएँ लेता है, जिनमें हिन्दी भाषासूत्र, साहित्य सुझाकर और साहित्य रत्नाकर उच्च परीक्षाएँ हैं, इन परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। परीक्षाओं के केन्द्र विभिन्न प्रदेशों में हैं जिनकी संख्या ८४७ है।

विद्यापीठ के पास अपना प्रेस है। इसने निजी प्रकाशन भी किये हैं। हिन्दी-प्रचार को लक्ष्य कर सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन विद्यापीठ करता है।

११-भारतीय विद्यापीठ, बम्बई

१९४२ में ज्ञानलता मंडल की स्थापना हुई थी, उसने १९४६ में भारतीय विद्यापीठ का संचालन किया। हिन्दी-प्रचार को लक्ष्य कर विद्यापीठ परीक्षाओं का संचालन, पुस्तकों का प्रकाशन और सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन करता है। रत्न और आचार्य विद्यापीठ की उच्च परीक्षाएँ हैं, कुछ राज्य सरकारों ने इनको मान्यता प्रदान की है।

१२-गुजरात विद्यापीठ

इस विद्यापीठ की स्थापना १९२० में महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के साथ हुई थी, जो विद्यार्थी असहयोग-आन्दोलन में सरकार के महा-विद्यालयों एवं शालाओं का बहिष्कार कर रहे थे उनकी शिक्षा के लिए इस विद्यापीठ का संचालन किया गया। उस समय महात्मा गाँधी स्वयं इसके उपकुलपति बने थे, आचार्य गिडवानी, आचार्य कृपलानी और आचार्य काका साहेब कालेलकर जैसे विद्वानों का सहयोग इस विद्यापीठ को प्राप्त था।

इस विद्यापीठ ने हिन्दी-शिक्षा को प्रमुख स्थान अपने शिक्षण कार्य में दिया। १९३५ में इसने 'नवजीवन' ट्रस्ट के सहयोग से हिन्दी-प्रचार के कार्य को गुजरात में विस्तृत किया।

१९४२ में जब हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना गाँधी जी की प्रेरणा से की गई तो इस विद्यापीठ ने हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी के प्रचार को अपना लक्ष्य बनाया। अर्थात् हिन्दुस्तानी भाषा और उसके साथ व्यागरी और फारसी दोनों लिपियों का प्रचार इसका लक्ष्य रहा। १९४५ में

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने गुजरात का अपना कार्य गुजरात विद्यापीठ को ही सौंप दिया था ।

संविधान मे हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को स्वीकार किये जाने के बाद विद्यापीठ ने दो लिपियों का अपना आग्रह समाप्त कर दिया ।

बम्बई और गुजरात प्रदेश मे इस विद्यापीठ के प्रति बड़ा आदर है । सम्प्रति विद्यापीठ हिन्दी की पाँच परीक्षाएँ लेता है—(१) हिन्दी पहली, (२) हिन्दी दूसरी, (३) हिन्दी तीसरी, (४) विनीत, (५) हिन्दी सेवक । परीक्षाएँ वर्ष मे दो बार होती है । तीसरी, विनीत और सेवक परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

१३—हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्षा

इस सभा की स्थापना का उल्लेख राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्षा के इतिहास में किया जा चुका है । हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का जन्म महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे २ मई १९४२ को हुआ । इसका लक्ष्य हिन्दी के स्थान पर ऐसी भाषा का प्रचार करना था जो उर्दू-भाषी मुसलमानों को भी स्वीकार हो तथा नागरी के साथ फारसी लिपि के अपनाये जाने का भी इसका आग्रह रहा है । १९४५ में हिन्दुस्तानी साहित्य तैयार करने के लिए एक बोर्ड कायम हुआ, उसकी एक उपसमिति बनी, जिसके प्रमुख निरीक्षक डॉ० ताराचन्द्र थे । १९४४ से सभा ने हिन्दुस्तानी लिखावट, हिन्दी पहली, हिन्दी दूसरी और हिन्दी तीसरी परीक्षाओं का संचालन आरम्भ किया था । गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार सभा तथा हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बम्बई—दो प्रदेशीय संस्थाएँ इससे सम्बद्ध हुई थीं ।

१९४५ मे काका साहेब कालेलकर जब जेल से बाहर आये तब उन्होंने इसके प्रचार-कार्य के लिए दौरा किया ।

गुजरात मे हिन्दुस्तानी-प्रचार का कार्य गुजरात विद्यापीठ को सौंप दिया

गया। आज गुजरात विद्यापीठ हिन्दी की जो परीक्षाएँ लेता है उनका पूर्व-निर्धारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने किया था।

१९४७ में सभा का कार्यालय बम्बई चला गया। वही अब इसका कार्य होता है। जो प्रायः नही के बराबर है। भारत सरकार ने इसकी विद्वान् और काबिल परीक्षाओं को मान्यता दी थी।

१४—हिन्दी विद्यापीठ, देवघर (बिहार)

इस विद्यापीठ की स्थापना स० १९८६ वि० में हुई। यह परीक्षाओं का संचालन करता है और एक साहित्य महाविद्यालय चलाता है। विद्यापीठ की चार परीक्षाएँ हैं—हिन्दीविद्, प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्यालंकार। बिहार से बाहर भी इसके परीक्षा केन्द्र हैं। इसकी साहित्यालंकार (उपाधि) परीक्षा के प्रति बड़ा सम्मान है और बिहार सरकार एवं बिहार के विश्व-विद्यालयों से इस परीक्षा को विभिन्न मान्यताएँ प्राप्त हैं।

हिन्दी का प्रचार करनेवाली दक्षिण भारत की ये तीन संस्थाएँ भी हैं, जिनका कार्य हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से स्तुत्य है—

१५—तिरुवांकुर हिन्दी प्रचार-सभा तिरुवनंतपुरम्

१६—साहित्यानुशीलन समिति—मद्रास

१७—कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा—धारवाड

उत्तर भारत की निम्नांकित दो संस्थाएँ भी हिन्दी के प्रचार और हिन्दी साहित्य के संवर्धन में योगदान करती रही हैं, इनके पास अपना निजी भवन और अच्छा पुस्तकालय है—

१८—नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा (उ० प्र०)

१९—नागरी प्रचारिणी सभा, आरा (बिहार)

इन संस्थाओं के अतिरिक्त प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन और अन्य साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान भी हिन्दी-प्रचार की उन्नत संस्थाएँ हैं जो क्रमशः

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और नागरी प्रचारिणी सभा काशी से सम्बद्ध है। सम्मेलन और सभा के इतिहास में इसका उल्लेख किया जा चुका है। ऐसी संस्थाओं में—

२०—उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

अब सन् १९६४ से अपनी तीन परीक्षाएँ लेता है—साहित्य-प्रवेश, साहित्यस्नातक, साहित्यशिरोमणि। इन परीक्षाओं की संज्ञा ‘राष्ट्र भाषा परीक्षाएँ’ है, इनकी विशेषता यह है कि केवल खड़ीबोली हिन्दी का अब तक की विविध विधाओं का साहित्य ही इनके पाठ्य-क्रम में है। सितम्बर सन् १९६६ में प्रदेशीय सम्मेलन ने अपने द्वादश अधिवेशन के समय इन परीक्षाओं का दीक्षान्त-समारोह भी किया है।

प्रदेशीय सम्मेलन की स्थापना सन् १९२१ में हुई थी। इसने कचहरियों में हिन्दी तथा नागरी लिपि के प्रवेश के लिए आन्दोलन किया है और इस सम्बन्ध की आवश्यक पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

प्रदेशीय सम्मेलन हिन्दी-सेवी गण्यमान्य विद्वानों को अपनी ‘साहित्य-चारिधि’ की उच्च उपाधि स्थायी-समिति के निश्चय के अनुसार प्रदान करता है। यह उपाधि ताम्रपत्र पर अर्चना-पूर्वक दी जाती है। गत १९६६ के अधिवेशन में हिन्दी के सात विद्वानों को यह उपाधि दी गई है।

सन् १९५१ में एक दूसरे उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी हुई थी, जिसने सरकार से अनुदान प्राप्त कर हिन्दी के एक-दो उपयोगी प्रकाशन किये हैं।

रचनात्मक संस्थान

रचनात्मक संस्थान शीर्षक से यह नहीं समझना चाहिए कि पीछे जिन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है उन संस्थाओं ने ऐसे रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया है, उनमें से अनेक संस्थाओं ने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है और नागरी प्रचारिणी सभा काशी का कार्य तो इस दृष्टि से बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ अब कुछ ऐसी संस्थाओं का परिचय दिया जा रहा है जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार, परीक्षा-संचालन आदि में रुचि न लेकर विद्वद्-गोष्ठियों के आयोजन और हिन्दी में उत्कृष्ट साहित्य के निर्माण के प्रति प्रयत्नशील रही है। और इस क्षेत्र में उन्होंने हिन्दी की अमूल्य सेवाएँ की हैं।

१—हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

इस अकादमी की स्थापना २० जनवरी १९२७ को उस समय की संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने की थी। सर तेजबहादुर सप्रू इसके पहले अध्यक्ष थे। हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं की उन्नति इसका लक्ष्य था। विस्तार से इसके उद्देश्य ये थे—

- (१) विशिष्ट विषय की सर्वोत्तम पुस्तकों पर पुरस्कार देना।
- (२) वैतनिक अनुवादकों द्वारा पुस्तकों का हिन्दी तथा उर्दू में अनुवाद करना और अकादमी के माध्यम से उन्हें प्रकाशित

(३) विश्वविद्यालयों तथा साहित्यिक संस्थाओं आदि को दिये गये अनुदान से मौलिक अथवा अमूल्य पुस्तकों को रचना के लिए प्राप्ताहित करना ।

(४) अकादमी के फेलोशिप के लिए विख्यात लेखकों का चुनाव करना ।

आज इस संस्था द्वारा भारत सरकार और अमेरिकी दूतावास ने भी अंग्रेजी, पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में कराया है ।

समय-समय पर अकादमी ने विभिन्न विषय के अधिकारी विद्वानों का व्याख्यान आयोजित किया है । इन विद्वानों में म० म० पं० गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा भी है, जिनका सहयोग अकादमी को मिला है, उनके व्याख्यान को 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति' नाम से अकादमी ने प्रकाशित किया था ।

अकादमी के पास एक अच्छा पुस्तकालय और अब अपना निजी भवन है । इसने अब तक कई उत्कृष्ट पुस्तकों का प्रकाशन किया है । जिनमें विज्ञान की भी पुस्तकें हैं, प्रदेशीय सरकार इसे प्रति वर्ष आर्थिक अनुदान देती है । 'हिन्दुस्तानी' नाम की शोध-पूर्ण त्रैमासिक पत्रिका अकादमी प्रकाशित करती है ।

इसके संगठन में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के हिन्दी-विभाग के प्रतिनिधि तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के भी प्रतिनिधि होते हैं । इसके अध्यक्ष और सचिव का निर्वाचन उत्तरप्रदेश सरकार स्वयं करती है ।

स्वतंत्रता के बाद हिन्दी भाषी प्रदेश की सरकारों ने ऐसी दूसरी संस्थाओं को भी जन्म दिया है जो हिन्दी को समृद्ध करने के लिए काम करती हैं । इनका परिचय आगे दिया जाता है—

२—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

११ अप्रैल १९४७ को बिहार राज्य की विधान सभा ने इस परिषद् की स्थापना का निश्चय किया था । परिषद् का मूल उद्देश्य साहित्य-निर्माण

और विद्वानों का सम्मान ही था पर विस्तार में उसके तीन भाग थे—भारतीय भाषाओं के साहित्य का संवर्धन, राष्ट्रभाषा और बिहार की राजभाषा हिन्दी में कला, विज्ञान तथा अन्य विषयों के उपयोगी एवं मौलिक ग्रन्थों का प्रकाशन, तथा बिहार की प्रमुख बोलियों का अनुशीलन ।

१६ जुलाई १९५० को श्री शिवपूजन सहाय इसके मंत्री नियुक्त हुए, तभी से वास्तविक रूप में इसके कार्य का आरम्भ हुआ । परिषद् का विधिवत् उद्घाटन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री माधव श्री हरि अरो ने ११ मार्च १९५१ को किया ।

परिषद् ने अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए प्रशंसनीय प्रयास किया है । इसने दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का काम करवाया है, विशिष्ट विद्वानों के भाषणों का आयोजन किया है और उन भाषणों को ग्रन्थ रूप में प्रकाशित किया है । भोजपुरी, मैथिली और मराठी भाषाओं के शब्द-कोश प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

परिषद् का प्रति वर्ष समारोह आयोजित होता है, इसी अवसर पर विद्वानों के भाषण भी कराये जाते हैं । 'परिषद् पत्रिका' नाम से इसका शोध-पूर्ण त्रैमासिक चिन्तित छह वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, जो 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' और 'सम्मेलन पत्रिका' के समकक्ष है ।

परिषद् के प्रकाशित ग्रन्थ हिन्दी के गौरव हैं । 'मध्य एशिया का इति-हास' 'दोहाकोश' 'यूरोपीय दर्शन' 'सार्थवाह' 'हर्षचरित-एक अध्ययन' 'कम्बन रामायण' 'काव्य मीमांसा' 'कथा सरित्सागर' 'ईश और चीनी'—जैसे मौलिक एवं अनुवाद, सम्पादन और अनुशीलन का मानदंड स्थापित करनेवाले ग्रन्थ इस परिषद् ने प्रकाशित किये हैं ।

३-हिन्दी-समिति उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार प्रति वर्ष ५० हजार से अधिक धनराशि हिन्दी के लेखकों को अखिल भारतीय स्तर पर उनकी मौलिक कृतियों के लिए पुरस्कार

मे देती है। इसके अतिरिक्त उसने राष्ट्रभाषा हिन्दी की समृद्धि के लिए डॉ० सम्पूर्णानन्द के मुख्यमंत्रित्व-काल में हिन्दी-समिति की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य हिन्दी में कला और विज्ञान के मौलिक ग्रन्थों तथा अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रन्थों के अनुवाद का प्रकाशन है। अब तक समिति ने लगभग ८० ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, जिनमें कोश, ज्योतिष और विज्ञान के भी उत्कृष्ट ग्रन्थ हैं। डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आज कल डॉ० दीनदयालु गुप्त अध्यक्ष हैं।

४-राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर

राजस्थान सरकार ने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना आजादी के बाद की है। अकादमी द्वारा प्रदेशीय स्तर पर हिन्दी-लेखकों को उनकी मौलिक कृतियों पर पुरस्कार दिया जाता है। विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान का आयोजन होता है। अकादमी हिन्दी में 'मधुमती' नामक साहित्यिक, सांस्कृतिक मासिक प्रकाशित करती है और उर्दू में 'नखलिस्तान' नाम की त्रैमासिक पत्रिका निकालती है। राजस्थान के लेखकों और विद्वानों का सहयोग इस अकादमी को प्राप्त है।

मध्यप्रदेश की शासन-साहित्य-परिषद् भी अखिल भारतीय एवं प्रदेशीय स्तर पर हिन्दी-लेखकों को उनकी मौलिक कृतियों पर पुरस्कार देती है। हरियाणा सरकार का भाषा-विभाग हिन्दी के दो पत्र 'सप्तसिन्धु' और 'जन-साहित्य' प्रकाशित करता है। हिन्दी के साहित्य-निर्माण की ओर प्रयत्नशील संस्थाओं में राजस्थानशोध-संस्थान जोधपुर, भारत सरकार की साहित्य अकादमी और हिन्दी साहित्य अकादमी कुरुक्षेत्र का भी नाम लिया जाना चाहिए।

इन सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है—

५-भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग (विश्वविद्यालय)

यह परिषद् समस्त के हिन्दी अध्यापकों का संगठन है

इस संगठन का आरम्भ सन् १९४३ में हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य हिन्दी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के अध्ययन एवं अनुसन्धान कार्य को विश्वविद्यालयीय स्तर पर अग्रसर करना है। अपने इस उद्देश्य को लेकर परिषद् ने कई प्रशंसनीय कार्य किये हैं।

इसके वार्षिक अधिवेशन विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित हुए हैं। इन अधिवेशनो में विचार-गोष्ठियो द्वारा परिषद् भाषा तथा साहित्य की अनेक समस्याओं का हल और नई योजनाओं का प्रारूप प्रस्तुत करती है। अनुसन्धान एवं पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में परिषद् का कार्य प्रशंसनीय है। 'हिन्दी-अनुशीलन' नाम से शोधपूर्ण त्रैमासिक पत्रिका परिषद् प्रकाशित करती है।

राष्ट्रभाषा के हितैषियों एवं गण्यमान्य विद्वानों का सहयोग सदैव परिषद् को मिलता रहा है।

अन्य रचनात्मक संस्थानों में राम वन, सतना और वीरेन्द्र केशव साहित्य-परिषद्, टीकमगढ़ (सन् १९३०) (मध्यप्रदेश) का भी नाम उल्लेखनीय है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी

जनसंख्या के विचार से हिन्दी विश्व की तीसरी भाषा है। उत्तरी चीनी और अंग्रेजी के बाद इसका स्थान है। अंग्रेजी का बहुत विस्तार अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के साथ हुआ है। मूलतः अंग्रेजी जितने लोगों की भाषा है उनकी संख्या हिन्दी-भाषियों और हिन्दी मम करने वालों से कम है। इस प्रकार चीनी भाषा के बाद दूसरा स्थान हिन्दी का होता है। चीनी भाषियों की संख्या ४४ करोड़ ४० लाख, हिन्दी-भाषियों की संख्या १९ करोड़ १५ लाख, रूसी भाषियों की संख्या १५ करोड़ ६० लाख है और अंग्रेजी भाषी २७ करोड़ ८० लाख है।

हिन्दी की लगभग २० उपभाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं। इस रूप में भारत की ४४ प्रतिशत जनसंख्या को हिन्दी मातृभाषा है। इस ४४ प्रतिशत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की गिनती की जायगी। भारत का आषा भाग इसे प्रचलित और व्यावहारिक भाषा के रूप में प्रयोग करता है।

हिन्दी की लिपि और उसके शब्दों तथा अर्थों का उच्चारण एवं बोध कुछ इतना वैज्ञानिक अर्थात् सहज है कि हिन्दी की लोकप्रियता अपने आप बढ़ी है। पहले अध्याय में हिन्दी की इस व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। हिन्दी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करने की बड़ी क्षमता है और आज हिन्दी में अनेक शब्द दूसरी भाषाओं के हैं। यह भारत देश के विशाल क्षेत्र की मातृभाषा है, जहाँ की यह मातृभाषा नहीं है, वहाँ भी यह आसानी से बोली और समझी जाती है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आज इसके माध्यम से हमारे कार्य-व्यवहार को जो सौविध्य प्राप्त है वह

कभी इतिहास में संस्कृत के माध्यम से प्राप्त सौविध्य से भी अधिक उत्कृष्ट है। हिन्दी में ही भारत के अतीत के इतिहास की लम्बी सांस्कृतिक परम्परा का बोध सुरक्षित है, जो अधिकांश में समाज को नई प्रगति देनेवाले सन्तों की वाणी में मुखर हुआ है। आज हिन्दी को समृद्ध करने के लिए कई क्षेत्रों में वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण भी अत्यन्त लगन से किया गया है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने पिछली शताब्दी में अटूट श्रम किया है वे किसी लोभ से प्रेरित नहीं थे, उनको किसी शासन ने प्रोत्साहन नहीं दिया था। और पिछले कुछ वर्षों में केवल उर्दू भाषा तथा फारसी लिपि को छोड़कर किसी भारतीय भाषा या उनकी लिपि ने हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को अपने अवरोध के रूप में नहीं स्वीकार किया है, आजादी के पूर्व अर्थात् जब तक शासन-तंत्र ने अंग्रेजी के प्रति अपना दुराग्रह नहीं शुरू किया तब तक सर्वत्र अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी को अपने घर की तरह सौहार्द मिलता रहा है। अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अच्छे लेखक पिछली अर्धशती में पैदा हुए हैं, आज भी हैं। विदेशों में भी हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन के प्रति लोग उन्मुख हैं। इस प्रकार पिछले अतीत, विगत की अर्धशती और आज के वर्तमान को जब हम देखते हैं तब कभी कोई भी हिन्दी की ऐसी दुर्बलता नहीं प्रकट होती जिससे यह मन्द स्वर से भी कहा जा सके कि हिन्दी अभी भारत की राष्ट्रभाषा के योग्य नहीं है परन्तु संविधान में इसे राष्ट्रभाषा (राज भाषा) स्वीकार करके भी केवल राष्ट्र-भक्त जनता को संतोष दिया गया है, हिन्दी उपेक्षित ही है।

सन् १९५० में राष्ट्र के समस्त व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग के लिए १५ वर्ष की अवधि दी गई थी। पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर वह अवधि फिर बढ़ गई और अभी अंग्रेजी बनी ही रहेगी, अंग्रेजी कब टलेगी इसके लिए कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। हिन्दी-भाषी प्रदेशीय सरकारों को जब पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद भाषा-और लिपि के व्यवहार का १९६४ में निश्चय करना पड़ा तब केवल बिहार और राजस्थान सरकार ने ही निर्भयता के साथ हिन्दी को सर्वत्र राजकाज में व्यवहृत करने के लिए अपने निश्चय की

घोषणा की। वैसे मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी यह निश्चय किया है। किन्तु हिन्दी की जन्म-भूमि उत्तरप्रदेश की विधान सभा में हिन्दी के प्रश्न को लेकर उस समय जो हंगामा हुआ और हिन्दी के समर्थक विरोधी-दलों को जो उत्तर मिला, वह सब कुछ ऐसा था जो राष्ट्रीय दृष्टि से लज्जाजनक था। इन अनेक प्रयत्नों के बावजूद कहना यही पड़ता है कि शासन के व्यवहार में हिन्दी अब भी उपोक्षित है। इतने बड़े राष्ट्र में, जिसका पुराना इतिहास हमें कम से कम पाँच हजार वर्षों की जानकारी देता है, जिसकी एक लम्बी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परम्परा है, उसकी अपनी भाषा के रूप में हिन्दी पूरे देश में समझी-जानी जाती है और आज से नहीं लगभग सात सौ वर्षों से हिन्दी की यह व्यापकता अग्रसर होती रही है, किन्तु हमारे स्वतंत्र देश के शासन में अंग्रेजी का व्यवहार होता है, अंग्रेजी जो हम पराधीन करने वाले विजेताओं की भाषा थी और इस रूप में ही आज भी जिसकी छाप जनता पर है। विश्व के इतिहास में और आज के वर्तमान में यह अनहोनी घटना है।

दिसम्बर १९२७ में महात्मा गाँधी भरिया की एक विराट सभा में पधारे थे, कोयले की खानों के मजदूरों की ओर से उनको एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया था, वह अंग्रेजी में था, यह जान कर गाँधी जी ने उसे सभा में पढ़ने नहीं दिया। २० जनवरी १९२८ के 'यंग इंडिया' में उनका वक्तव्य प्रकाशित हुआ—

“उन हजार लोगों में जो सभा में आये थे, मुश्किल से शायद पचास अंग्रेजी जानते होंगे। भारी बहुसंख्या उनको थी जो हिन्दी भाषानी से समझ सकते थे, और एक बड़ी संख्या उनकी थी जो बंगाली जानते थे। उक्त संगठन के अगुआ बंगाली व्यक्ति थे। यदि अंग्रेजी का प्रयोग मेरे लिए किया गया था तो मैं कहूँगा कि वह व्यर्थ था। वे अभिनन्दन-पत्र बंगला में लिख सकते थे और मुझे उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद दे सकते थे। परन्तु यदि अंग्रेजी अभिनन्दन-पत्र उस बड़ी सभा पर थोपा जाता तो नेताओं का अनादर ही होता। मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब श्रोतमग्न

ऐसी सभाएँ छोड़कर चले जायेंगे जहाँ सभा की कार्यवाही उस भाषा में की जाती है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझ सकते ।”

गाँधी जी का अन्तिम वाक्य ही राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा की कुंजी है । जनतंत्र की सरकार में यदि जनता की ही भाषा का व्यवहार राजकाज में नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी अथवा कमजोरी जनता पर ही थोपी जायगी, जनता उनको शासन सौपती ही क्यों है जो उसकी भाषा की उपेक्षा करते हैं ? जनता की भाषा कुछ है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं, क्या यही जनतंत्र का प्रर्थ है ? इसका अर्थ है जनता नहीं है । गाँधी ने अपना अभिनन्दन-पत्र अंग्रेजी में होने के कारण नहीं पढ़ने दिया था, आज राज्यपाल और राष्ट्रपति के भाषण अंग्रेजी में होते हैं, यह अन्तर जनता की निद्रा का प्रतीक है ।

बहुत सत्य बात है कि आज शासनतंत्र और जनता में दूरी पैदा हो गई है और जब शासनतंत्र के निर्माण में हाथ जनता का है तब भाषा की यह दूरी जनता के चाहने पर ही दूर होगी । इस दूरी के लिए कोई कारण नहीं है । हमारे हिन्दी के समर्थक नेताओं—डा० सम्पूर्णानन्द, डा० राम-मनोहर लोहिया, डा० रघुवीर, डा० लक्ष्मीनारायण ‘सुधांशु’ आदि ने अपने वक्तव्यों में भली भाँति यह स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दी की उपेक्षा निष्कारण हो रही है । पिछली शती में देश के जो गण्यमान्य नेता हुए हैं, उनमें जो अहिन्दी भाषी रहे हैं उन्होंने भी मुक्तकठ से हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने का समर्थन किया है । नीचे ऐसे कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं—

बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय

अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भी भावना हो, पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिन्दी के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता ।
 × × जो सज्जन हिन्दी भाषा द्वारा भारत में एकता पैदा करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारत-बन्धु हैं ।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

एक विदेशी भाषा के लिए जैसी मजदूरी भारत में है वैसी कही नहीं है। जिस शिक्षा को प्राप्त करने में हमें बीस-पच्चीस वर्ष व्यय करने पड़ते हैं वह देश की भाषाओं के माध्यम से सात-आठ वर्ष में प्राप्त की जा सकती है। × × × × हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम कोई भी लिपि अपनाएँ, यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि वह लिपि सुगमता और प्रवाह के साथ लिखी जा सके और देखने में सुन्दर हो। उसमें विभिन्न अर्थ तथा द्रविड भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता भी होना चाहिए, मेरे विचार में देवनागरी ही प्रधानतः ऐसी भाषा है। (१९०५)

महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी

मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, पूरी आजादी तो हमें अंग्रेजी भाषा की गुलामी छोड़ने पर ही मिलेगी। (१९१८)

महाराज सयाजीराव गायकवाड़

यदि हिन्दी को भारतवर्ष के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाय तब हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करना चाहिए। (१९३३)

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस

कुछ लोगों का विचार है कि बँगला राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि इसमें उच्च काटि का साहित्य है। हिन्दी में उच्च साहित्य है अथवा नहीं, यह विवाद-ग्रस्त विषय उठाना व्यर्थ है। हिन्दी व्यापक रूप से भारत में बोली जाती है, और इसमें ग्रहण शक्ति है तथा यह सरल है। (१९३८)

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ

यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सब से बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा जी ने हम लोगों से की है अर्थात् हिन्दी । (१९३८)

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

हिन्दी के द्वारा उत्तर और दक्षिण के कार्य में तथा भाव-विनिमय में सुविधा होगी । यह धारणा बिल्कुल भ्रमात्मक है कि उर्दू की उत्पत्ति इस्लाम में हुई है । उर्दू को इस्लाम और हिन्दी को हिन्दू भाषा मानना बिल्कुल गलत है । जिस भी लिपि में लिखी जाय, भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है, इसके नाम से भी ऐसा ही बोध होता है । (१९३८)

श्री श्रीनिवास शास्त्री

यदि मुझे पुराने बादशाहों के अधिकार काम में लाने के लिए दिये जायें तो मैं एक काम यही करूँ कि देश में एक भाषा और एक लिपि का व्यवहार हो । (१९३४)

श्रीमती अम्बु जम्बाल

मेरे दिल में आशा बँध गई है कि हिन्दी के द्वारा ही भिन्न-भिन्न प्रांत एक सूत्र में पिरोये जा सकते हैं और उस माध्यम के द्वारा ही विभिन्न भाषा-भाषियों के हृदय में ऐक्य की भावना जाग्रत हो सकती है । (१९३३)

श्री जोश मलीहाबादी

हिन्दी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है । हिन्दी के सरकारी जवान बन

जाने को हम मुसलमानों के लिए क्यों न्यायमत्त समझ रहे हैं ? इसलिए समझ रहे हैं कि देवनागरी लिखाई मुल्कभर में आम हो जायगी । (१६४७)

श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर

हिन्दी भारतवर्ष की सामान्य भाषा होनी चाहिए ।

डॉ० रामकृष्ण भण्डारकर

भिन्न प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनाने का सम्मान हिन्दी को ही मिलना चाहिए ।

श्री फजल अली

हिन्दी भारत की स्वाभाविक भाषा है । हिन्दी को न सिर्फ़ राष्ट्रभाषा होने का अधिकार है बल्कि यदि उसके प्रचार और विकास की ओर उचित ध्यान दिया गया तो वह भी समर्थ हो सकता है जब वह समस्त एशिया की भाषा बने ।

श्री खवाजा हुसैन निजामी

बंगला, बर्मी, गुजराती और मरहठी वगैरह सब जवानों से ज्यादा रिवाज हिन्दी या नागरी जवान का है ।

श्री हरिकृष्ण महताव

मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे इस समय इस सम्बन्ध में कैसा ही वाद-विवाद और विरोध क्यों न चल रहा हो, एक न एक दिन भारतवर्ष में राष्ट्रीयता अपने आप को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त करेगी और देश के लिए एक राजभाषा की मांग होगी और वह राजभाषा हिन्दी के अनिरिक्त और कोई भाषा नहीं हो सकती । इस स्थिति के आने तक हिन्दी के कार्यकर्ताओं को धैर्यपूर्वक कार्य करना पड़ेगा ।

विदेशों में हिन्दी

भारत में बाहर हिन्दी का प्रचार और उसका सम्मान दो क्षेत्रों में हो रहा है। एक क्षेत्र तो वह है जहाँ हमारी भारतभूमि के निवासी बसे हुए हैं, जैसे—बर्मा, लंका, वेस्टइंडोज, दक्षिण अफ्रीका और मारीशस। दूसरा क्षेत्र उन उन्नत राष्ट्रों का है जो ४५ करोड़ की आबादीवाले इस विशाल देश की सर्वाधिक जन-संख्या में बोली जानेवाली भाषा और उसके साहित्य के प्रति स्वतः जिज्ञासु हैं, इन राष्ट्रों में विशेषरूप से सोवियत रूस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, ग्रेटब्रिटेन, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हिन्दी और उसके साहित्य के प्रचार-प्रसार, अनुवाद एवं अनुशासन का अच्छा काम हुआ है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं का एक केन्द्र हिन्दी प्रचारिणी सभा लोंगदोलाई-मारीशस में है। इसके व्यवस्थापक हैं श्री एस्० एम्० भगत। सम्मेलन का दूसरा केन्द्र गाँधी हिन्दी हाई स्कूल जियावडी ब्रह्मा में है।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं के कई केन्द्र विदेश में हैं। दक्षिण अफ्रीका में विशेषरूप से समिति के तत्वावधान में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम हुआ है। इसका कारण यह है कि वहाँ हमारे भारतीय सन् १८६० से जाकर बसे हुए हैं। अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी भाग में समिति के २५ से ऊपर परीक्षा-केन्द्र हैं। पश्चिमी अफ्रीका में एक केन्द्र है। दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी सीखने के लिए नियमित रूप के राजि-पाठशालाएँ चलायी जाती हैं। वर्धा-समिति इस कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका में नियमित रूप से

वार्षिक अनुदान भी दिया करतो है। वहाँ हिन्दी सीखनेवाले तीन हजार से ऊपर विद्यार्थी हैं। दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी के पहले प्रचारक स्वामी शंकरानन्द जा हैं, उनके बाद स्वामी भवानीदयाल सत्यासी ने यह कार्य किया। सन् १९४७ में नरदेव जी वेदालंकार ने यहाँ पहुँचकर हिन्दी-प्रचार कार्य को विशेष बल प्रदान किया। १९४८ में उन्होंने एक हिन्दो-सम्मेलन बुलाया और उसमें निश्चय करके हिन्दी-शिक्षा-संघ नातान की स्थापना की, पुनः इसके द्वारा सभी जगह रात्रि-पाठशालाओं आदि के आयोजन किये गये।

अफ्रीका का हिन्दी-प्रचार एक तरह से भारतीयों से ही सम्बन्धित है। यही बात मारीशस के लिए कही जा सकती है। मारीशस में हिन्दी-प्रचारिणी मन्त्रा प्रचार-कार्य में संलग्न है। मारीशस छोटा-सा द्वीप है, इसकी जनसंख्या पाँच लाख है, जिसमें तीन लाख भारतीय हैं। सन् १९१३ में स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी ने यहाँ हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्भ किया। मारीशस में वर्धा-समिति और सम्मेलन दोनों के परीक्षा-केन्द्र चलते हैं। मारीशस की तरह भारतीयों का दूसरा उपनिवेश फिजी है जहाँ हिन्दी का व्यापक प्रचार है। भारत सरकार ने मारीशस, फिजी, वेस्टइंडीज, ब्रिटिश गयाना और जमैका के भारतीयों में हिन्दी-प्रचार के लिए सहायताएँ दी हैं। अन्य जिन देशों में वर्धा-समिति के केन्द्र हैं वे ये हैं—दक्षिण रोडेशिया, मूदान, इरीट्रिया।

ग्रेट ब्रिटेन में हिन्दी का पठन-पाठन और हिन्दी-पुस्तकों का प्रकाशन उन्नीसवीं शती के आरम्भ से ही पाया जाता है। जैसे सन् १७७३ में भी लन्दन के श्री फर्ग्युसन ने हिन्दी के दो शब्दकोश रोमन लिपि में प्रकाशित किये थे। आगे चल कर हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन और अनुशीलन में अंग्रेजों ने बड़ी रुचि दिखाई है। कई अंग्रेज हिन्दी के अच्छे विद्वान् हुए हैं और आज भी हैं। फोर्टविलियम कालेज के हिन्दुस्तानी अध्यापक गिलक्रिस्ट और हिन्दी-इतिहास के लेखक सर जार्ज ग्रियर्सन का नाम तो प्रसिद्ध ही है। अंग्रेजों का यह हिन्दी-प्रेम भारत के अंग्रेजी राज्य का उपनिवेश होने के कारण था।

सोवियत रूस में हिन्दी-प्रचार का आरम्भ अक्टूबर सन् १९१७ से सम्पन्न चाहिए जब राष्ट्रेनेता लेनिन के आदेश से महान् साहित्यकार गोर्की के नेतृत्व में वहाँ पौरस्त्य विभाग की स्थापना की गई, इसमें डण्डोर्लाजी एक महत्त्वपूर्ण विभाग है। उस स्थापना-काल से लेकर अब तक भारतीय-भाषाओं के लेखकों की ३०० से ऊपर पुस्तकें रूस की ३२ भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित की जा चुकी हैं। पन्द्रह करोड़ से ऊपर उनकी प्रतियाँ छप चुकी हैं। इन अनुवादों में तुलसीदास का रामचरितमानस भी है, जिसका अनुवाद श्री बेरेनिकोव ने किया है। अन्य हिन्दी लेखकों में, जिनकी पुस्तकों का अनुवाद रूस की भाषाओं में हुआ है, प्रमुख है—कामताप्रसाद गुरु (हिन्दी व्याकरण) किशोरीदास वाजपेयी (हिन्दी शब्दानुशासन), प्रेमचन्द्र (१६ पुस्तकें), सुमित्रानन्दन पन्त सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', यगपाल, डा० रामकुमार वर्मा, मौथिलीशरण गुप्त। रूस के साहित्यकारों का प्रतिनिधि मण्डल हमारे यहाँ आ चुका है और हिन्दी-लेखकों के प्रतिनिधि-मण्डल भी रूस गये हैं। रूस में हिन्दी का अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या हजार की संख्या में है। रूसी-साहित्य की अनेक पुस्तकों के सुत्रांश हिन्दी-अनुवाद वहाँ से प्रकाशित हुए हैं।

इन देशों के अतिरिक्त अन्य जिन देशों में हिन्दी का विधिवत् अध्ययन हो रहा है वे देश हैं—पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन। जापान की तीन युनिवर्सिटियों में हिन्दी-अध्ययन की व्यवस्था है और इसके लिए हिन्दी-लेखक रखे गये हैं। हिन्दी के कई ग्रन्थों और रचनाओं का जापानी भाषा में अनुवाद हो चुका है। इटली, पोलैण्ड, आस्ट्रेलिया, विएतनाम में भी हिन्दी-अध्ययन की ओर रुचि है। अपने पड़ोसी देश और टापू—नेपाल, ब्रह्मा, सिक्किम, भूटान, लंका और अन्दमान-निकोबार की तो कोई बात नहीं है, यहाँ हिन्दी पढ़ी ही जाती है। लका विश्वविद्यालय में हिन्दी-अध्ययन की व्यवस्था है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ अध्यक्ष पद पर काम किया है और इस समय श्री आनन्द कौसल्यायन कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार हिन्दी भाषा आज विश्व के एक बड़े भाग में पढ़ी-लिखी जाती है और निरन्तर व्यापक होती जा रही है। उसे आवश्यकता है उसके घर में ही उन भारतीयों के हिन्दी-प्रेम की, जो अपने अंग्रेजी-प्रेम में उसे राजकाज में जगह नहीं देना चाहते हैं और जबर्दस्ती भारतीय-भाषियों के ऊपर अंग्रेजी का बोझ लाद रहे हैं जब कि हिन्दी भाषा समूचे भारत में पूर्ण लोक-प्रिय है।

परिशिष्ट—१

नागरी प्रचारिणी सभा काशी के सभापति

वर्ष	सभापति
संवत् १९५० वि०	श्री राधाकृष्णदास
१९५१	" "
१९५२-५८	पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र
१९५९-६६	म० म० सुधाकर द्विवेदी
१९६७	प० आदित्यराम भट्टाचार्य
१९६८	म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
१९६९	पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या
	पं० श्यामविहारी मिश्र
१९७०-७२	पं० श्यामविहारी मिश्र
१९७३-७४	बाबू श्यामसुन्दर दास
१९७५	बाबू श्याम सुन्दर दास
	श्री गौरी शंकर प्रसाद
१९७६-७८	म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा
१९७९-८०	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
१९८१	डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल
१९८२-८४	श्री हीरालाल
१९८५-८७	डॉ० श्यामसुन्दर दास
१९८८-९०	पं० रामनारायण मिश्र
१९९१-९२	डॉ० श्यामसुन्दर दास
१९९३	श्री पंड्या

परिशिष्ट—१

१०५

१९९४	डॉ० इराम सुन्दर दास
	प० रामनाथराय मिश्र
१९९५-९६	प० रामनारायण मिश्र
१९९७	प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल
	ठा० शिवकुमार सिंह
१९९८	श्री कमलाकर द्विवेदी
१९९९-२००१	डॉ० सम्पूर्णानन्द
२००२-०४	श्री मैथिलीशरण गुप्त
२००४	डॉ० सम्पूर्णानन्द
२००६	राय कृष्णदास
२००७-००८	प्राचार्य नरेन्द्र देव
२००९	डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
२०१०-१२	डॉ० भ्रमरनाथ झा
२०१३-१७	प० गोविन्दवल्लभ पन्त (स्वराष्ट्रमंत्री)
२०१८-१९	डॉ० सम्पूर्णानन्द
२०२०-२३	प० कमलापति त्रिपाठी

परिशिष्ट-२

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति और अधिवेशन

सभापति	वर्ष	अधिवेशन
१. महामना पं० मदनमोहन मालवीय	संवत् १९६७ वि०	काशी
२. पं० गोविन्दनारायण मिश्र	१९६८	प्रयाग
३. उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'	१९६९	कलकत्ता
४. महात्मा मुचीराम (स्वामी श्रद्धानन्द)	१९७०	भागलपुर
५. पं० श्रीधर पाठक	१९७१	लखनऊ
६. रायबहादुर बाबू श्यामशुन्दर दास बी० ए०	१९७२	प्रयाग
७. महामहोपाध्याय पंडित रामा- वतार गर्मा	१९७३	जबलपुर
८. कर्मवीर मोहनदास कर्मचंद गाँधी	१९७४	इन्दौर
९. महामना पं० मदनमोहन मालवीय	१९७५	बम्बई
१०. रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल	१९७६	पटना
११. डॉ० भगवानदास एम्० ए०, डी० लिट्०	१९७७	कलकत्ता
१२. पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी एम्० आर्० ए० एस्०	१९७८	लाहौर
१३. श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन एम्० ए०, एल्-एल्० बी०	१९७९	कानपुर
१४. पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	१९८०	दिल्ली
१५. पं० माधवराय सप्रे	१९८१	देहरादून

१६. पं० अमृतलाल चक्रवर्ती	भवत १९८२ वि० वृन्दावन
१७. म० म० रा० व० पं० गौरीशंकर	१९८३ भरतपुर
ह्रीराचन्द ओझा	
१८. पं० पद्मसिंह शर्मा	१९८५ मुजफ्फरपुर
१९. श्री गरीशशंकर विद्यार्थी	१९८६ गोरखपुर
२०. बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर श्री० ए०	१९८७ कलकत्ता
२१. पं० किशोरीलाल गोस्वामी	१९८८ भाँसी
२२. रायगजा डॉ० श्यामविहारी मिश्र	१९८९ ग्वालियर
एम० ए०	
२३. महाराज सर सगार्जाराव गायकवाड	१९९० दिल्ली
(बडौदा)	
२४. महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गाँधी	१९९२ इन्दौर
२५. डॉ० राजेन्द्रप्रसाद	१९९३ नागपुर
२६. सेठ जमनालाल वजाज	१९९४ मद्रास
२७. पं० बाबूराव विष्णु पराडकर	१९९५ शिमला
२८. पं० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी	१९९६ काशी
२९. श्री सम्पूर्णानन्द	१९९७ पूना
३०. डॉ० अमरनाथ भा	१९९८ अबोहर
३१. प० माखनलाल चतुर्वेदी	२००० हरिद्वार
३२. गोस्वामी गरीशदत्त	२००१ जयपुर
३३. श्री कन्हैयालाल भार्गवकलाल मुंजी	२००२ उदयपुर
३४. श्री विद्योगीहरि	२००३ कराँची
३५. महापण्डित राहुल साकृत्यायन	२००४ बम्बई
३६. सेठ गोविन्ददास	२००५ भेरठ
३७. आचार्य चन्द्रबली पाण्डे	२००६ हैदराबाद
३८. श्री जयचन्द्र विशालंकार	२००७ कोटा

परिशिष्ट-३

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के पदवीदान—समारोहों के

दीक्षान्त भाषण कर्ता—

मनु १९३१ ई०	आचार्य काका कालेलकर
१९३२	प्रो० मुहम्मद आगा शुस्तरी
१९३३	पं० रामनरेश त्रिपाठी
१९३४	बाबू प्रेमचन्द
१९३५	पंडित सुन्दरलाल
१९३६	बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन
१९३७	जनाब याकूब हसन सेठ
१९३८	श्रीमती सरोजिनी नायडू
१९३९	श्री बाल गंगाधर खरे
१९४०	डॉ० पट्टाभि सीता रामैया
१९४१	आचार्य विनोबा भावे
१९४२, ४३	सैय्यद अब्दुल्ला बरेलवी
१९४६	राजकुमारी अमृत कौर
१९४८	डॉ० जाकिर हुसैन
१९४९	आचार्य विनोबा भावे
१९५०	श्री आर्० आर्० दिवाकर
१९५२	श्री श्रीप्रकाश
१९५३	श्री ए० जी० रामचन्द्र राव
१९५४	श्री बी० रामकृष्ण राव
१९५६ (जनवरी)	श्री एम्० सुन्दर ऐय्यर
१९५६ (अगस्त)	डॉ० राजेन्द्रप्रसाद
१९५७	श्री जगजीवन राय
१९५८	डॉ० हरिकृष्ण महताब
१९५९	श्री सदाशिव कानोजी पाटिल
१९६०	डॉ० बी० गोपाल रेड्डी

परिशिष्ट-४

अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के अध्यक्ष—

वर्ष	स्थान	सम्मेलन	अध्यक्ष
सन् १९४९ ई०	वर्धा	एहला	सेठ गोविन्ददास
१९५०	अहमदाबाद	दूसरा	मुनि जितांजय जी
१९५१	पूना	तीसरा	श्री वियोगीहरि
१९५२	बम्बई	चाथा	श्री कर्दयालाल मुशी
१९५३	नागपुर	पाँचवा	श्री न० वि० गाडगिल
१९५४	पुरी	छठा	डॉ० बालकृष्ण वि० केसकर
१९५६	जयपुर	सातवा	सेठ गोविन्ददास
१९५८	भोपाल	आठवा	डॉ० के० एल० श्रीमाली
१९५९	नई दिल्ली	नवाँ	श्री अनन्तशयनम् अयंगर
१९६१	तिनसुकिया	दसवा	डॉ० हरिकृष्ण महताव
१९६२	वर्धा	ग्यारहवाँ	(राष्ट्रपति) डॉ० राजेन्द्रप्रसाद
१९६६	औरंगाबाद	बारहवाँ	श्री यशवन्तराव चव्हाण

परिशिष्ट-५

मंगलाप्रसाद पारितोषिक-प्राप्त लेखक (हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग)

लेखक	ग्रन्थ	वर्ष
१. श्री पद्ममित्र वर्मा	विद्वारी गतसई	संवत् १९७६ वि०
२. म० म० गोरीशंकर हीराचन्द्र श्रीभक्त	प्राचीन लिपि-माला	१९८१
३. प्रो० सुधाकर	मनोविज्ञान	१९८२
४. श्री त्रिलोकीनाथ वर्मा	हमारे शरीर की रचना	१९८३
५. ,, वियोगो हरि	वीर सतसई	१९८४-८५
६. प्रो० सत्यकेतु	मौर्य-साम्राज्य का इतिहास	१९८६
७. श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय	आस्तिकवाद	१९८७
८. डॉ० गोरखप्रसाद	फोटोग्राफी की शिक्षा	१९८८
९. डॉ० मुकुन्दस्वरूप	स्वास्थ्य विज्ञान	१९८९
१०. श्री जयचन्द्र विद्यालंकार	भारतीय इतिहास की रूपरेखा	१९९०
११. ,, चन्द्रावती लखनपाल	शिक्षा-मनोविज्ञान	१९९१
१२. ,, रामदास गाँड़	विज्ञान-हस्तामलक	१९९२
१३. ,, अयोध्यासिंह उपाध्याय	प्रियप्रवास	१९९३
१४. ,, मैथिलीशरण गुप्त	साकेत	१९९३
१५. ,, जयशंकर प्रसाद	कामायनी	१९९४
१६. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	चिन्तामणि	१९९५
१७. श्री वामदेव	गुप्त का इतिहास	१९९६

१८. डॉ० सम्पूर्णानन्द	समाजवाद	संवत् १९९७ वि०
१९. श्री बलदेव उपाध्याय	भारतीय दर्शन	१९९८
२०. " महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	सूर्य सिद्धान्त का विज्ञान- भाष्य	१९९९
२१. " शंकरलाल गुप्त	क्षयरोग	२०००
२२. श्रीमती सहादेवी वर्मा	रश्मि, नीरजा, आधुनिक कवि	२००१
२३. डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी	कवीर	२००२
२४. डा० रघुवीर सिंह	मालवा में युगान्तर	२००३
२५. श्री कमलापति त्रिपाठी	ब्राह्म और मानवता	२००४
२६. डॉ० सम्पूर्णानन्द	चिद्विलाम	२००५
२७. श्रीमती चन्द्रावती राधारमण	मन्तुलित गोंपालन	२००७
२८. डॉ० दीनदयालु गुप्त	अष्टछाप और वल्गम- संप्रदाय	२००६
२९. डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल	हर्षचरित—एक सांस्कृतिक अध्ययन	२०१०
३०. श्री सत्यजित सिद्धातालंकार	समाजशास्त्र के मूल तत्त्व	२०११
३१. श्री उदयवीर शास्त्री	सांख्यदर्शन का इतिहास	२०१२
३२. प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा	ईश और चीनी	२०१४

परिशिष्ट-६

महात्मा गाँधी पुरस्कार-प्राप्तकर्ता अहिन्दी-भाषी हिन्दी-लेखक
(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा)

लेखक	वर्ष
१. आचार्य क्षितिमोहन सेन	सन् १९५१ ई०
२. महर्षि श्रीपाद दामोदर मानवलेकार	१९५२
३. स्व० बाबुराव विष्णु पराडकर	१९५३
४. आचार्य विनोबा भावे	१९५५
५. प्रज्ञाचक्षु प० सुखलाल सप्रेमी	१९५६
६. प० सन्तराम बी० ए०	१९५८
७. श्री काका साहेब कालेलकर	१९५९
८. श्री अनन्तगोपाल शेवडे	१९६१
९. स्व० डॉ० रागेयराधव	१९६६



भारती परिषद् प्रयाग

[अखिल भारतीय साम्प्रतिक मस्थान]

- प्रतिष्ठापक** महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय ।
- स्थापना** संवत् १९९४, मन् १९३७ ।
- उद्देश्य** भारतीय समाज को शिक्षित और उदात्त बनाने के लिए बौद्धिक एवं रचनात्मक कार्यो द्वारा भारत-भारती की प्रतिष्ठा बढाना ।
- माध्यम** भारती शोध मस्थान, भारती विद्यासंस्थान, भारती संग्रहालय, भारती परीक्षाएँ
- शाखाएँ** • दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, कश्मीर, बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश ।
- अध्यक्ष** : पण्डित मीताराम चतुर्वेदी, साहित्याचार्य, एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत, पालि, प्रत्न भारतीय इतिहास तथा संस्कृति) बी० टी०, एल० एल० बी० ।
- महामन्त्री** • श्रीधर शास्त्री, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न
- कार्यालय** बहादुरगज, इलाहाबाद-३